

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 28 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(9)60
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(9)62

विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(9)69
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— कैथल क्षेत्र के बरौट के किसानों से अत्याधिक बिजली प्रभार वसूल करने संबंधी	(9)69
वक्तव्य— (i) सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (ii) कृषि राज्य मंत्री द्वारा जिला भिवानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुन्डी से चने की फसल के क्षतिग्रस्त होने संबंधी	(9)69 (9)71
वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)74
बैठक का समय बढ़ाना	(9)124
वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)124
बैठक का समय बढ़ाना	(9)130
वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)131

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Construction of new Bridge Over Zahar Nallah in Faridabad District

***393. Shri Yogesh Chand Sharma:** Will the Minister for P.W.D (Building and Roads) be pleased to state whether there is any proposal to construct any new Bridge over Zahar Nallah to connect Khadar Villages in Faridabad District; if so, the details thereof together with the time by which the said proposal is likely to materialize?

लोक निर्माण मंत्री (श्री औम प्रकाश भारद्वाज): जिला फरीदाबाद में जहर नाले के ऊपर पुल बनाने के लिए धनराशि जुटाने का मामला विचाराधीन है। प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत 8.25 करोड़ रुपए है। इस स्टेज पर प्रोजैक्ट के कार्यान्वित होने बारे कोई समय अवधि निर्धारित नहीं कह जा सकती क्योंकि यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर होगी।

श्री योगे । चन्द्र भार्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहले साल काम भुरु किया जाएगा तब इस पुल पर कितने लाख लागत आएगी?

श्री औम प्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, जब तक इस पुल की मंजूरी नहीं दी जाती तब तक अनुमान के बारे में नहीं बताया जा सकता।

श्री योगे । चन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, यह क्षेत्र बीस हजार की आबादी वाला है। बरसात के दिनों में इस क्षेत्र का बाकी हरियाणा से संबंध बिल्कुल टूट जाता है और इन दिनों में इन लोगों को जीवनोपयोगी कोई चीज मुहैया नहीं होती। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सरकार की ओर से कोई ऐकान क्यों नहीं लिया गया?

श्री औम प्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि खादर के बारह गांव हैं जिनकी आबादी लगभग आठ हजार है। यह बात भी ठीक है कि इन लोगों को पुल न बनने से काफी दिक्कत रहती है। लेकिन फिर भी वहां पर मोहना के नजदीक एक कित्तियों का पुल बना दिया जाता है और यह पुल 15 नवम्बर से 15 जून तक चालू रहता है। जब भारी बाढ़ आ जाती है तब कित्तियों से लोगों को सूविधा पहुंचाई जाती है।

श्री मांगे राम: स्पीकर साहब, रोहतक जिले के अन्दर पिछली सरकार ने कोई भी पुल नहीं बनाया। 1977-78 में चौधरी

देवी लाल की सरकार ने बहादुरगढ से बराही तक सडक बनाई थी लेकिन उस सडक पर पुल नहीं है। क्या मंत्री महोदय वहां पर पुल बनाने की कृपा करेंगे।

श्री औम प्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, चौधरी मांगे राम ने जिस पुल के बारे में जिक्र किया है वह इस साल चालू करवा देंगे।

श्री योगे । चन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो खादर के एरिया में पुल बनाने की बात थी लेकिन चौधरी मांगे राम इसे रोहतक ले गए।

श्री औम प्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, चौधरी मांगे राम ने जिस पुल की बात की है उसकी लागत तो लाखों में है लेकिन जिस पुल का योगे । चन्द्र भार्मा जिक्र कर रहे हैं उसकी लागत आठ करोड है। जब हमारे पास ऐडीक्वेट फण्डज हो जाएंगे तो वहां पर पुल बना देंगे।

श्री आत्मा राम गोदारा: स्पीकर साहब, बहुत से रोडज ऐसे हैं जहां पर मैटीरियल खरीद कर डाला हुआ है लेकिन उनको भुरु नहीं किया गया है। ऐसी ही एक रोड राजली से बेबलपुर है। क्या मंत्री महोदय इस बजट में ऐसी रोडज को प्रायोरिटी देकर बनाएंगे?

श्री अध्यक्ष: गोदारा जी, यह सवाल पुल के बारे में है, रोडज के बारे में नहीं है।

Appointments made in HUDA

*307. Sh. Hira Nand Arya, Shri P.K. Chaudhary:

Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons appointed by HUDA during the period from 1986-87 to 1987-88 (upto 29-2-1988) on daily, adhoc and regular basis togetherwith their complete address and mode of their appointment?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

श्रेणी	1986-87	1987-88 (29-2-88 तक)
दैनिक वेतन पर		इन आंकड़ो को संकलन से प्राप्त होने वाला लाभ, उनके इकट्ठे करने में लगने वाले समय एवं श्रम के अनुरूप नहीं है।
तदर्थ	61	244
नियमित	69	51

कर्मचारियों के पूरे पते तथा उनकी नियुक्ति की विधि को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध ए, बी, सी एवं डी के रूप में अलग से सदन के पटल पर रखा जाता है।

क्रमांक	नाम व पता	नियुक्ति की विधि
	कनिष्ठ अभियन्ता	
	सर्वश्री / श्रीमती	
1	राम पाल यादव पुत्र राम कुमार गांव व डा0 मोहिनदुदीन, जिला महेन्द्रगढ	रोजगार विभाग के माध्यम से
2	केवल कृष्ण पुत्र कुरडा राम, नजदीक विक्रमादित्य अस्पताल, राम नगर कालोती, मण्डी डबवाली।	—सम—
3	जगदीश कुमार पुत्र धर्मचन्द 38/8, राम नगर, करनाल	—सम—
4	बलबीर सिंह पुत्र किरपा राम, गांव घराडसी, डा0 बारना, तह0 कैथल (कुरुक्षेत्र)	—सम—
5	विनोद कुमार पुत्र मदन लाल, गांव व डा0 कुम्भा, तह0 हांसी, जिला हिसार।	—सम—
6	रमेश कुमार शर्मा पुत्र औम प्रकाश शर्मा, गांव डेरा, डा0 हमीदपूर तह0 नारायणगढ	—सम—

	(अम्बाला)	
7	याम सुन्दर पुत्र बनवारी लाल, गली पटवारीन नजदीक डी०डी०ए० कार्यालय, डी० एस० पी० रोड, फतेहाबाद।	—सम—
8	सुभाष चन्द्र पुत्र मनोहर लाल, गांव लन्धारी, तह० व जिला हिसार	—सम—
9	रामवीर सिंह पुत्र दरिया सिंह, गांव व डा० मिर्चपुर, तह० हांसी, जिला हिसार।	—सम—
10	पन्नु राम पुत्र वधवा राम, गांव बुर्ज, डा० चिमन, तह० रतिया, जिला हिसार।	—सम—
11	ललीत कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण, प्लाट न 3, स्कूल कम केनाल एरिया, नीलोखेडी, करनाल।	—सम—
12	सतीश शर्मा पुत्र मनोहर लाल सेवक सभा हस्पताल, सिरसा रोड, हिसार	—सम—
	कनिष्ठ अभियन्ता (बागवानी)	
13	जोगी राम पुत्र मिरची राम गांव व डा० पुटठी तह० हांसी, जिला हिसार	—सम—

14	महेन्द्र सिंह पुत्र भगवान राम गांव व डा0 माण्डी कलां, तह0 लोहारु, भिवानी	—सम—
15	हर लाल पुत्र सुख राम गांव बिज्जन, डा0 रामघाट, जिला बुलन्दशहर, यू पी	—सम—
16	विरेन्द्र सिंह पुत्र चौखा लाल मकान नं.515, काली वादी मार्ग, नई दिल्ली	—सम—
	सहायक प्रारूपकार	
17	हरबंस लाल पुत्र जवाहर लाल आर्य समाज मौहल्ला प्रेम मोहल्ला, गुडगांव	—सम—
	लेखा सहायक	
18	आनन्द प्रकाश पुत्र जय नारायण 20 / 4258 काठ मण्डी, सोनीपत	—सम—
19	सुरेश कुमार पुत्र कली राम गांव व डा0 साधा, करनाल	—सम—
20	वेद प्रकाश पुत्र छज्जु राम गांव व डा0 कबलाना, जिला रोहतक	—सम—
21	राकेश कुमार पुत्र आर के कश्यप मकान नं0 2173 / 19 सी, चण्डीगढ	—सम—

22	विरेनद्र कुमार पुत्र एस सी हांडा मकान नं0 440 / 7-ए, चण्डीगढ	-सम-
23	गुलशन कुमार पुत्र किशन चन्द कपूर प्लाट नं0 42,कच्छवा रोड, करनाल	-सम-
24	अपनन्द स्वरुप पुत्र बोज राम जैन मकान नं0 302, गली मथरा दास,सिरसा	-सम-
25	संगीता पुत्री साधु राम मकान न.0 645, दयाल बाग गेट, करनाल	-सम-
26	आनन्द प्रकाश पुत्र जिया लाल नजदीक पंजाब मैडिकल स्टोर, सोनीपत	-सम-
27	सुभाष कुमार पुत्र डी एस वर्मा नैषनल मैडिकल हाल, थानेसर	-सम-
	आशुलिपिक (स्टै नोटाईपिस्ट)	
28	संतोष पुत्री ज्ञान चंद ाहजदपुर, तह0 नारायणगढ	-सम-
29	कमलेश कुमारी पुत्री सौदागर मल गांव डिपल, डा0 डण्डहेरी, हिसार	-सम- (अब सेवा में नही है)

30	माया देवी पुत्री टी एस तोमर 471/13, कमलवीर हाउस, टमलटस रोड, रोहतक	—सम—
31	रोशन लाल पुत्र सेवा सिंह गांव सिसमोड, कुरुक्षेत्र	—सम—
32	बलबीर सिंह पुत्र राम चन्द गांव व डा0 कर्मगढ, साहुवाला-1, सिरसा	—सम—
33	जय कृष्ण पुत्र गैण्डा राम गांव महमदपुर, जी पी, गुंडियाना।	—सम—
	लिपिक	
34	बाल सिंह वर्मा पुत्र मोहल्लू सिंह मकान नं. 84, कुलदीप नगर, यमुनानगर जिला अम्बाला	—सम—
35	मुख्तयार सिंह पुत्र राम सिंह गांव रुडकी, डा0 मणक टावर, तह0 नारायणगढ, अम्बाला	—सम—
36	विजय कुमार पुत्र गुरदास मल मकान नं 242, बी सी बाजार, अम्बाला कैट	—सम—
37	राजकुमारी पुत्री नन्द लाल लुथरा भवन, पुरानी सब्जी मण्डी, कैथल जिला कुरुक्षेत्र	—सम—
38	हर्षवर्धन पुत्र राम सरन दास हाउस के पीछे,	—सम—

	पी एस लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र	
39	कृष्ण चन्द पुत्र रुलिया राम गांव भाणा, डा0 रतनगढ, जिला कुरुक्षेत्र	-सम-
40	मधु बाला पुत्र बशन दास टेलर मास्टर, मकान नं 138, मोहल्ला लोहिया बाड, होहीना, जिला गुडगांव	-सम-
41	रमेश कुमार पुत्र हेत राम गांव व डा0 उजीना, तह0 नूहं, गुडगांव	-सम-
42	सुलेख खान पुत्र हवील खान गांव व डा0 बीसरु, जिला गुडगांव	-सम-
43	हाशियार सिंह पुत्र उमराव सिंह मकान नं0 52/293, आचार्य पुरी जिला गुडगांव	-सम-
44	तेज राम पुत्र राम चन्द्र गांव खजूरवाला, सोहना, गुडगांव	-सम-
45	बिशम्बर पुत्र चमन लाल 342/1, वाड नं0 7, अर्जुन नगर, गुडगांव	-सम-
46	बृज मोहन पुत्र मनशा राम लेबर आफिस, लेबर निरीक्षक गुडगांव	-सम-

47	अशोक कुमार पुत्र लखमेर सिंह ेखो हवेली, जटवाडा गेट, बावल, महेन्द्रगढ	—सम—
48	हर लाल पुत्र समा लाल गांव राठीवास डा0 करनावता, तह व जिला महेन्द्रगढ	—सम—
49	धम्रपाल पुत्र मोती राम गांव टोटकिया, डा भोडिया कैनालपुर तह0 रिवाडी, जिला महेन्द्रगढ	—सम—
50	मदन लाल पुत्र बहादुर चन्द वार्ड न 6, बैरक 24, एच 28-29 गांधी नगर, रोहतक	—सम—
51	विरान रानी पुत्री बहादुर चन्द मकान नं0 463214, डी एल एफ कालोनी रोहतक	—सम—
52	लक्ष्मी नारायण पुत्र बनशी धर गांव व डा0 टुमाना, तह0 कोसली, रोहतक	—सम—
53	सुन्दर सिंह पुत्र चान्द राम गांव व डा0 चमारियां, रोहतक	—सम—
54	भगवन्त सरुप पुत्र हुक्म चन्द मकान नं.0 642 / 10, किला रोड पुरानी सब्जी मण्डी, रोहतक	—सम—

55	प्रताप सिंह पुत्र नन्द राम गांव व डा खराटी खेडा, तह0 फतेहाबाद, हिसार	—सम—
56	सूरेश धमीजा पुत्र किशन लाल एम एच एस डी बी जगजीवनपुरा विफद रोड, फतेहाबदा, हिसार	—सम—
57	भाशी वाला पुत्री अशोक कुमार दुकान न0 118, राज गुरु मार्केट, किरयाना मर्चेन्ट, हिसार	—सम—
58	जिले सिंह पुत्र रणजीत सिंह गांव व डा0 लाडवा तह0 व जिला हिसार	—सम—
59	राधे श्याम पुत्र वीर भान म0 न0 613, मगीया मनधेन स्कूल, लोहारु, भिवानी	—सम—
60	रविन्द्र कुमार पुत्र हरनाम दास सिविल हस्पताल तोशाम, तह0 जिला भिवानी	—सम—
61	पृथ्वी सिंह पुत्र बदरी सिंह बिश्नोई कालोनी, सेवान मण्डी, भिवानी	—सम—
62	जय सिंह पुत्र राम चन्द गांव गोविन्दपुरा, डा0 बरौटी, जीन्द	—सम—

63	प्रेम चंद पुत्र नन्द लाल गांव व डा0 थुराना जिला हिसार	—सम—
	चालक	
64	धर्मपाल पुत्र इन्द्र राज गांव व डा0 किरणवाड, तह0 बवानी खेडा, जिला भिवानी	—सम—
65	बलवन्त पुत्र गुरमिक सिंह गांव मनका, डा0 रामगढ, तह0 कालका, अम्बाला	—सम— (अब सेवा में नहीं है)
	सेवादार	
66	जुबेदा मकान न. जे 13 न0, 4 एन आई टी, फरीदाबाद	अपने स्वर्गीय पति के सीान पर
67	राम नाथ पुत्र कुन्दन लाल गांव व डा0 घरौंडा, करनाल	रोजगार विभाग के माध्यम से
68	सुरेश पाल पुत्र मालू राम गांव व डा0 रामपुर, अम्बाला	—सम—
	फैरो खैलासी	

69	रामफल गांव व डा0 पत्रठेडा, कलां, फरीदाबाद	—सम—
----	--	------

अनुबन्ध 'बी'

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987-88
तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूचि—

क्रमांक	नाम व पता	नियुक्ति की विधि
	उप मण्डल अभियन्ता	
	सर्वश्री / श्रीमती	
1	विरेन्द्र कुमार पुत्र बसंत सिंह म. न. 145, सोनीपत रोड, रोहतक	रोजगार विभाग के माध्यम से
2	प्रीतमोहन पुत्र म. न. 69, "सैक्टर 9, पंचकूला	—सम—
3	भुपिन्द्र पुत्र म. न. 69-113/6, अशोका रोड, भिवानी	—सम—
4	अशवनी पुत्र म. न. 3-ए, कैलाश नगर, अम्बाला शहर	—सम—

	सहायक प्रारूपकार (सिविल)	
5	रण प्रकाश पुत्र प्रेम चन्द गांव व डा0 मलिकपुर, बांगर, तह0 छिछरोली, अम्बाला	—सम—
6	प्रोमिला बांसल पुत्री श्री श्याम सुन्दर म0 न0 123-ए, सैक्टर 20, चण्डीगढ	—सम—
7	शिव कुमार सिंगला पुत्र धनी राम धनी राम, म0 न0 716/6, फरीदाबाद	—सम—
	लेखा सहायक	
8	दया सागर पुत्र राम प्यारा, ए-501, पिछे चर्च सदर बाजार, करनाल	—सम—
9	नरिन्द्र चौपडा पुत्र औम प्रकाश, म0 न0 353/32ए, चण्डीगढ	—सम—
10	श्याम सुन्दर पुत्र साधुराम, गाव व डा0 मुलालता, तह फिरोजपुर जिरका	—सम—
11	सतीश कुमार पुत्र सागर चन्द, म0 न0 10/841, मोहल्ला सोदन वाला, नजदीक जैन मन्दिर, सोनीपत	—सम—
12	योगेन्द्र मोहन पुत्र सोम नाथ, म0 न0 212/11, पंचकूला	—सम—
13	विरेन्द्र कुमार पुत्र नारायण सिंह,	—सम—

14	कमलजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, ए-9, जी पी ओ कम्पाउंड, अम्बाला शहर	—सम—
15	रजनीश चन्द्र पुत्र बी सी तिरखा, म0 न0787 / 22-ए, चण्डीगढ	—सम—
16	सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री निवास, गांव वडा पिल्लुखेडा मण्डी, जिला जीन्द	—सम—
17	सतबीर सिंह पुत्र योदाराम, गांव व डा0 सांगवाडी, जिला भिवानी	—सम—
18	घनश्याम दास पुत्र श्री पाल, हरियाणा स्टेट हैण्डलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कारपोरेशन, चण्डीगढ	—सम—
	स्टैनोग्राफर	
19	सरोज वाला म0 न0 1765, मोहल्ला राम पुरा, हिसार	—सम—
20	सुरेश कुमारी पुत्री फुल सिंह, नजदीक एस डी एम निवास, हांसी, हिसार	—सम—
21	विशवेन्द्र कुमार पुत्र कली राम, 3223 / 21-डी, चण्डीगढ	—सम—
22	हरी किशन म0 न0 65 / 11-2, ढाणी बडवाली, हिसार	—सम—
23	प्रेम लता म न0 5 / 15, पक्का बाग, खरखौदा,	—सम—

	सोनीपत	
24	दर्शना रानी पुत्री सेवा दास, किला मोहला इन्दरी, करनाल	—सम—
	अनुरेखक	
25	राय सिंह पुत्र जवाहर राम, मकान न. 152/6, जाट मोहल्ला माता गेट, कैथल	—सम—
26	लाल सिंह पुत्र शीश राम, गांव वजिदपुर, डा0 हीरमदाना, कुरुक्षेत्र	—सम—
27	रमेश कुमार पुत्र राज किशन, मकान न0 6/1339-ए, मोडर्न कालोनी, यमुनानगर	—सम—
28	विनु कुमार पुत्र अभी लाल, नजदीक ऐक्शन निवास, पी डबल्यू डी कालोनी, नारनौल	—सम—
29	मेहर दीन पुत्र फतेह मोहम्मद, गांव व डा0 बलवाडी, तह0 रिवाडी, महेन्द्रगढ	—सम—
30	कैलाश चन्द्र पुत्र पन्ना लाल, गांव व डा0 ठसका, तह0 पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र	—सम—
31	जगन्नाथ पुत्र नेक राम, गांव व डा0 चन्दाना, तह0 कैथल	—सम—
32	वेद पाल पुत्र होरी सिंह, गांव इन्दुगढी, डा0 गोहाना, जिला सोनीपत	—सम—

33	जय प्रकाश पुत्र अनन्त राम, गांव व डा0 गढी बीरबल, तह इन्द्री, जिला करनाल	—सम—
34	अशोक कुमार पुत्र घर्मपाल, मकान न0 एम एम 2, वी डबल्यू सी सुरजपुर, तह0 कालका	—सम—
35	विनोद कुमार पुत्र माधो राम गांव व डा0 नियना, सब तह0 इन्द्री, करनाल	—सम—
	चालक	
36	राज सिंह पुत्र विजय सिंह, झंकाल गली, मकान न0 45, पुराना फरीदाबाद	—सम—
37	प्रदीप कुमार पुत्र तिलक राज, दुकान न.8, माडल टाउन, अम्बाला शहर	—सम—
38	राम किशन पुत्र राम कुमार, गांव व डा0 दनोद, तह0 भिवानी	—सम—
39	लाभ सिंह पुत्र जगीर सिंह,	—सम—
	सेवादार	
40	सुरिन्द्र पाल पुत्र राजा राम, गांव व डा0 रेवर, जिला करनाल	—सम—
41	रजिन्द्र कुमार पुत्र शान्ति प्रकाश, मकान न. 785/9, पंचकूला	—सम—

42	मनशा राम पुत्र लछमन दास, मकान न.2281, फेस-2, राम दरबार, चण्डीगढ	—सम—
	सर्वे खलासी	
43	चमन लाल पुत्र मकान न 2537 / 15, पंचकूला	—सम—
44	मान सिंह पुत्र पन्नु मल, गांव व डा0 धरीन्दा, अम्बाला	—सम—
	स्वीपर—कम—चौकीदार	
45	कर्मपाल पुत्र नथा राम, गांव व डा0 रेवर, जिला करनाल	—सम—
46	पूर्ण चन्द पुत्र धनी राम, गांव व डा0 मंगलपूर, जिला करनाल	—सम—
47	कृष्ण पुत्र धनपा राम, गांव व डा0 मंगलपूर, जिला करनाल	—सम—
48	राम दास पुत्र तुलसी राम, गांव व डा0 झण्झहरी, करनाल	—सम—
49	रिशी पाल पुत्र तुलसी राम, गांव व डा0 झण्झहरी, करनाल	—सम—
50	सतपाल पुत्र सुरजा राम, गांव व डा0 बगपत, जिला करनाल	—सम—

51	राम कुमार मकान न 85 / 14, पंचकूला	सीधी भर्ती द्वारा
----	-----------------------------------	----------------------

अनुबन्ध 'सी'

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986-87
मे तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूची-

क्रमांक	नाम व पता	नियुक्ति की विधि	विवरण
1	2	3	4
	सहायक जिला न्यायवादी		
	सर्वश्री / श्रीमती		
1	बी० के० सिंगला	सीधी भर्ती द्वारा	
2	ए० के० बख्शी मकान नं 1228, सैक्टर 15-बी, चण्डीगढ	-सम-	सेवा में नहीं है
	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल		
3	जवाहर लाल पुत्र राम चन्द्र, मकान नं 16, वार्ड नं 3, ब्लॉक नं 16, गांधी नगर,	-सम-	सेवा में नहीं है

	रोहतक		
	लिपिक		
4	राजेन्द्र कुमार पुत्र लोक राम, माता गेट, रोहतक	—सम—	—सम—
5	धर्मबीर सिंह पुत्र चान्द राम, मकान नं 19/285, प्रेम नगर, रोहतक	—सम—	—सम—
6	संजय पुत्र जय लाल जैन, म नं 59/10, हारवा गली, पाहरु चौक, रोहतक	—सम—	—सम—
7	हरमेश कुमार पुत्र बुध राम, मार्फत चानन टी स्आल, बस स्टेण्ड रोड, धुरी, पंजाब	—सम—	—सम—
8	सरोज बाला पुत्री गोविन्द राम, मं नं 9456/6, कलाल माजरी, अम्बाला	—सम—	—सम—
9	अंजु बाला पुत्री बिहारी लाल, ई-83, पौलटरी एरिया, नीलाखेडी, करनाल	—सम—	—सम—
10	रमेश कुमार पुत्र रण सिंह, गावं मातण, जिला रोहतक	—सम—	—सम—
11	राकेश कुमार पुत्र हकुम चंद, 336/5, पाडा मौहल्ला, बडा बाजार, रोहतक	—सम—	—सम—
12	हरीश चन्द पुत्र श्री चन्द, मं नं 548, वार्ड	—सम—	—सम—

	नं 18, रविदास नगर, रोहतक		
13	भगवन्त दयाल पुत्र हजारी लाल, जैन पुरा, रोहतक	—सम—	—सम—
14	दारा सिंह पुत्र हरनेक सिंह, विश्वकर्मा नगर, काठ मण्डी, रोहतक	—सम—	—सम—
15	हरीश कुमार पुत्र चरन्जी लाल, 74123, कुल मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
16	भारत भूषण पुत्र श्री डी एन मेहता, बी-2, मं नं 1211, बडा बाजार, रोहतक	—सम—	—सम—
17	गौरी शंकर पुत्र लक्षमण दास, मं नं 1818, वार्ड नं 3, पारा मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
18	अशोक कुमार पुत्र रधुबीर सिंह, न्यू राज राम फ़ैक्ट्री, हिसार रोड, रोहतक	—सम—	—सम—
19	राकेश कुमार पुत्र हर भगवान दास, मं नं 253/2, वार्ड न 6, कल्याण मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
20	सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, वार्ड नं 6, मं नं 190, गांधी नगर, रोहतक	—सम—	—सम—
21	कर्मवीर पुत्र सेम सिंह, मं नं 553, वार्ड नं 30, रोहतक	—सम—	—सम—

22	अशोक कुमार कटयाल पुत्र श्री सेवा मल, बी 2 158, पारा मोहल्ला, नजदीक पाहवा फैक्टरी, रोहतक	—सम—	—सम—
23	विनोद कुमार पुत्र मं नं 22, गांधी नगर, रोहतक	—सम—	—सम—
24	प्रवीरण सहगल पुत्र कृष्ण कुमार, 160—ए, सुभाष नगर, रोहतक	—सम—	—सम—
25	महेन्द्र सिंह पुत्र बजिन्द्र कुमार, वसुदा शावन सरकुलर, नजदीक कांग्रेस भवन, रोहतक	—सम—	—सम—
26	संजीव कुमार पुत्र राम कुमार, पूण्डीर 255/7, पारास मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
27	राजिन्द्र सिंह पुत्र सुभाष चन्द, बी-2, 472 सालेडा मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
28	रविन्द्र कुमार पुत्र रूप चन्द, मं नं 452/33, जनता कालोनी, रोहतक	—सम—	—सम—
29	वशिष कुमार जैन पुत्र शांती प्रकाश जैन मं नं 15, जैन मंदिर गली, बाहरा बाजार, रोहतक	—सम—	—सम—
30	मुनीष कुमार पुत्र भजन लाल, मं नं 669—बी, प्रतान मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—

31	संजीव कुमार पुत्र अमर चन्द, मकान नं 3329/1, सैक्टर 40-डी, चण्डीगढ	-सम-	-सम-
32	शिव कुमार पुत्र पृथ्वी चन्द शास्त्री, तितलीवाली मकान नं 193, वार्ड नं 32, जनता कालोनी रोहतक	-सम-	-सम-
33	मुकेश शर्मा पुत्र लाजपत राय, मोहल्ला बाबरा, रोहतक	-सम-	-सम-
34	सुरेन्द्र पाल पुत्र निहाल चन्द, मं नं29, इन्दिरा कालोनी, रोहतक	-सम-	-सम-
35	विनोद कुमार पुत्र चेतन सिंह, मकान ने0 639/3, गढी मोहल्ला, रोहतक	-सम-	-सम-
36	रोशन लाल पुत्र रधुबीर सिंह, 530/14, गोहाना रोड, हबण्डल, राहेतक	-सम-	-सम-
37	सतबीर सिंह पुत्र जय कृष्ण, मकान नं 860, वार्ड नं2,धानी मोहल्ला, रोहतक	-सम-	-सम-
38	कुल भूषण पुत्र एन डी शर्मा, मं नं 2410, सैक्टर 19-सी, चण्डीगढ	-सम-	-सम-
39	बलराज पुत्र दया चन्द, गांव व डा0 बरौडा, तह0 गोहाना, जिला सोनीपत	-सम-	-सम-
40	राम अवतार पुत्र जीत राम, गांव व डा0	-सम-	-सम-

	विरान, तह0 व जिला भिवानी		
41	सुभाष चन्द्र पुत्र सुरज भान, गांव व डा0 जुलाना, जीन्द	—सम—	—सम—
42	सुरेश कुमार पुत्र रधुबीर दत्त, गांव व डा0 बिजाना, भिवानी	—सम—	—सम—
43	कृष्ण कुमार सैनी पुत्र दल सिंह, मकान नं0 555, वार्ड न 19, सैणी पुरा, रोहतक	—सम—	—सम—
44	दया सिंह पुत्र औम प्रकाश, मकान नं0 814, वार्ड नं 1, नजदीक आई0 बी0 कालेज, रोहतक	—सम—	—सम—
45	महावीर प्रसाद पुत्र सत नारायण, मकान नं0 1271/9, बहलुआ मोहल्ला, कादियान गली, रोहतक	—सम—	—सम—
46	चन्द्र प्रभा पुत्री स्व0 श्री एन एल चुघ, 6 राम पुरी, कालका जी, नई दिल्ली	—सम—	—सम—
47	राजीव कुमार पुत्र जगदीश चन्द, मकान नं0 97, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भिवानी	—सम—	—सम—
	सेवादार		
48	जगपाल सिंह पुत्र गजे सिंह, चुनीपरा रोहतक	—सम—	संवा मे नही है

49	शमशेर सिंह पुत्र श्री राम, नजदीक इन्दिरा कालोनी, रोहतक	—सम—	—सम—
50	नरेश कुमार पुत्र देवी राम, डेरी मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
51	अशोक कुमार पुत्र तारीफ सिंह, डेरी मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
52	दया नन्द पुत्र महताब सिंह, डेरी मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
53	महेन्द्र सिंह पुत्र घमण्डी लाल, डेरी मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
54	महेन्द्र सिंह पुत्र पृथी सिंह, मार्फत आर0 एस0 कादयान, कैथान मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
55	नरेश कुमार पुत्र दर्शन दयाल, बाबरा मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
56	रमेश कुमार पुत्र लच्छु राम, मकान नं0 267/7, बाबरा मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
57	नर बहादुर पुत्र घुमन बहादुर, मकान नं0 121, सैक्टर 9, पचंकुला	—सम—	—सम—
58	श्री भगवान पुत्र जागे राम,	—सम—	सेवा मे नही है

59	श्री राज कुमार पुत्र सत्य नारायण,	—सम—	—सम—
60	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी शशी भूषण,	—सम—	—सम—
61	कुलदेव राज पुत्र हरी चन्द,	—सम—	सेवा में है

अनुबन्ध 'डी'

हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987-88
में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूची—

क्रमांक	नाम व पता	नियुक्ति की विधि	विवरण
1	2	3	4
	सहायक जिला न्यायवादी		
	सर्वश्री / श्रीमती		
1	अभी चन्द सिंहाग पुत्र श्रीमान, गांव व डा0 सिवानी बालम, तह0 व जिला हिसार	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में नहीं है
2	कन्हैया लाल पुत्र हेत राम, गाव व डा0	—सम—	—सम—

	दांड, जिला हिसार		
3	जसवन्त सिंह पुत्र श्री शंकर, गाव व डा0 किरथन, जिला हिसार	—सम—	सेवा में है
4	कृष्ण कुमार पुत्र राम जी लाल, गाव व डा0 जेवरा, जिला हिसार	—सम—	—सम—
5	अनिल कुमार पुत्र मकान नं0 2, सैक्टर 14, पंचकूला	—सम—	—सम—
6	जगत पाल पुत्र धींगड रोड, फतेहाबाद जिला हिसार	—सम—	—सम—
	सहायक प्रारूप		
7	प्रतिभा रानी पुत्री श्री एम पी गुप्ता, मकान नं0 1551/20 बी, चण्डीगढ	—सम—	सेवा में है
8	सुनीता तनेजा पुत्री श्री सुन्दर दास, मकान नं0 4987, पंचकूला	—सम—	—सम—
9	गीता शर्मा पुत्री नरदेव शास्त्री, 707 मेरठ रोड, करनाल	—सम—	सेवा में नहीं है
10	जय करण पुत्र किशन चन्द, जिला	—सम—	—सम—

	रोहतक		
	कनिष्ठ अभियन्ता		
11	यश पाल पुत्र बी० डी० बत्रा, मकान नं० 2616 ए, सैक्टर 20 सी, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
12	शीतल ठुकराल पुत्र गुरबख्श लाल, मकान नं० 1703/2, सैक्टर 45 बी, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
13	प्रवीण बजाज पुत्र धर्म चन्द, 36 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भिवानी	—सम—	—सम—
14	हरी सिंह पुत्र हेत राम, गाव व डा० डाबी कलां, जिला हिसार	—सम—	सेवा में है
15	जगत सिंह पुत्र हमीर सिंह, गाव व डा० नेहला, जिला हिसार	—सम—	—सम—
16	रन सिंह पुत्र हेम राम, गाव व डा० कुलेरी, जिला हिसार	—सम—	—सम—
17	राज पाल पुत्र हरि सिंह, गाव व डा० दहोला, जिला जीन्द	—सम—	—सम—
18	जगदीश चन्द्र पुत्र मनी राम, गाव व	—सम—	—सम—

	डा0 शाहपुर, जिला हिसार		
19	राम सरुप पुत्र मुख राम, गाव व डा0 अगौहा, जिला हिसार	—सम—	—सम—
20	जय सिंह पुत्र रावत राम, गाव व डा0 जोदकन जिला सिरसा	—सम—	—सम—
21	सुंदर सिंह पुत्र श्री राम स्वरुप, गाव व डा0 अन्नाकलां, तह0 व जिला सिरसा	—सम—	—सम—
22	जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह, गाव व डा0 बीबीपुर जाटान, जिला करनाल	—सम—	—सम—
23	पंकज भूषण पुत्र ज्ञान प्रकाश, 42 आदर्श नगर, भिवानी	—सम—	—सम—
24	होशियार सिंह पुत्र जय राम चन्द मकान नं0 1090 / 10, विनोद नगर, हिसार	—सम—	—सम—
25	राम फल पुत्र चतुर सिंह गाव व डा0 लोन, नरवाना, जिला जीन्द	—सम—	—सम—
26	भूप सिंह पुत्र दलेर राम, हरियाणा	—सम—	—सम—

	प्रदेश लोक दल आफिस, रोहतक		
27	महावरी प्रशाद पुत्र श्री मनोहर लाल, गाव व डा0 भट्टू कलां, जिला हिसार	—सम—	—सम—
28	मनोहर लाल पुत्र श्री इन्द्र राज, नजदीक रेलवे स्टेशन, मण्डी आदमपुर, जिला हिसार	—सम—	—सम—
29	मेवा सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, गाव व डा0 बाल समन्द, जिला हिसार	—सम—	—सम—
30	विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रिसाल सिंह, गाव व डा0 खरड अलीपुर, जिला हिसार	—सम—	—सम—
31	दवेन्द्र कुमार पुत्र हरी राम, कार्ट रोड, नरवाना, जिला जीन्द	—सम—	—सम—
32	शमशेर सिंह पुत्र टेक चन्द, गांव व डा0 नरवाना, जिला जीन्द	—सम—	—सम—
33	हवा सिंह पुत्र मोहन लाल, गांव व डा0 बेखडा कलां, तह0 फतेहाबाद	—सम—	—सम—
34	सुरेश पाल पुत्र छज्जु राम, न्यू कालोनी, नजदीक शिव मंदिर, शाहबाद	—सम—	—सम—

	कुरुक्षेत्र		
35	जगजीत सिंह पुत्र बनवारी लाल, गांव व डा0 किरडान तह0 फतेहाबाद	—सम—	—सम—
36	विनय कुमार पुत्र निहाल सिंह, गांव व डा0 नारनौंद तह0 हांसी	—सम—	—सम—
37	देवी लाल पुत्र माल सिंह, गांव व डा0 छहरवाल जिला सिरसा	—सम—	—सम—
38	हरदीप सिंह पुत्र पी0 एस0 मलिक, कोठी नं0 629, सैक्टर 6, पंचकूला	—सम—	—सम—
39	गुटी राम पुत्र बहादुर सिंह, गांव व डा0 खेडी सरेन जिला सिरसा	—सम—	—सम—
40	सुभाष चन्द्र पुत्र मुन्शी राम, कोठी नं0 629, सैक्टर 6, पंचकूला	—सम—	—सम—
41	जसमत सिंह पुत्र सुरजा राम, गांव व डा0 बावड कलां, भटटू जिला हिसार	—सम—	—सम—
42	गिरधारी लाल पुत्र राम प्रताप, गांव धीयोल, पालीय डा0 बसवाला खुर्द सिरसा	—सम—	—सम—

43	राम किशन पुत्र शिव नारायण, गांव व डा0 कुमथल, जिला सिरसा	—सम—	—सम—
44	भरत सिंह पुत्र श्री हनुमान, गांव व डा0 बावड कलां, भटटू, जिला हिसार	—सम—	—सम—
45	भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, गांव व डा0 बहबलपुर, जीन्द	—सम—	—सम—
46	श्याम प्रकाश पुत्र श्री मनफल सिंह, गांव व डा0 भटटू कलां, जिला हिसार	—सम—	—सम—
47	मांगे राम पुत्र शिव लाल, गांव व डा0 खावडा कलां	—सम—	—सम—
48	अनुरुध बिश्नोई पुत्र इन्द्र जीत, गांव व डा0 जंडवाला बिश्नोइयान, जिला सिरसा	—सम—	—सम—
49	पृथ्वी सिंह पुत्र देवी लाल, गांव व डा0 जंडवाला चौटाला, जिला सिरसा	—सम—	—सम—
	आशुलिपिक		
50	रोहताश पुत्र श्री बनवारी लाल गांव व डा0 खेरम पुर जिला हिसार	—सम—	—सम—

51	जगदीश चन्द्र पुत्र श्री आत्मा राम गांव व डा0 खेरम पुर जिला हिसार	—सम—	—सम—
52	सज्जन कुमार पुत्र श्री मनफूल सिंह, गांव व डा0 किरमारा, जिला हिसार	—सम—	सेवा में नहीं है
53	सुगन कुमार पुत्र बस्ती राम, गांव व डा0 नंगथला, जिला हिसार	—सम—	—सम—
	लिपिक		
54	ललित कुमार पुत्र खरैती लाल, मकान नं0 106, वार्ड नं0 21, सामने भरतगढ, रोहतक	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में नहीं है
55	रमेश कुमार पुत्र दूनी चन्द, मार्फत हैप्पी स्कूल, सिविल रोड, रोहतक	—सम—	—सम—
56	इन्दू वाला पुत्र मुलख राज, मकान नं0 1215,बी-2, रोहतक	—सम—	—सम—
57	प्रेम प्रकाश पुत्र श्री सागर मल, मकान नं0 376-ए, पारस मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
58	मनोहर लाल पुत्र श्री धर्म चन्द मार्फत कृपा राम, देव राज, साडी क्लोथ	—सम—	—सम—

	मार्किट, रोहतक		
59	रमेश चन्द पुत्र श्री मंगत राम मकान नं० 698 / 10, बाबरा मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
60	राम सिंह पुत्र सुरज भान गावं धानी केन्डू, डा० खेकपुरा, जिला हिसार	—सम—	—सम—
61	राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह मकान नं० 619 / 2 सन्त आनन्दपुर,, रोहतक	—सम—	—सम—
62	राम निवास पुत्र श्री दया नन्द गांव व डा० हथवाला, तह० जुलाना जिला जीन्द	—सम—	—सम—
63	रामदीया पुत्र श्री सुदन राम मकान नं० 671 / 3, गढी मौहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
64	सुरेश राय पुत्र श्री गणपत राय सामने पी० डबल्यू डी, स्टोर झज्जर रोड, रोहतक	—सम—	—सम—
65	रमेश कुमार पुत्र श्री पी० एन० गुप्ता मकान नं० 1095 ए, सैक्टर 23 बी, चण्डीगढ	—सम—	—सम—

66	आनन्द प्रकाश पुत्र श्री बृज मोहन मकान नं0 586, रुप कॉलोनी, सदर बाजार, करनाल	—सम—	—सम—
67	राम नाथ पुत्र बिन्दू राम मकान नं0 355/6, शाहबाद मारकंडा, करनाल	—सम—	—सम—
68	प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रकाश गांव व डा0 बालर्य, जिला रोहतक	—सम—	—सम—
69	कुष्ण देव पुत्र मांगे राम, विजय नगर, झज्जर, जिला रोहतक	सीधी भती 'द्वारा	सेवा में नहीं है
70	सूनील कुमार पुत्र श्री तिलक राज, मकान नं0 503, वार्ड नं 3, डेरी मोहल्ला, रोहतक	—सम—	—सम—
71	सुमन लता पुत्री प्रेम नाथ, मकान नं0 3201, सैक्टर 15 डी, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
72	खुशी राम पुत्र उदमी राम, गांव चूली खुर्द, डा0 चूली बागडीयान, जिला हिसार	—सम—	सेवा में है
73	राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, गावं	—सम—	—सम—

	व डा0 खाबडा कलां, जिला हिसार		
74	सतबीर सिंह पुत्र खेम चन्द, गावं आसा महाजन, डा0 भोडा होसनिक, जिला हिसार	—सम—	—सम—
75	भरत लाल पुत्र मनी राम, गांव व डा0 चीन्द्र, हिसार	—सम—	—सम—
76	विजय सिंह पुत्र शेरसिंह गांव व डा0 खाबडा कलां, हिसार	—सम—	—सम—
77	सुभाष चन्द्र पुत्र हरद्वारी लाल, गांव व डा0 बैन बनदोरी, हिसार	—सम—	—सम—
78	बलवान सिंह पुत्र जबर सिंह गांव व डा0 बैनिवाल, हिसार	—सम—	—सम—
79	रविन्द्र सिंह पुत्र देवी दयाल, गांव व डा0 चूली बागडीयान, जिला हिसार	—सम—	—सम—
80	ओम प्रकाश पुत्र जय, गांव व डा0 किरौडी, हिसार	—सम—	—सम—
81	देवी लाल पुत्र सुल्तान सिंह, गांव व डा0 सेनीवती, हिसार	—सम—	—सम—

82	श्मशेर सिंह पुत्र ज्ञानी राम, गांव जेबरा, डा0 सरसौद, जिला हिसार	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में नहीं है
83	महिन्द्र सिंह पुत्र गोपाला, गांव व डा0 थुएन, जिला हिसार	—सम—	सेवा में है
84	बिन्दु राम पुत्र अमर सिंह, गांव मीरपूर, डा0 जफरोहा, जिला हिसार	—सम—	—सम—
85	सतबीर सिंह पुत्र राम सरूप, गांव व डा0 चूलीकलां, जिला हिसार	—सम—	—सम—
86	जगदीश लाल पुत्र सुरजा राम, गांव भौंडिया बिश्नोईयान, डा0 डांड, जिला हिसार	—सम—	—सम—
87	धर्म पाल पुत्र दीलू राम, गांव व डा0 कुमहारिया, जिला हिसार	—सम—	—सम—
88	हनुमान सिंह पुत्र जजारी चन्द, गांव व डा0 शामसुख, जिला हिसार	—सम—	—सम—
89	सतबीर सिंह पुत्र श्योचन्द, गांव आसा महाजन, डा0 भोडा होसनिक, जिला हिसार	—सम—	—सम—

90	महाबीर सिंह पुत्र जगदीश चन्द्र गांव व डा0 शामसुख, जिला हिसार	-सम-	-सम-
91	दयानन्द पुत्र लोचन चन्द, गांव व डा0 सिवानी, जिला हिसार	-सम-	-सम-
92	भाग मल पुत्र राम कुमार, गांव किरन वाली, पो0 मुखपुररानी, सिरसा	-सम-	-सम-
93	देवी लाल पुत्र कस्तूरी लाल, गांव व डा0 खेडा खेडी, जिला हिसार	-सम-	-सम-
94	सतपाल पुत्र इन्द्रजीत सिंह, गांव व डा0 सरसौंद, जिला हिसार	-सम-	-सम-
95	सुभाष चन्द्र पुत्र बदन सिंह, गांव व पो0 नहला, हिसार	-सम-	-सम-
96	राम कुमार पुत्र करतार सिंह, गांव व पो0 नहला, हिसार	-सम-	-सम-
97	राजबीर सिंह पुत्र शिव लाल, गांव व पो0 नहला, हिसार	-सम-	-सम-
98	राजिन्द्र सिंह पुत्र बट्टी प्रसाद, गांव शेखपुर दरौली, हिसार	-सम-	-सम-

99	राज पाल पुत्र बुज लाल, गांव व पो0 खेडा खेडी, हिसार	-सम-	-सम-
100	राम चन्द्र पुत्र बग्गा राम, गांव व पो0 कुलेरी, हिसार	-सम-	-सम-
101	मोहिन्द्र सिंह पुत्र बनवारी लाल, गांव व पो0 कुलेरी, हिसार	-सम-	-सम-
102	शमशेर सिंह पुत्र बलवान सिंह, गांव व पो0 धिराय, हिसार	-सम-	-सम-
103	सुशील कुमार पुत्र तारा चन्द, गांव व पो0 नंगथला, हिसार	-सम-	-सम-
104	बलदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह, गांव व पो0 नंगथला, हिसार	-सम-	-सम-
105	चरणजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह, गांव व पो0 मेवोवाला, हिसार	-सम-	-सम-
106	बलवान सिंह पुत्र फूल सिंह, गांव व पो0 भट्टू कलां, हिसार	-सम-	सेवा मे नहीं है
107	जीत राम पुत्र लाल चन्द्र, गांव व पो0	-सम-	सेवा

	कुम्हारियन, हिसार		में है
108	पप्पु राम पुत्र राम साहिब, गांव व पो0 ढाणी खासा, हिसार	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में है
109	किशन कुमार पुत्र मंगत राम, गांव व पो0 किरधान, हिसार	—सम—	—सम—
110	कृष्ण कुमार पुत्र मनी राम, गांव व पो0 ढाणी खास, हिसार	—सम—	—सम—
111	सत्य पाल पुत्र इन्द्र सिंह, गांव व पो0 भौदा होसनक, हिसार	—सम—	सेवा में नहीं है
112	वेद प्रकाश पुत्र अमर चन्द, गांव व पो0 किरमारा, हिसार	—सम—	सेवा में है
113	फतेह सिंह पुत्र चेलू राम, गांव व पो0 चुली खुर्द, हिसार	—सम—	—सम—
114	कश्मीरी सिंह पुत्र भीम सिंह, मकान नं0 91, सैक्टर 2, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
115	शशी बाला पत्नी रामजी लाल, गांव हल्दरी, अम्बाला	—सम—	—सम—

116	सजन सिंह पुत्र जोरा राम, गांव व पो0 नहला, हिसार	—सम—	—सम—
117	देवी लाल पुत्र लघु राम, गांव व पो0 चुली बागडियां, हिसार	—सम—	—सम—
118	शमशेर सिंह पुत्र बलबीर, गांव व पो0 सोवानी बोलान, हिसार	—सम—	—सम—
119	हरपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, गांव व पो0 सोवानी बोलान, हिसार	—सम—	—सम—
120	सीता राम पुत्र शंकर लाल, गांव व पो0 शेखपुर दरौली, हिसार	—सम—	—सम—
121	सीरी चन्द पुत्र डांगन मल, गांव व पो0 सिंदौल, हिसार	—सम—	—सम—
122	शंकर पुत्र मेन पाल, गांव व पो0 दरौली, हिसार	—सम—	सेवा में है
123	शेर सिंह पुत्र हरदयाल, गांव व पो0 भटटू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
124	महिन्द्र सिंह पुत्र खैया राम, गांव व पो0 भटटू कलां, हिसार	—सम—	सेवा में

			नही है
125	औम प्रकाश पुत्र अमी लाल, गांव व पो0 बनावाली, हिसार	—सम—	सेवा में है
126	औम प्रकाश पुत्र बनवारी लाल, गांव व पो0 ढाणी कलां, हिसार	—सम—	—सम—
127	जगदीश कुमार पुत्र खुबी राम, गांव व पो0 बनावाली, हिसार	—सम—	—सम—
128	सतबीर सिंह पुत्र चतर सिंह, गांव व पो0 सरसौंद, हिसार	—सम—	—सम—
129	राजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह, गांव व पो0 कनौह, हिसार	—सम—	—सम—
130	कृष्ण चन्द्र पुत्र जय सिंह, गांव व पो0 चूली बागडियान, हिसार	—सम—	—सम—
131	औम प्रकाश पुत्र बलबीर सिंह, गांव व पो0 भटटू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
132	कृष्ण चन्द्र पुत्र सीरी राम, गांव व पो0 जगन, हिसार	—सम—	—सम—
133	बलवन्त सिंह पुत्र नेक राम, गांव व पो0	—सम—	—सम—

	भट्टू कलां, हिसार		
134	भूप सिंह पुत्र सीरी चन्द्र, गांव व पो0 ढाबी कलां, हिसार	—सम—	—सम—
135	सुबे सिंह पुत्र दलीप सिंह, गांव व पो0 दुर्जन पुर, हिसार	—सम—	—सम—
136	जोगी राम पुत्र हरि राम, गांव व पो0 कनौह, हिसार	सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में है
137	जगबीर पुत्र राम नारायण, गांव व पो0 चमारियान, रोहतक	—सम—	—सम—
138	सुभाष चन्द्र पुत्र बालू राम, गांव व पो0 खारा, हिसार	—सम—	—सम—
139	धर्मपाल पुत्र दिवान सिंह, गांव जेवरा व पो0 सरसौंद, हिसार	—सम—	—सम—
140	भागीरथ पुत्र सूरज भान, गांव व पो0 ढांड, हिसार	—सम—	—सम—
141	साधू राम पुत्र केहर सिंह, गांव व पो0 करनावाली, हिसार	—सम—	—सम—
142	बजीर सिंहु पुत्र सुमेर चन्द, गांव व	—सम—	—सम—

	पो० किरमारा, हिसार		
143	कृष्ण कुमार पुत्र श्योराम, गांव व पो० भटटू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
144	बालू राम पुत्र मनी राम, गांव व पो० भटटू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
145	हनुमान पुत्र रणजीत सिंह, गांव व पो० मोठसरायं, हिसार	—सम—	—सम—
146	रघुबीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, गांव व पो० कनौह, हिसार	—सम—	—सम—
147	कर्मबीर सिंह पुत्र मनी राम, गांव व पो० धूयां, हिसार	—सम—	—सम—
148	जय सिंह पुत्र छबील सिंह, गांव व पो० अग्रोहा, हिसार	—सम—	—सम—
149	हरगयान सिंह पुत्र अमी लाल, गांव व पो० खाबडा कलां, हिसार	—सम—	—सम—
150	रिसे सिंह पुत्र राम सिंह, गांव व पो० भटटू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
151	बलवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह, गांव व	—सम—	—सम—

	पो० काली रावण, हिसार		
152	राम किशन पुत्र मांडू राम, गांव व पो० सारंगपुर, हिसार	—सम—	—सम—
153	मदन लाल पुत्र राम रूप, गांव व पो० सारंगपुर, हिसार	—सम—	—सम—
154	उमेद सिंह पुत्र कृष्ण लाल, गांव चिकनवास हिसार	—सम—	—सम—
155	बलवन्त सिंह पुत्र सूरजा राम, गांव दुर्जन पुर पो० काजलां , हिसार	—सम—	—सम—
156	चन्दगी राम पुत्र हरजी राम, गांव जगन पो० असरावां, हिसार	—सम—	—सम—
157	रणजीत सिंह पुत्र मनफूल सिंह, गांव जगन पो० चुली बागडियानं, हिसार	—सम—	—सम—
158	कृष्ण कुमार पुत्र चन्दगी राम गांव जगन पो० चुली कुमारियां, हिसार	—सम—	—सम—
159	जगदीश कुमार पुत्र कांसी राम, गांव जगन पो० चुली किरमारां, हिसार	—सम—	—सम—
160	भूप सिंह पुत्र हरलाल, गांव जगन पो०	—सम—	—सम—

	चुली गिगोरानी, हिसार		
161	राम चन्द्र पुत्र सोवत राम, गांव जगन पो0 चुली नहला, हिसार	—सम—	—सम—
162	कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर गांव जगन पो0 चुली शामसुख, हिसार	—सम—	—सम—
163	संत लाल पुत्र नन्द लाल, गांव जगन पो0 चुली अग्रोहा, हिसार	—सम—	—सम—
164	साहिब सिंह पुत्र मालू राम, गांव जगन पो0 चुली डाबी कलां, हिसार	—सम—	—सम—
165	अर्जुन सिंह पुत्र जागर मल, गांव जगन पो0 चुली डाबी कलां, हिसार	—सम—	—सम—
166	धर्मपाल पुत्र फूल सिंह, गांव खेरमपुर, हिसार	—सम—	—सम—
167	सूबे सिंह पुत्र राजा राम, गांव अग्रोहा, हिसार	—सम—	—सम—
168	हनुमान पुत्र अमी लाल, गांव जगन पो0 चुली खासा महाजन, हिसार	—सम—	—सम—
169	कर्णबीर सिंह पुत्र निहाल सिंह, गांव	—सम—	—सम—

	ठसका, हिसार		
170	राजेश कुमार पुत्र कंवर सिंह, गांव ठसका, हिसार	—सम—	—सम—
171	गुलाब सिंह पुत्र रामजी लाल, गांव सुली खेडा, डा0 भट्टू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
172	जय बीर सिंह पुत्र खरग सिंह, गांव व डा0 कनोह, हिसार	—सम—	—सम—
173	धर्मपाल पुत्र सदन सिंह, गांव व डा0 कनोह, हिसार	—सम—	—सम—
174	महेन्द्र सिंह पुत्र चान्दी राम, गांव व डा0 कनोह, हिसार	—सम—	—सम—
175	रोहताश कुमार पुत्र दूली चन्द, गांव डांगी सिलावाला, डा0 सिवानी, भिवानी	—सम—	—सम—
176	राम पाल पुत्र रुली राम, गांव व डा0 कोहली, हिसार	—सम—	—सम—
177	छल्लु राम पुत्र अमी लाल, गांव फरान्सी, डा0 असरावां, हिसार	—सम—	—सम—
178	राजे राम पुत्र श्री राम, गांव व डा0	—सम—	—सम—

	किरमारा, हिसार		
179	महेन्द्र सिंह पुत्र हरी राम, गांव व डा0 भट्टू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
180	राम कुमार पुत्र छबील दास, गांव फरान्सी, डा0 असरावां, हिसार	—सम—	—सम—
181	कृष्ण कुमार पुत्र पंताप सिंह, गांव व डा0 कुलेरी, हिसार	—सम—	—सम—
182	विजय सिंह पुत्र तेलू राम, गांव व डा0 बरकी, हिसार	—सम—	—सम—
183	कुलवन्त सिंह पुत्र जय सिंह, गांव व डा0 किरमारा, हिसार	—सम—	—सम—
184	जगदीश पुत्र बीरबल सिंह, गांव व डा0 बडोपल, हिसार	—सम—	—सम—
185	जगदीश पुत्र सामसु राम, गांव व डा0 कलहेडी, हिसार	—सम—	—सम—
186	दयावीर सिंह पुत्र बलदेव सिंह, गांव व डा0 बोलान, हिसार	—सम—	—सम—
187	राज कुमार पुत्र मांगे राम, गांव व डा0	—सम—	—सम—

	बोलान, हिसार		
188	लाधु राम पुत्र खुशी राम, गांव सुली खेडा, डा0 भट्टू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
189	सुनीता देवी पुत्र कलीन्द्र दास, गांव दरौली वाया आदमपुर	—सम—	—सम—
190	इन्द्र सिंह पुत्र याद राम, गांव व डा0 पटवा, हिसार	—सम—	—सम—
191	कृष्ण लाल पुत्र धनपत राय, गांव व डा0 मखोसरानी, सिरसा	—सम—	—सम—
192	जसवन्त सिंह पुत्र करन सिंह, गांव व डा0 बनावाली, हिसार	—सम—	सेवा मे नही है
193	परस पुत्र फकीर चन्द, गांव व डा0 सिवानी बोलान, हिसार	—सम—	—सम—
194	कुन्दन लाल पुत्र जगदीश चन्द्र, गांव ढाण्ड, हिसार	—सम—	—सम—
195	धर्मवीर सिंह पुत्र चान्दा राम, मकान नं0 285, वार्ड नं0 19, प्रेम नगर, रोहतक	—सम—	—सम—

	अनुरेखक		
196	नरेन्द्र कुमार पुत्र दल सिंह, गांव नेहला, हिसार	—सम—	—सम—
197	पुरन चन्द पुत्र लछमन दास, गांव सुचाव, हिसार	—सम—	—सम—
198	महेन्द्र सिंह पुत्र श्योराम, गांव व डा0 भट्टू कलां, हिसार	—सम—	—सम—
199	अरविन्द शर्मा पुत्र बृज मोहन मकान नं0 1062/20 बी, चण्डीगढ।	—सम—	—सम—
200	धर्मवीर सिंह पुत्र फतेह सिंह, गांव व डा0 किरमारा, हिसार	—सम—	—सम—
201	कृष्ण कुमार पुत्र मनी राम, गांव व डा0 शामसुख, हिसार	—सम—	—सम—
202	सन्ता सिंह पुत्र बनवारी लाल, गांव व डा0 चौधरीवास, हिसार	—सम—	—सम—
203	धर्मपाल सिंह पुत्र माम राज, गांव व डा0 जमाल, हिसार	—सम—	—सम—
204	सत्यपाल सिंह पुत्र चुननी लाल, गांव व	—सम—	—सम—

	डा0 भौडिया खेडा, हिसार		
205	राजेश कुमार पुत्र हरसरूप राम, राम राय गेट, वाल्मिकी बस्ती, वार्ड नं0 24 / 290, जीन्द ।	—सम—	—सम—
206	वेद प्रकाश पुत्र सोलू राम, गांव व डा0 काली रावण, हिसार	—सम—	—सम—
207	सुरजभान पुत्र जोधा राम, गांव जेवरा पो0 सरसौद, हिसार	—सम—	—सम—
208	सुन्दर पाल पुत्र जोधा सिंह, गांव जेवरा पो0 सरसौद, हिसार	—सम—	—सम—
209	महावीर सिंह सोहाग पुत्र प्रताप सिंह, मकान नं0 5 / 204, गोविन्द नगर, सिरसा	—सम—	—सम—
210	दिलावर सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, गांव व डा0 डाबडा, हांसी	—सम—	—सम—
211	राज सिंह पुत्र गंगा दयाल, गांव व डा0 खावडा कलां, हिसार	—सम—	—सम—
212	जगदीश चन्द्र पुत्र हरि सिंह, गांव व	—सम—	—सम—

	डा0 किरमारा, हिसार		
	सेवादार		
213	दीवान सिंह पुत्र मंगला राम, गांव व डा0 शामसुख, हिसार	—सम—	—सम—
214	कालू राम पुत्र गोपी राम, गांव व डा0 धुली संगरियान, हिसार	—सम—	—सम—
215	भगत सिंह पुत्र कालू राम, गांव व डा0 खावडा कलां, हिसार	—सम—	सेवा में नहीं है
216	महेन्द्र सिंह पुत्र चन्दा सिंह, गांव व डा0 अग्रोहा, हिसार	—सम—	सेवा में है
217	दिलबाग सिंह पुत्र सुरजा राम, गांव व डा0 कनोह, हिसार	—सम—	—सम—
218	गोविन्द राम पुत्र रिसाला राम, गांव व डा0 सरसौद, हिसार	—सम—	—सम—
219	सोहन लाल पुत्र पत राम, गांव व डा0 चिन्दर, हिसार	—सम—	—सम—
220	बलराम पुत्र सोहन लाल, गांव व डा0	—सम—	सेवा

	खावडा कलां, हिसार		में नहीं है
221	बलवीर सिंह पुत्र शादी राम, गांव व डा0 खावडा कलां, हिसार	—सम—	सेवा में है
222	दलीप सिंह पुत्र सुरजा राम, गांव व डा0 ढाणी ईसर हिजरवाल खुर्द, हिसार	—सम—	—सम—
223	रणधीन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, गांव व डा0 कनोह, हिसार	—सम—	—सम—
224	जयवीर सिंह पुत्र दया नन्द, गांव बागनवाला, भिवानी	—सम—	—सम—
225	लील राम पुत्र फूल सिंह, गांव व डा0 खैरमपुर, हिसार	—सम—	—सम—
226	लहरी सिंह पुत्र घिसी राम, गांव व डा0 चिन्दर, हिसार	—सम—	—सम—
227	कृष्ण कुमार पुत्र नेकी राम, गांव व डा0 जगन, हिसार	—सम—	—सम—
228	रामधारी सिंह पुत्र पोलू राम, गांव व डा0 डाबी कलां, हिसार	—सम—	—सम—

229	सुभाष चन्द्र पुत्र सरदार राम, गांव व डा0 मिख वाला, जीन्द	-सम-	-सम-
230	धर्म पाल पुत्र मोहन लाल, गांव व डा0 शेखपुर, हिसार	-सम-	-सम-
231	उत्तम पाल पुत्र जय गोपाल, गांव व डा0 कनोह, हिसार	-सम-	-सम-
232	निहाल सिंह पुत्र ज्ञानी राम, लोहार सिवानी बोलान, हिसार	-सम-	-सम-
233	सुभाष चन्द पुत्र बनवारी लाल, गांव व डा0 कुलेरी, हिसार	-सम-	-सम-
234	बलवान सिंह पुत्र मेहर चन्द, गांव व डा0 खसूरा महाजन, हिसार	-सम-	-सम-
235	बलवन्त सिंह पुत्र औम प्रकाश, गांव व डा0 कुम्हारिया आग्रेहा, हिसार	-सम-	-सम-
236	हरी सिंह पुत्र माला राम, गांव व डा0 मोठसरां, हिसार	-सम-	सेवा मे नही है
237	वागरावत पुत्र त्रिलोक चन्द, गांव व	-सम-	-सम-

	डा0 कुमकेरिया वाया आग्रोहा, हिसार		
238	सुरेन्द्र कुमार पुत्र भरत सिंह, मकान नं0 5, इंदिरा कालोनी, रोहतक	—सम—	—सम—
239	राम कुमार पुत्र भले राम, मकान नं0 139/8ए, सैक्टर 20 बी, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
240	वीजेन्द्र कुमार पुत्र मलहा राम, गांव बोंड कला जिला भिवानी	—सम—	—सम—
241	हरमिन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल, मकान नं0 1205, सैक्टर 18, चण्डीगढ	—सम—	—सम—
	पटवारी		
242	सन्तोष कुमार पुत्र पन्ना लाल, म0 न0 134, वार्ड न 1, चरखी दादरी, भिवानी	—सम—	सेवा में है
243	बलवन्त सिंह मकान नं0 40, लाभ सिंह कालोनी, करनाल	—सम—	—सम—
244	उदे सिंह गांव व डा0 नांगल, तह0 हथीन, जिला फरीदाबाद	—सम—	—सम—

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इन्होंने कुछ लोगो को डेली वेजिज पर डायरेक्ट अप्वायंटमेंट की है। इनको ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज के थ्रू भरने में क्या दिक्कत थीं? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन पोस्ट्स को ऐम्पलायमेंट से लोग भरने के लिए सरकार विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब इन लोगो को लगाया गया था उस समय इनकी फौरी तौर पर जरूरत थी। लेकिन अब सरकार ने (हुडज़ अथार्टीज) ने पहले ही ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज को इस बारे में लिखकर दे दिया है। ज्यां ज्यां उधार से नाम आते जाएंगे इन पोस्टो को फिल अप कर लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि हुडडा के अन्दर जो मजदूर तबका या दूसरे वर्कर्स है उनके उपर कोई इंडस्ट्रीयल ला भी लागू होता है? हमें पता चला है कि उन्होंने इंडस्ट्रीयल ला के तहत स्टे ली रखी हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह रैलेवेंट सवाल नहीं है। आनरेबल मैम्बर यह तो बताएं कि किस बात की स्टे ले रखी है।

श्री अध्यक्ष: यह रैलेवेंट सवाल नहीं है। इसके लिए सैपरेट नोटिस देना चाहिए।

**Installation of Statue of Dr. B. R. Ambedkar at
Sohna**

***345 Ch. Shiv Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any decision was taken by the previous Government to install the statue of Late. Sh. B. R. Ambedkar at Sohnna on National Highway.

(b) if so, the reasons for its non-installation so far; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to install the said statue there?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) स्वर्गीय डा० बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा सोहना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित किए जाने बारे पिछली सरकार कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ख) डा० अम्बेडकर की प्रतिमा पहले ही डा० भीमराव अम्बेडकर मि। इन सोसायटी लि० (रजि०) सोहना क्षेत्र द्वारा सोहना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित की जा चुकी है।

(ग) डा० अम्बेडकर की प्रतिमा पहले ही सोहना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित की जा चुकी है।

चौधरी विठ्ठल लाल: स्पीकर साहब, मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या 255

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री जगपाल सिंह चौधरी, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Providing of Pre-Fabricated Houses in the state

***279. Shri Maha Singh:** Will the Minister of State for Housing be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide pre-fabricated houses in the State; and

(b) if so, the time by which the proposal is likely to materialize?

आवा राज्य मंत्री (श्री सुभाश कटियाल):

(क) जी हाँ।

(ख) इस पद्धति के भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्रिफैब्रिकेटिड हाउसिंग का स्टेट में कब तक निर्माण हो जाएगा, इसके लिए कितना समय और लगेगा जबकि पहले ही इस कार्य में काफी देर लग चुकी है। यह

महत्वपूर्ण योजना है और हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी ने पीछे इसके लिए आर्डर भी किए थे। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार और कितना समय लेगी?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: यह योजना वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर विचार करने पर कुछ टाइम तो लगेगा ही। ऐसी योजनाओं के लिए जल्द बाजी वांछित नहीं है। इसके भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है।

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इस योजना के भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा क्योंकि यह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या हाउस में महत्वहीन मामले भी आते हैं? वे यह भी बताएं कि वे कौन कौन से भिन्न भिन्न पहलु हैं जिन पर सरकार को विचार करना होगा?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: अध्यक्ष महोदय, भिन्न भिन्न पहलुओं से मेरा मतलब इन से होने वाले लाभ व हानियों से था। इसमें सब से बड़ी लाभ की बात यह है कि जो मकान चाहने वाले हैं उनकी तादाद ज्यादा है, मांग ज्यादा है और इससे निर्माण करने में तेजी आती है लेकिन इसके साथ साथ इसकी हानियां भी हैं जैसे जो निपुण मजदूरी है, उनके काम के अवसरों का अभाव हो जाता है। इसकी असैम्बली के लिए निपुण श्रमिकों और विदेश

औजारों की आवृत्त तकनीक होती है। इस तकनीक को अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लिमिटेड स्केल एवं भिन्न भिन्न नमूनों में अपनाया जाए तो यह तकनीक महंगी साबित होगी। कुछ संस्थाएं पूर्व संरचित मकानों की तकनीक पर कार्य कर रही हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही कार्यवाही की जानी है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह प्रिफैबरीकेटिड हाउसिज की क्या परिभाषा है? इसका क्या मतलब है?

श्री सुभाष चन्द कटियाल: पूर्व संरचित मकान।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि राज्य में सरकार की ओर से प्रिफैबरीकेटिड हाउसिज बनाने की योजना विचाराधीन है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में इस तरह की जो योजनाएं अपनाई गई हैं क्या उस का अध्ययन भी राज्य सरकार ने किया है, अगर किया तो उस अध्ययन की क्या रिपोर्ट है?

श्री सुभाष चन्द कटियाल: हरियाणा आवास बोर्ड ने लिमिटेड स्केल पर, थोड़े थोड़े स्तर पर इसको अपनाया है जैसे छत के स्लैब, दरवाजों खिड़कियां, चोखटों और दीवारों के निर्माण तक ही इस नीति को अडॉप्ट किया गया है। इस तरह की आरंभिक पूर्व संरचित तकनीक फिलहाल गुडगांव और अम्बाला में बन रहे मकानों में अपनाई गई है। बाकी हरियाणा में अभी यह

नहीं अपनाई गई है। पूर्ण रूप से इसे सारे देश में अपनाना सम्भव भी नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रिफ़ैबरीकेटिड हाउसिज स्कीम के अन्तर्गत किस किस स्तर पर कितना खर्चा आएगा?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री रधु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रिफ़ैबरीकेटिड हाउसिज से क्या लाभ होगा और खर्च में कितनी कमी आएगी?

श्री सुभाश चन्द कटियाल: स्पीकर साहब, इससे जो लाभ होगा वह मैंने बता दिया है।

Number of Harijan and Backward Classes Employees in Haryana Police

***399. Shri Jai Narain Khundia:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the number of Constables, Head constables, assistant sub inspector and inspectors in the state, at present;

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Harijans and Backward Classes, separately; and

(c) whether the number of persons, out of those as referred to in part (a) above is according to the reservation prescribed for the Harijans and Backward Classes; if not, the time by which the shortfall is likely to be completed?

गृह मंत्री (प्रे.0 सम्पत सिंह): वांछित सूचना निम्न प्रकार है:—

	सिपाही	प्रधान सिपाही	सहायक उप निरीक्षक	निरीक्षक
(अ)	13859	3039	1075	142
(ब) हरिजन	2427	418	97	13
पिछडे वर्ग	1539	273	106	8

(स) हरिजन: हरिजन जाति से संबंधित सदस्यों की 345 सिपाही, 190 प्रधान सिपाही, 118 सहायक उप निरीक्षक तथा 15 निरीक्षको की कमी है। सिपाहियों की कमी को भविश्य में की जाने वाली भर्तियों के समय पूरा कर लिया जाएगा।

उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार बी-1 सूचि (जो कि सिपाही के पद से प्रधान सिपाही की उन्नति का मूलाधार है) प्रस्तुत करनेमें कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। अतः प्रधान सिपाही तथा उससे उपर के पदों में वर्तमान हिदायतो के अनुसार आरक्षण की कमी पूरी नहीं की जा सकती।

पिछडे वर्ग: सिपाही तथा सहायक, उप निरीक्षक के पदों के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के सदस्यों की संख्या आरक्षण कोटे के अनुसार है और प्रधान सिपाही तथा निरीक्षको के पदों में 31 व 6 की कमी है, जिस कमी को उपरोक्त कथित कारण से पूरा नहीं किया जा सकता।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि रिजर्वेड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लिए रिजर्वेड पदों के लिए क्या उसी तरह से इकनॉमिकल वीकर सैव पदों के लिए रिजर्वेड पदों हैं यदि नहीं तो क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इकनॉमिकल वीकर सैव पदों के लिए रिजर्वेड पदों नहीं हैं और न ही इस बारे में कोई विचार किया जा रहा है।

श्री जय नारायण खुंडिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि रिजर्वेड पदों के हिसाब से हरिजन जाति से संबंधित 345 सिपाही, 190 प्रधान सिपाही, 118 सहायक उप निरीक्षक तथा 15 निरीक्षको की कमी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस बैकलॉग को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां सिपाहियों की भर्ती का सवाल है वह डायरेक्ट होती है। जिस समय सिपाहियों की भर्ती की जाती है उस समय रिजर्वेड कास्टस और बैकवर्ड

क्लासिज के कैंडिडेटस को कुछ कनसै इन भी दी जाती है। भर्ती करते समय इन क्लाजि के लिए ऐजूके इन के मामले में इतनी ज्यादा गौर नहीं की जाती। इन जातियों के कैंडिडेटस की ऐजूके इन चाहे कम भी क्यों न हो फिर भी भर्ती कर लिए जाते हैं। आम जाति के लिए सिपाही की भर्ती के लिए मैट्रिक क्वालिफिके इन रखी हुई है। लेकिन रिटायर्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लिए कम ऐजूके इन भी कंसिडर कर ली जाती है। इसके अलावा छाती में भी इन जातियों के लिए एक इंच की छूट है और हाइट में भी एक इंच की छूट है। माननीय सदस्य ने जो बैकलॉग के बारे में पूछा है यह बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन सारे सदन को इस बात की खुशी होगी कि जब से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला है उसके बाद जो भर्ती हुई है उनमें कोई बैकलॉग नहीं है। जैसे रिटायर्ड कास्टस की 20 परसेंट रिजर्व इन है लेकिन हमने 25.12 परसेंट तक रिटायर्ड कास्ट कैंडिडेट के लिए है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के लिए है। उम्मीद की जाती है कि यह जो बैकलाग है इसको जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो रिटायर्ड कास्टस के कोटे के पुलिस विभाग में पद खाली पड़े हैं क्या उन पदों के लिए मंत्री जी को सुटेबल रिटायर्ड कास्टस कैंडिडेटस नहीं मिले, या कुछ

अन्य कारण है जिनकी वजह इन पदों को आज तक नहीं भरा गया?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह बैकलॉग जिस समय चौधरी तैयब हुसैन जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय से है। मैं सदन को यह आवासन देता हूँ कि जब भी भर्ती की जाएगी आज की सरकार बकायदा इस बैकलॉग को पूरा करती रहेगी।

श्री रतन लाल कटारिया: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह जो बैकलॉग है इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

प्रो सम्पत सिंह: अब ज्यों ज्यों नए पद बनते रहेंगे त्यों त्यों हम इन बैकलॉग को पूरा करते रहेंगे।

श्री परमा नन्द: अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि पिछड़े वर्ग के कोटे के हिसाब से हैड कांस्टेबल के 31 पदों की कमी है और इस कमी का कारण इन्होंने बी-1 का टैट पास न करना बताया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस कमी को किसी तरह से पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की परमो इन के लिए बी-1 का टेस्ट पास करना जरूरी है। और वह टेस्ट ओपन होता है। इसी वजहसे सरकार इन लोगों

की परमोान नहीं कर पा रही है। मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि कोई कांस्टेबल हाईकोर्टमें चला गया था कि वह परमोान नहीं है बल्कि टैस्ट है, इसलिए इसमें रिजर्वेान नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेा दिए कि इसमें रिजर्वेान नहीं होगी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेा एि कि यह टैस्ट है इसलिए इसमें टैस्ट पास करने के बाद ही परमोान मिलेगी। इसी वजह से यह कमी अभी तक बनी हुई है।

श्री भाग मल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय का इस बारे में फैसला क्या है और दूसरे क्या उच्च न्यायालय के आदेा को हमारी पड़ोसी स्टेट पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी लागू कर रही हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कई बार तो कोर्ट संबंधित व्यक्ति तक ही आदेा देती है और कई बार हरेक केस में उसी तरह करने के आदेा देती है। इस केस में कोर्ट ने हरेक केस के लिए यही डायरेक्ान दी है कि यह प्रमोान टैस्ट पास करने के बाद ही दी जाए इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटस का आदेाों को मान रही है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सारे दे 1 पर ही लागू होता है।

श्री उदय भान: ए एस आई और एस आई की भर्ती का क्या कार्टेरिया है?

प्रो० सम्पत सिंह: ए एस आई की 75 प्रति 1त भर्ती बाई प्रमो 1न और 25 प्रति 1त डायरेक्ट की जाती है और एस आई की 90 प्रति 1त भर्ती बाई प्रमो 1न और 10 प्रति 1त भर्ती डायरेक्ट होती है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पदोन्नति के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैकवर्ड क्लासिज और रिजर्व्ड कास्ट के कैंडिडेट्स क्या इसलिए पास नहीं हो पाते क्योंकि विभागीय परीक्षा लेने वाले वर्ण जाति के कुछ लोग उनके प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं? क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगे?

प्रो० सम्पत सिंह: इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। यह सभी जातियों की सरकार है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने यदि 100 लडकें होते थे और उन 100 लडकों में हरिजनो का कोटा 20 प्रति 1त होता था तो पहले 80 लडके वर्ण जाति से लेकर बाद में 81वां नम्बर कोटे

का रखते थे यानि कि पहले 80 लडके स्वर्ण जाति से और बाद के 20 लडके रिड्यूल्ड कास्ट से भर्ती किए जाते थे चाहे रिड्यूल्ड कास्ट का लडका एम0 ऐ0 क्यों न हो, चाहे ओपन लिस्ट में क्यों न आता हो, उसे सिर्फ रिजर्वे इन कोटे में ही रख कर लगाया जाता था। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी इसी तरह से लिस्ट बनाई जाती है?

प्रो० सम्पत सिंह: इस तरह से लिस्ट नहीं बनाई जाती।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासिज की रिजर्वे इन पालिसी लागू करने के लिए क्या विभागो ने रोस्टर बनाए हुए है? अगर बनाए हुए है तो क्या उसी हिसाब से उनकी जगह और उनकी सीट उन्हें मिल जाती है या नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: इसके लिए सैपरेट नोटिस की आवश्यकता है।

Grant of fodder under Drought Relief Programme

***338. Shri Tek Chand:** Will the Minister for revenue pleased to state-

(a) the district wise amount of grant given for fodder under the drought relief programme during the period from December] 1987 to date (29-2-1988); and

(b) whether any complaint has been received by the Government regarding improper distribution of the said grant; if so, the action taken thereon?

राजस्व मंत्री (श्री सुरजभान):

(क) दिनांक 29-2-88 तक अलौट की गई सबसिडी का जिला-वार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जिला भिवानी में चारे के अनुचित वितरण बारे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जो कि जांच उपरान्त सच्ची नहीं पाई गई। लेकिन, तो गाम में सबसिडी के कुछ जाली क्लेम पकड़े गए और 20 एफ आई आर दर्ज की गई जो जांच के अधीन है।

विवरण

दिनांक 29-2-88 तक अलौट की गई सबसिडी का जिला-वार विवरण

क्रमांक	जिला	चारा सबसिडी व वाहन खर्च के लिए अलाटमेंट (रु लाखों में)	मुफ्त चारा बांटने के लिए अलाटमेंट
1	अम्बाला	5.0	..
2	भिवानी	190.00	6.00
3	फरीदाबाद	2.00	..

4	गुडगांव	20.00	2.00
5	जीन्द	12.50	2.00
6	हिसार	55.00	2.00
7	कुरुक्षेत्र	2.50	..
8	महेन्द्रगढ	90.00	2.00
9	रोहतक	5.00	..
10	सिरसा	3.00	5.00
11	सोनीपत	3.00	..
12	करनाल
	जोड	388.00	19.00

श्री टेक चन्द: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि कुछ रिक्वायर्मेंटें प्राप्त हुई हैं जो जांच उपरान्त सच्ची नहीं पाई गईं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किस केडर के अफसर ने जांच की थी और क्या विजिलेंस ने इंक्वायरी की थी या किसी आफिसर ने की थी?

श्री सुरजभान: तहसील दार ने जांच की थी और डी सी ने उसे कन्फर्म किया है।

श्री टेक चन्द: जिन अफसरों ने चारे पर सबसिडी और अन्य रियायतें दी हैं, उन्हीं अफसरों और कर्मचारियों ने इन्वेस्टीगेशन की है। इसलिए सही जांच होने की संभावना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये रियायतें किन किन लोगों ने की थीं और कब रियायतें मिली थीं, किस एजेंसी को इन्वेस्टीगेशन के लिए लिखा गया?

श्री सुरज भान: रियायतें दो तरह की थीं। तीन गावों से रियायत आई थी कि तुड़ी कम तोली गई। इन्वेस्टीगेशन के लिए जब वहां पर तहसीलदार गया तो वहां के लोगों ने बताया कि पार्टीबाजी की वजह से रियायत की गई है, जब कोई रियायत नहीं है। दूसरी रियायत यह थी कि कुछ लोगों ने बोगस क्लेम किया है। इन्होंने तुड़ी खरीदी नहीं और सबसिडी का क्लेम किया है उनके अगैन्सट एफ आई आर दर्ज है और इन्वेस्टीगेशन हो रही है।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने टेबल आफ दि हाउस पर जो स्टेटमेंट रखी है उसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फरवरी के अन्ततक कितनी सबसिडी खर्च हो चुकी है?

श्री सूरज भान: चार करोड बीस लाख रुपया सैन्टर की तरफ से मिला था, वह खर्च हो चुका है और चालीस लाख फालतू खर्च कर चुके है।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 388 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेड इन और चारे की सबसिडी के लिए दिया और 19 लाख रुपए का मुफ्त चारा सुखा पीडितों के लिए सहायता के लिए दिया गया। ये आंकड़े बड़े सराहनीय हैं लेकिन जिन सुखा पीडित लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है, क्या यह सहायता और राहत उन तक पहुंची है? इस बारे में जांच कराने का क्या तरीका है? जिस चारे की सबसिडी खुद तहसीलदार और डी सी की मार्फत बंटती है और यदि वही इस बाबत जांच करते हैं तो यह तो वही बात हुई कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बैठाया जाए।

श्री सूरज भान: मुझे अफसोस है कि इन्होंने यह बात आफिसर्ज के बारे में कही कि 'दूध की रखवाली पर बिल्ली को बैठाया जाए'। ऐसा कहना ठीक नहीं। हमारे ज्यादातर आफिसर्ज रिस्पोंसिबल हैं और साथ ही साथ रिस्पोंसिव भी हैं। कोई ित्कायत आती है तो उसकी इनवेस्टीगेंशन करते हैं। इसलिए उनके बारे में यह कहना ठीक नहीं।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जिन सुखा पीडित लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है, क्या यह

सहायता और राहत उन तक पहुंची है? इस बारे में जांच कराने का क्या तरीका है?

श्री सूरज भान: हमारे पास कोई विकल्प नहीं आया। अगर कोई विकल्प आया है तो हम देख लेंगे।

श्री कैलाश चन्द भार्गव: क्या इस सबसिडी में से जो गाएं राजस्थान से आयी थी और जो हमारी गठनालाएं हैं उन्हें भी कुछ सहायता दी गई है और अगर दी गई है तो कितनी दी गई है?

श्री सूरज भान: वहां पर सहायता दी है। जो आवारा गाएं हैं या राजस्थान से गाएं आयी हैं या इधर उधर के पशु होते हैं उन्हें भी मुफ्त चारा दिया गया है?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस बार सुखा राहत के अन्तर्गत चारे का जो वितरण किया गया है वह बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। इक्का दुक्का विकल्पों का होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई फसल आते तक यह सबसिडी इसी प्रकार दी जाती रहेगी और इसे बंद करने की तो कोई योजना नहीं है?

श्री सूरज भान: इसे बंद करने की तो कोई योजना नहीं है। इस कार्य हेतु केन्द्र से 4 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि आई थी। इसके बावजूद हमने अपने खजाने से 40 लाख रुपए की

राशि । इस कार्य के लिए व्यय की है । इस योजना को बन्द करने का अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री सचदेव त्यागी: करनाल डिस्ट्रिक्ट में चारे पर कोई सबसिडी नहीं दी गई । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि करनाल जिला को इस सबसिडी से अलग क्यों रखा गया?

श्री सूरज भान: करनाल जिला में चारे पर सबसिडी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहाँ पर चारे की जरूरत नहीं थी ।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: करनाल जिला में भी कुरुक्षेत्र जिले की तरह सुखा पडा है । करनाल में कई गऊ मालाएँ भी हैं, क्या उन गऊओं के लिए चारे का कोई प्रबन्ध किया गया है?

श्री सूरज भान: करनाल के डी सी ने चारे की सप्लाई के लिए कोई मांग नहीं की ।

श्री जय नारायण खुण्डिया: रोहतक जिला के अन्दर सुखा राहत के अन्दर कितना पैसा दिया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रोहतक के झज्जर एरिया और कलानौर एरिया के लिए कितनी सुखा राहत दी गई?

श्री सूरज भान: रोहतक जिले के लिए पांच लाख रुपए की राशि । रिवोल्विंग फण्ड के लिए दी गई और पांच लाख रुपए की राशि । सबसिडी के लिए दी गई ।

श्री लछमण सिंह कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि करनाल डिस्ट्रिक्ट को चारा सबसिडी से अलग क्यों रखा गया? क्या सबसिडी में करनाल का हिस्सा नहीं आता। करनाल में भी चारा नहीं है और किसानों ने 125 रुपया या 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वहां चारा खरीदा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सबसिडी देने का क्या काइटेरिया है?

श्री सूरज भान: सबसिडी के लिए डी सी करनाल से रिपोर्ट मांगी गई थी। डी सी करनाल ने चारे पर सबसिडी के लिए कोई मांग नहीं की इसलिए करनाल में चारे पर सबसिडी नहीं दी गई।

श्री हजार चन्द: सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कई गऊ ालाएं हैं और आजकल सर्दी में गऊएं मैदान में धूप में बैठी रहती हैं। अब गर्मी का मौसम आ रहा है और धूप में गऊओं के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि गर्मियों में गऊओं के बैठने के लिए कोई भौड इत्यादि बनवाने का कोई विचार है?

श्री सूरज भान: इस बारे में सोचा जाएगा।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सोनीपत में भी करनाल की तरह कोई सूखा राहत

नहीं दी गई। वहाँ पर ओलावृष्टी के लिए तो बहुत कुछ दिया गया है लेकिन सूखा राहत के लिए भी कुछ दिया जाएगा?

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, सोनीपत जिले के दो लाख रुपया रिवाँलविंग फण्ड दिया गया और तीन लाख रुपया सबसिडी दी गई तथा 1811 क्विंटल चारा दिया गया।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, करनाल जिला और करनाल के देहातेँ के अन्दर काफी सूखा पडा है जिस वजह से पिछली फसल में काफी कमी हुई है। वहाँ देहात के अन्दर चारे की बहुत कमी है, वहाँ भी राहत दी जानी चाहिए।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, अगर करनाल से मांग आएगी तो उस पर विचार कर लेंगे।

Allotment/Distribution of Palm Oil in the State

***311. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the district wise quantity of palm oil allotted in the State during the year 1987&88 upto 29-2-88 together with the manner in which it was distributed?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज): वर्ष 1987-88 में (दिनांक) 29-2-88 तक राज्य को 8900 मीट्रीक टन पाम आयल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वितरण के लिए अलाट किया गया था। वर्ष 1987-88 में

(दिनांक 29-2-88 तक) प्राप्त अलाटमैट का जिलावार वितरण का ब्यौरा अनुबन्ध 'ए' में दिया गया है

वर्ष 1987-88 दिनांक 29-2-88 तक की जिलावार पाम आयल की आबंटन तथा इसकी लिफटिंग की विवरणी।

क्रम	जिला का नाम	वर्ष 1987-88 में पाम आयल की अलाटमैट	वर्ष 1987-88 में पाम आयल की उठाई गई मात्रा
1	अम्बाला	890	660
2	भिवानी	600	450
3	फरीदाबाद	610	620
4	गुडगांव	800	850
5	जीन्द	770	350
6	हिसार	1080	650
7	कुरुक्षेत्र	370	280
8	नारनौल	840	440
9	रोहतक	790	550

10	सिरसा	620	490
11	सोनीपत	510	280
12	करनाल	590	1125
13	कैथल	430	330
	जोड़:	8900	7075

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने 1987-88 का ब्यौरा दिया है कि पाम आयल कितना आया और कितना कितना हर जिले ने उठाया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी डिस्ट्रिब्यूशन ठीक हुई है या ब्लैक में बिका है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, पिछली सरकार के समय इसकी फेयर डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होती थी। लेकिन हमने इस बार इसकी फेयर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए कदम उठाए हैं और इसकी बकायदा फेयर डिस्ट्रिब्यूशन हो रही है।

श्री भाग मल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि अम्बाला जिले की ऐलोकेशन 890 मीट्रिक टन थी और उठाया गया 660 मीट्रिक टन। इसी तरह से भिवानी में भी 150 मीट्रिक टन कम उठाया गया। करनाल में 590 के अगेंस्ट 1125 मीट्रिक टन उठाया गया। इसका क्या कारण है जहां ऐलोकेशन

ज्यादा थी वहां कम उठाया गया और जहां ऐलोके इन कम थी वहां ज्यादा उठाया गया है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, करनाल में जो 590 के अगेंस्ट 1125 मीट्रिक टन उठाया गया है इसमें कई बार ऐसा होता है कि पिछले महीने का कोटा उठाया नहीं जाता। उसके लिए हम एक महीने का ऐक्स्टें इन दे देते हैं। दूसरा कारण यह है कि कई बार स्टेट का कोटा लैप्स हो रहा होता है इस लिए उस कोटे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट उठा लेते हैं। ये कारण है।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, पिछले पांच सालों में करीब 50 करोड़ रुपए का पाल आयल आया। इसकी डिस्ट्रीब्यू इन की गडबड में कनफैड का एक जी एम सस्पेंड किया गया था। क्या फूड एंड सप्लाइज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कोई ऐक् इन लिया गया या नहीं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि जब सरकार के नोटिस में आया कि पाम आयल की बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही है तो मुख्य मंत्री महोदय ने रेड कंडक्ट करवाएं। यह पहला मौका है कि 12-10-87 को केवल एक दिन में 46 भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया गया।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कुल 7075 मीट्रीक टन पाम आयल उठाया गया। क्या उसमें से कुछ वापिस भी आया। दूसरा

सवाल यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पाम आयल उपभोक्ता तक पहुंचें, उसके लिए आपने कौन सा कदम उठाया है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, पाम आयल वापिस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि जो नहीं उठाता उस के लिए अगले महीने के लिए ऐक्सटेंड कर दिया जाता है। जहां तक पग उठाने की बात है, सबसे पहला पग हमने यह उठाया कि पहले यह आयल कनस्तरो में आता था और उसे हलवाईयों को सप्लाई कर दिया जाता था। अब हमने कनस्तरो की बजाय दो किलो और पांच किलो की स्माल पैकिंग से मंगवाना शुरू कर दिया है। इसके वितरण के लिए डी सी की अध्यक्षता में हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में रजिस्ट्रार कोओपरेटीव सोसाइटी, डी0 एम0 कनफ़ैड, हमारे विभाग का डी एफ सी है। हर जिले में 15 दिन के बाद मीटिंग करने का निर्देश है कि पाम आयल की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी निगरानी से करवाई जाए। इस समय इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हो रही है।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूँ कि करनाल में ज्यादा पाम आयल इसलिए तो नहीं बंटा है क्योंकि वहां पर बाई-इलैक्शन था? क्या यह बात सही है कि वहां पर ज्यादा पाम आयल इसलिए दिया गया है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: इस तरह की प्रथा इनके दिनों में रही होगी। हमारी सरकार में ऐसी कोई प्रथा नहीं है।

श्री कैला । चन्द भार्मा: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पाम आयल के वितरण के लिए मात्रा किस आधार पर तय की गयी है? क्या यह प्रति राशन कार्ड के हिसाब से है या प्रति यूनिट के हिसाब से है या राशन कार्ड में मैम्बरो की संख्या के आधार पर है? विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताएं?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र और भाहरी क्षेत्र में कोई अन्तर इस मामले में नहीं है। प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम की मात्रा तय की गई है। कोई यूनिट के साथ सम्बंध नहीं है। हर राशन कार्ड होल्डर के लिए 5 किलो की मात्रा निश्चित की हुई है।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जो कन्फैड और फूड एंड सप्लाइज विभाग के जिम्मे है, इनका काम बंटने के कारण कई खराबियां आ गयी है उनको हटाने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाये है जैसे हायर लैवल पर कोई कमेटी बनायी हो, अगर बनायी है तो कब बनायी है?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, यह विभाग जो अब मेरे पास है, पहले भाई परमानन्द जी के पास हुआ करता था। इस तरह की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए जो कन्फैड और

फूड एंड सप्लायज विभाग के कामो मे आ रही है, भाई परमा नन्द जी के समय से ही एक कमेटी बनी हुई है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक मीट्रिक टन में कितने मन होते हैं?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, यह क्विंटल के हिसाब से होता है। एक क्विंटल में अठ्ठाई मन होते हैं। आगे गुना तकीम माननीय सदस्य खुद कर लें।

श्री हीरा नन्द आर्य: जैसे उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए समितियाँ बनी हुई हैं, उसी तरह से 1986 में सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिला लैवल पर और स्टेट लैवल पर कौंसिल बनाने का प्रावधान किया था ताकि वितरण प्रणाली को ठीक किया जा सके। स्टेट लैवल पर जो कौंसिल बनी थी उसमें डिस्ट्रीक्ट एंड सै न जज होना था। क्या वह कौंसिल बना ली गयी है, अगर नहीं तो कब तक बना ली जाएगी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, वह कौंसिल नहीं, कमी न है। बकायदा भारत सरकार के कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्ट्रि एक्ट के तहत कमी न बनाने का प्रावधान है। सभी राज्यों में एक राज्य लैवल पर और एक जिला स्तर पर कमी न बनना है। जो इन्होंने कहा है कि उसमें हाई कोर्ट का जज होना

था, तो उसमें प्रेफरेंस के तौर पर यह कहा गया है कि उसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी हो सकता है और सिटींग जज भी हो सकता है। उस कमी इन में एक आदमी ऐसा होना था। यह कमी इन स्टेट लैवल पर स्टेट कन्जयूमर्ज प्रोटैक् इन कमी इन बनेगा। हमारे डिवीजन हैडक्वार्टर्ज अम्बाला और हिसार में सबसे पहले बनेगा। उसकी बकायदा स्वीकृती हो चुकी है। कमी इन बनाये जाने के बारे में मुख्य मंत्री महोदय के जल्दी आदे 1 जारी होने वाले है।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो डिस्ट्रिब्यू इन सिस्टम है, इसमें कनफैड या होल सेल डीलर को कितना मुनाफा मिलता है और रिटेल डीलर को कितना मिलता है? क्या रिटेल डीलर का मुनाफा कम होने की वजह से छोटे लैवल पर करप् इन नहीं बढ रही है? अगर ऐसा है तो उसको मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, 37.80 रुपए में दो किलो के हिसाब से भारत सरकार से यह मिलता है और 1.20 रुपए एडमिनिस्ट्रटिव चार्जिज़ है और कुछ मुनाफा लेकर 39.00 रुपए में रिटेलर या डिपो होल्डर को दिया जाता है। रिटेलर या डिपो होल्डर चालीस रुपए में दोकिलो बेचता है यानी एक रुपया किलो पर। यह कोई ज्यादा मुनाफा नहीं है। स्पीकर साहब, रिटेलर और डिपो होल्डर का मुनाफा बढ़ाने के लिए सरकार ने

नोटिस में बात आई है और इसको दुबारा निरीक्षण के लिए पांच तारीख को एक मीटिंग होने वाली है।

कामरेड हरपाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपाकरेगी कि जो लागे सस्पेंड हुए है वे किस रैंक के थे और क्या उनके उपर जो अफसर थे वे भी पकड़े गए थे? स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि पिछली सरकार के समय में जो करण था वह अब दूर कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उन अफसरों को बदल दिया गया है या उन अफसरों की अब नीयत ठीक हो गई है, या दस बारे में कौन सी कार्यवाही की गई है जिसके कारण अब अफसर ईमानदार हो गए हैं?

श्री अध्यक्ष: हरपाल जी आपने एक ही बार में चार क्वै चन कर दिये है। एक ही क्वै चन आपको करना चाहिए।

श्री सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, श्री हरपाल सिंह जी की जिज्ञासा बिल्कुल जायज है। इसमें डिपो होल्डर्स या नीचे के अधिकारी नहीं है। कन्फैड के औफिसर्स है जो सस्पेंड किए है, अगर मैम्बर साहब लिस्ट देखना चाहें तो देख सकते है। सदन में 46 आदमियों का नाम पढने में काफी समय लगेगा। स्पीकर साहब, औफिसर्स को बदलने की जरूरत नहीं केवल औफिसर्स को बदलने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। औफिसर्स तो सरकार की नजर को समझते हैं। कहावत भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर सरकार

की नजर को समझ लिया है और मैं विवास के साथ कह सकती हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है।

Haryana Tanneries Limited, Jind

***325. Shri Parma Nand:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether the Haryana Tanneries Limited, Jind has been closed;

(b) if so, the number of employees who have become jobless; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to absorb the employees, as referred to in part (b) above, in other departments.

उद्योग मंत्री (डा किरपा राम पुनिया):

(क) इस समय यह इकाई बन्द है।

(ख) कम्पनी के रोल पर 157 कर्मचारी थे। श्रमायुक्त हरियाणासे आवयक स्वीकृती प्राप्त करके 98 कर्मचारियों की जबरी छुट्टी (ले-आफ) कर दिये गये है। कम्पनी ने 21 और कर्मचारियों की ज्वरी छुट्टी हेतु स्वीकृती मांगी है।

(ग) इस इकाई के मामलो तथा कार्य-प्रणाली जो कि घाटे में जा रही है, का अध्ययन हाई पावर्ड कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भीघ्र आने की सम्भावना है।

श्री परमा नन्द: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस उद्योग को लगाते समय कितनी फिक्सड कैपिटल रखी गई थी और कितनी वर्किंग कैपिटल रखी गई थी और जो वर्किंग कैपिटल रखी गई थी क्या वह मिलती रही थी?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस उद्योग का बिगनिंग ही अनफारचुनेट रहा। जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनी थी वह 122.69 लाख की थी और इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से दो हजार स्किन पर-डे पर तैयार करने की कैपेसिटी मन्जूर हुई थी लेकिन जो कंसलटेंट थे उन्होंने ऐडवांस कैपेसिटी को बढ़ा लिया। उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया को इसकी कैपेसिटी ऐनहांस करने के लिए लिखा लेकिन भारत सरकार ने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। यह युनिट जब से लगा है घाटे में चल रहा है और अब भी घाटे में ही है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह तथ्य है कि जीन्द की टैनरी से चमड़े का जो बेहतरीन माल बनकर मार्किट में जाता था, वह हाथों हाथ बिक जाता था लेकिन फिर भी वह टैनरी घाटे में गई? इसके क्या कारण हैं?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मुख्य तौर पर इसके दो तीन कारण इस प्रकार हैं। सब से पहला कारण तो यह था कि उसकी लाइसेंसिंग कैपेसिटी कुछ थी, इंस्टाले इन के वक्त

कुछ और हो गई और उसके लिए फायनेंशियल इंस्टीच्यूट ने वर्किंग कैपीटल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद काफी देर तक भारत सरकार के साथ जदोजहद चलती रही। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रोजैक्ट 1976 में चालू किया गया था और 1982 में जहां तक मुझे पता है इसकी ऐनहांसमेंट हुई। तब तक काफी घाटा हो चुका था। इसके अलावा रा-मैटीरियल भी कम ही मिलता था। लेकिन मेन डिफीकल्टी फायनेंससिज की ही रही, जिसकी वजह से यह प्रोजैक्ट घाटे में रहा।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, 1976-77 में दो बार इस प्लांट को वर्किंग कैपीटल के लिए 20 लाख रुपया मिला था और उसमें से 15 लाख रुपया दूसरे अन्य कामों पर खर्च कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस लोस का कारण यह तो नहीं था?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, सरकार के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें सरकारी मुलाजिमों को तनखाह भी देनी होती है। इसलिए सरकार किसी भी काम की प्रायर्टी को देखते हुए किसी भी फंड को किसी दूसरी जगह पर यूज कर सकती है। जैसा यहां किया गया। इस तरह हालात चलते रहे।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त इस प्रोजैक्ट की प्रोपोजल बनाई

गई क्या उस वक्त मुनाफा देखते हुए बनाई गई थी और जब यह प्रोपोजल सरकार के सामने आई तो क्या उस वक्त भी मुनाफे को ध्यान में रखा गया था?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इनकी बात सही है कि जिस वक्त यह प्रोजैक्ट बनाया गया था उस वक्त यह उम्मीद थी कि ये प्रोजैक्ट इकोनोमिकली वायेबल होगा और मुनाफे में चला जाएगा।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के ये जो उपक्रम घाटे में जा रहे हैं, इनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, वह कब से बनाई गई है? इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूँ कि जो 98 कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेज दिए गये हैं, उनको छुट्टी पर भेजने की कार्यवाही कब भुरु हुई थी? इस इकाई में घाटा होते हुए भी वहां पर चेयरमैन की नियुक्ति की गई। उस चेयरमैन पर सरकार की तरफ से प्रतिमाह पे व पर्स पर कितना खर्चा किया गया था?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, हाई पावर्ड कमेटी दिसम्बर, 1987 में बनी थी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही एक सब कमेटी भी बनाई है ताकि ऐसे यूनिट्स को काफी डिटेल में ऐग्जामिन करें। उसके

चेयरमैन बाबू मूल चन्द जी जैन है। इस बारे में काफी डिटेल में स्टडी किया गया है और उसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। जहां तक कर्मचारियों को ले-आफ करने का सवाल है यह कार्यवाही 1 जून, 1987 से बन्द है और अब जनवरी 1988 को ले-आफ करने का प्रस्ताव रखा था कि इन मुलाजमों को ले-आफ कर दिया जाये परन्तु 15 फरवरी से 30 मार्च तक ले-आफ करने की इजाजत मिली है। अब वे ले-आफ है।

श्री परमा नन्द: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि इस युनिट का फेल होने का कारण वर्किंग कैपिटल का न मिलना है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब सरकार लोगों को रोजगार देने का वायदा करती है तो क्या ऐसे युनिट्स को एक और मौका देकर अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाकर दोबारा चलाने का सरकार विचार रखती है या नहीं?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हम काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। कमेटी ने अपनी अंतिम रिकमैन्डे टान देनी है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जो ऐम्पलाई वहां लगे हुए हैं, वे आजकल हडताल पर हैं और वे मुझे मिले भी थे। क्या सरकार उस फैक्ट्री के बन्द होने के कारण जो

कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं उनको किन्हीं दूसरी जगहों पर रोजगार देने का विचार रखती हैं क्योंकि कई तो 8-8 सालों से काम कर रहे हैं और वे ओवर एज भी हो चुके हैं?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, स्ट्राइक के बाद उनको कहीं नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 98 एम्पलाईज को लेबर कोर्ट से परमिशन लेकर ही ले-आफ किया हुआ है और 21 एम्पलाईज को ले-आफ करने के लिए हमने लेबर कोर्ट को लिखा हुआ है। अभी तक उसकी परमिशन नहीं आई है। लेकिन सभी मुलाजिमों के बारे में क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, इस बारे में अंतिम निर्णय कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही होगा।

श्री हीरा चन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस इकाई में जिन कर्मचारियों को ले-आफ दिया गया है क्या उनको वापिस नौकरी में लि लिया जाएगा, क्या मंत्री जी इस बात को अर्थोत्तर करेंगे?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों द्वारा एक ही बात को बार-बार दोहराना मैं उचित नहीं समझता। मैंने इस बारे में पहले ही अर्ज कर दी है कि इस युनिट के बारे में केवल हाई पावर्ड कमेटी अध्ययन कर रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस विषय में सरकार कोई अंतिम निर्णय लेगी।

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या 1 जून, 1987 के बाद इस इकाई में कोई नियुक्त किया गया है अगर किया गया है तो उस की पे व वर्कज पर कितना पैसा खर्च हुआ है?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, उस यूनिट में लगभग 2 लाख रुपए महीने के चेयरमैन, एम डी और दूसरे स्टाफ पर खर्च होते हैं। यह बात भी ठीक है कि जब तक कोई यूनिट जिंदा है और उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक उस यूनिट में चेयरमैन, एम डी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ रखा जाता है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस यूनिट के बन्द होने से कितने हरिजनो को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ है यानी कितने हरिजन ले-आफ किए गए हैं?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, कोई ज्यादा फर्क नहीं पडा है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसी सै ान के दौरान श्री दुर्गा दत्त अत्री द्वारा पूछे गए एक सवाल के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जब तक इस यूनिट के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तक इस यूनिट के किसी भी कर्मचारी की छुटटी नहीं की जाएगी

लेकिन आज मंत्री जी ने बताया है कि इस यूनिट के 98 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है और 21 कर्मचारियों की छुट्टी करने के बारे में अभी फैसला लिया जाना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस यूनिट से ऐडमिनिस्ट्रेटिव लैवल के कितने लोगो को नौकरी से निकाला गया है?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उन कर्मचारियों को ले आफ किया गया है न कि नौकरी से हटाया गया है और यदि यह यूनिट चालू करना है तो सारे वे कर्मचारी वापिस ले लिए जाएंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, यह यूनिट 1976 में लगाई गई थी। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 1976 से लेकर 1987 तक इस यूनिट की कितनी बार जांच करवाई गई और इस यूनिट को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

डा किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस यूनिट की तीन बार जांच करवाई गई। एक बार 1982 में, दूसरी बार 1984 में और तीसरी बार आज कल चल रही है।

श्री परमा नन्द: स्पीकर साहब, जिन 98 कर्मचारियों को ले आफ किया गया है वे सभी प्रोडक्शन ब्रांच से संबंध रखते थे। मैं आपको माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चेयरमैन,

एम डी और जो दूसरे रखे हुए थे क्या उनके खर्चों को कम करके इस यूनिट को घाटे को कम करने की कोशिश की गई है?

डा० किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, जिन कर्मचारियों को ले आफ किया गया है मेरे पास उनकी लिस्ट है लेकिन इस लिस्ट को पढ़ना उचित नहीं होगा क्योंकि इसके पढ़ने में काफी समय जाया हो जाएगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिन जिन कर्मचारियों के बारे में यह समझा गया कि इस वक्त इनकी जरूरत नहीं है केवल उन्हीं को ले आफ किया गया है और जिनकी जरूरत थी उनको ले आफ नहीं किया गया।

श्री दुर्गादत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब तीन बार इस यूनिट की जांच करवाई गई तो उन जांच रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार ने इस यूनिट के घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हे बताना चाहूँगा कि इस उद्योग की 2 या 3 बार जांच कराई गई। पहली बार 1982 में इसकी जांच करवाई गई थी। उस वक्त यह मामला फाईनेंसियल इंस्टीच्यूट के सामने ले जाया गया था ताकि और फाईनेंस देकर इस युनिट को रि-हैबिलिटेड किया जा सके। फाईनेंसियल इंस्टीच्यूट पैसा देने से इंकार करते रहे। फिर 1984 में कैबिनेट की सब कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि इस यूनिट को क्लोज करना ही उचित रहेगा। परन्तु गवर्नमेंट द्वारा उस रिपोर्ट

पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इसकी जांच अब भी चल रही है। हम ने हर संभव कोशिश की है कि इस यूनिट को पैसा दिलवाया जाये। सरकार ने स्वयं गारंटी देकर बैंक से पैसा दिलवाया भी। हमने तो अपनी तरफ से हर मौके पर इस युनिट को रिहैबिलिटेड करने की कोशिश की है ताकि इस यूनिट का काम ठीक प्रकार से चल सके परन्तु अभी तक इसका काम ठीक प्रकार से चल नहीं पाया है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है कि 98 कर्मचारी इस यूनिट से निकाले गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निकाल गए कर्मचारी किस स्तर के हैं और उनको निकालने के लिए क्या काइटेरिया अपनाया गया है?

डा० किरपा राम पुनिया: अध्यक्ष महोदय, एक जैसी ही सप्लीमेंटरी बार बार पूछी जा रही है। मैं सभी सदस्यों को निकाले गए कर्मचारियों के पद और नाम पढ़ कर सुना देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप रहने दें, क्योंकि इस में समय ज्यादा लगेगा।

Replacement of Faridabad Complex Administration

by Municipal Committee

***489. Shri Harnam Singh:** Will the deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace Faridabad

Complex Administration by a Municipal Committee; if so, the details thereof?

उप मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): जी नहीं ।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, लोकदल की सरकार बनने के बाद हरियाणा सरकार ने सारी म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव करवाये है लेकिन फरीदाबाद जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहां से भी लोक दल का ही एम एल ए चुन कर आया है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि अभी तक वहां पर इलैक्ट्रान क्यो नहीं करवाये गए है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारे में पहले भी सवाल आ चुके है और उनके जरिए इस संबंध में पहले ही काफी सप्लीमेंटरी पूछी जा चुकी है तथा उनका स्पष्ट उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा चुका है । हमने ऐक्ट के अन्दर संशोधन किया है कि 14 जनवरी, 1990 तक ऐक्ट के मुताबिक की गई व्यवस्था के अनुसार वहां पर काम चलेगा और उसके बाद सरकार की यह पक्की राय है कि वहां पर इलैक्ट्रान करवा दिए जाएंगे ।

श्री योगे । चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी उपयुक्त मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर मौजूद ऐक्ट के अनुसार जनवरी 1990 तक ही व्यवस्था चलेगी । मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐक्ट में दुबारा संशोधन करके वहां पर 1990 से पहले चुनाव नहीं करवाये जा सकते?

श्री बनारसी दास गुप्ता: इसमें और कोई सं तोधन करने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद हरियाणा प्रान्त का सबसे बडा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर सबसे ज्यादा झोपडियां है, पोल्यू टन भी वहां पर सबसे ज्यादा है और इसी प्रकार से दूसरे ऐसे बहुत से मसले है जो दूसरे भाहरो में वहा की अपेक्षा कम है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर सरकार जल्दी चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का जिक्र डा० हरनाम सिंह जी ने अपने सवाल में किया है इन सभी समस्याओं के बारे में ही सरकार ने यह सं तोधन किया है कि वहां पर कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो इन सभी समस्याओ को हल कर सके। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

15:00 बजे

श्री अध्यक्ष: अब क्वै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर

**Supply of Essential Commodities Direct to
Ration Depots**

***524. Shri Shiv Parshad:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply essential commodities like Palm oil, cloth etc. direct to the Ration Depots in the State instead of through CONFED. if so, the time by which it is likely to materialize?

खाद्य एवं पूर्ती मंत्री (श्रीमती सुशमा स्वराज): नही ।

T.A./D.A. drawn by Minister and Ministers of State

***521. Shri Balbir Pal Shah:** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of T.A./D.A drawn by each of the Minister and Ministers of State during the period from 21-6-87 to 15-3-88

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता बिल दिनांक 21-6-1987 से 15-3-1988 तक ।

क्र० न० नाम व पद	कुल रुपये
श्री देवी लाल, मुख्य मंत्री	19397.50
श्री बनारसी दास गुप्ता, उप मुख्य	22895.50

मंत्री	
मंत्री	
श्री वीरेन्द्र सिंह	6416.00
डा0 के आर पुनिया	8123.75
श्री सूरज भान	13080.00
श्री सम्पत सिंह	12960.00
श्री खुर पीद अहमद	4970.00
श्री हुकम सिंह	4500.00
श्री राम बिलास भार्मा	5358.75
डा0 कमला वर्मा	5117.50
राव लक्ष्मी नारायण	4575.00
श्री औम प्रकाश भारद्वाज	3750.00
श्रीमती सुशमा स्वराज	1367.00
श्री परमा नन्द	4521.00

राज्य मंत्री

श्री रघुबीर सिंह	8120.00
श्री धर्मवीर	7293.25
श्री सुभाश कटियाल	5810.00
श्री सम्पत सिंह	2250.00
श्री अजमत खान	5650.00
श्री मनफूल सिंह	6413.00
श्री महा सिंह	4670.00
श्री नर सिंह	3000.00
श्री सीता राम सिंगला	4819.00
श्री नरवीर सिंह	4222.00

तारांकित प्र न एवं उत्तर

E.S.I. Hospitals & Dispensaries

69. Shri Vasu Dev Sharma & Shri Hira Nand Arya:

Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state the total number of Hospitals/Dispensaries, Separately, sanctioned in the State under the E.S.I./Scheme togetherwith the number and name of such Hospitals/Dispensaries which are under construction as at present?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा० रघुबीर सिंह):

1. स्वीकृत ई एस आई अस्पतालो की संख्या : 5
2. स्वीकृत ई एस आई डिस्पेंसरियों की संख्या : 68
3. निर्माणाधीन अस्पतालो की संख्या तथा नाम : 2
 - 3.1. 200 बिस्तर ई एस आई अस्पताल बल्लभगढ (फरीदाबाद)
 - 3.2. 50 बिस्तर ई एस आई अस्पताल भिवानी
4. निर्माणाधीन डिस्पेंसरियों की संख्या तथा नाम : कोई नहीं

63. Shri Raghu Yadav: Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any memorandum regarding creation of new districts in the State has been received by the Government since 1st January, 1988:

(b) if so, a copy thereof be placed on the Table of the House; and

(c) the action, if any, taken thereon?

राज्य मंत्री (श्री सूरजभान)

(क) जी हां। एक ज्ञापन नागरिक परिशद रेवाडी से दिनांक 14-3-88 को प्राप्त हुआ।

(ख) उसकी प्रति बतौर अनुबन्ध 'ए' सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ग) ज्ञापन सरकार द्वारा गठित जिला पुनर्गठन कमेटी के सम्मुख विचार हेतु उचित समय पर रख दिया जाएगा।

ANNEXTURE 'A'

नागरिक परिशद, रेवाडी

मुख्य कार्यालय: आर -256 माडल टाउन, रेवाडी

कमांक 315

दिनांक 29-2-88

To

The Chairman

Distt. Re-organising Committee, Haryana.

Chandigarh.

Subject: Formation of New Distt. of Rewari-

(a) Removal of Regional Imbalances.

(b) Redressal of Revenge.

Historic city of Rewari, biggest meter gauge Rly. Junction of Asia, Land of Heroes like Hemu Bhargava of 1st Battle of Panipat (1556), Rao Tula Ram a Martyr of 1st war of independence of 1857, a nursery of brave soldiers since the

time immoral, has been a eye sore to Foreigners for the patriotic zeal of its people.

In Marathe time it was a full flaged & prosperous distt. was known as Sarkar-e-Rewari.

in the first war of independence 1857, Rao Tula Ram with Nawab of Jhajjar & Raja of Ballabgarh tried to expel the British out of their mother-land. Both, the Nawab & Raja ware hanged publically while Rao Tula Ram, had to meet the same fate as Bahadur Shah Jaffar & dies as a martyr:-

Dam luck & the help or traitors helped the British to recapture the region & to re-bind us is slavery for other 90 years.

Taking revenge, the British Tore our Bosam, prized the Traitors Rajas with the gift o pargna of Bawal to the Nabha Ruler. To rule ruthlessly the rest of Rewari area, merged it with Gurgaon under their direct control.

As if not to lag behind, we were kept neglected & backward by our own people after independence. In fact, it has been one of the most neglected areas.

It's population of 80000 is more than that of both other Sub-Divisional towns of Narnaul & Mohindergarh.

Not to speak of Engineering or Medical Colleges, it has no Govt. Degree College or a Polytechnic while both the other sub-divisions have one each post graduate Govt. College. We have only one Degree College at Bawal & that is also a taken over one.

Further details of regional imbalances as compared to other areas not only of this area but of Haryana can be quoted in details at the spot.

Even at present it is the centre of Trade & Industries of South West Haryana.

(i) Its copper & brass utensils are sent to far off places like Bombay & Calcutta.

(ii) It has a modern grain market & handles the grain trade of some parts of Rajasthan even.

(iii) Well-knit bus service, nearly 100 buses leave for Delhi and much more to other places including other states.

(iv) Being the biggest meter gauge Rly. Junction, it is connected with all the cities of India.

(v) Revenue income of the area excels that of both the other Sub-Divisions of Distt. taken together even.

(vi) Nearly 75% Distt court cases in Distt courts of Narnaul are of this Sub-Division.

(vii) Due to the enterprise of our people, we have 3 degree & 2 training colleges, 2 Girls & 7 Boys High schools (All Recognised) besides 5 Govt. Senior Secondary Schools, 58 High Schools, 61 Middle Schools & nearly 300 Primary Schools in this Sub-Division.

(viii) Though backward area for industries, it has become a very busy centre of industrial Enterprises,

Dharuhera a tiny village has developed into a busy and flourishing centre of industries.

Bawal is sure to develop as it has recently been declared backward.

(ix) It has export potential too. Slate stones & stone slabs of chances of its further development if it is declared a Distt. Some markets of Delhi can find a proper place here by its development.

(x) It is in the National Capital Region & there are sufficient chances of its further development.

(xi) Being the heart of South West Haryana, known as the capital of Ahirwal, creation of Distt will be emotional, moral, economical, educational & patriotic booster for the people of this region.

(xii) It is a centre of business for the adjoining areas now included in Rohtak & Gurgaon Distt. These areas have emotional, social, cultural affiliation with Rewari than to their Distt. quarters.

(xiii) With the completion of S.Y.L. this district will be a grainary of Haryana.

The areas adjacent as mentioned above can be merged with Rewari are:-

(i) Kosli Tehsil of Rohtak which has 10 M.L.As & will be reduced to 9 to be better administered.

(ii) Machhrauli area of Jhajjar Tehsil

(iii) Pataudi & Tauru constituencies of Gurgaon Distt.

If fact traders of these areas have more business contacts with Rewari than with other centres.

Hundreds of students of these areas come here for college education.

These areas are nearer to Rewari than their Distt head quarters.

Thus the proposed Rewari District will have under noted Tehsils:

1. Rewari
2. Bawal
3. Pataudi
4. Kosli

Plus proposed tehsils of Tauru & Jatusana.

It will comprise six constituencies equal to those of Sonipat & will have more population than some other districts of Haryana.

Mohindergarh Distt can be compensated with the inclusion of Loharu Sub-Division. In fact half the constituency of Loharu comprises a portion of Mohindergarh Distt.

It will not be out of place mention that it was due to personal ambitions & gains of some people that Dadri Tehsil of Mohindergarh Distt. was taken away for creating District of

Bhiwani & Rewari was merged into Mohindergarh in early seventies. Thus our interest & claims of Distt were ignored & we were let down by our own people *who had to be discordest by us.*

Surely the present Govt. will give us long awaited justice. avenge for the Revenge of our Foreign Rulers, Redress the neglect & apathy of our own people, remove this Regional imbalances and *announce with a bloc & loud voice*, Like that of declaring a holiday on 23rd Sept. as Haryana Heroes and Martyrs Day, the formation of District of Rewari in this Budget session itself.

On behalf of the people of the region.

Yours Faithfully

SD/-प्रधान

नगरपालिका, रेवाडी।

Haryana Brewerles, Murthal

64. Shri Raghu Yadav: Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the yearwise profit earned or loss suffered, if any, by the Haryana Brrewerie, Murthal (Sonepat) during the years] 1984-85, 1985-86 and 1986-87; and

(b) the reasons for the diminishing of profit/loss, if any?

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क) हरियाणा ब्रूवरिज लिमिटेड मूर्थल पिछले तीन वर्षोंसे लाभ में जा रही है, उसका लाभ निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कर से पहले लाभ	कर कटौती के पश्चात् लाभ
1984—85	42.81	32.81
1985—86	54.02	22.02
1986—87	16.02	7.02

(ख) उपक्रम के प्रबन्धकों ने, कर कटौती के पश्चात् लाभ में कमी होने के निम्न कारण बताए हैं:—

(1) वर्ष 1985—86 के लिए डेप्रीशियेशन का प्रावधान 13.46 लाख रुपये था जबकि वर्ष 1984—85 में यह प्रावधान 9.57 लाख रुपये था।

(2) वर्ष 1985—86 में आयकर का प्रावधान 32 लाख रुपये था जबकि वर्ष 1984—85 के लिए यह प्रावधान केवल 10 लाख रुपये था।

(3) उत्पादित मूल्य में वृद्धि होना तथा कम्पनी द्वारा कठिन मुकाबले का सामना करना।

(4) वर्ष 1985—86 में डेप्रीशियेशन 13.46 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1986—87 में 15.03 लाख रुपये हो गया।

(5) जैसा कि कम्पनी ने डिवैचरंज् इ ू नवम्बर, 1985 में निकाला जिसके कारण वर्ष 1985-86 में ब्याज का प्रावधान 31.32 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1986-87 में 41.46 लाख रुपये हो गया।

(6) वर्ष 1986-87 में मजदूरी तथा वेतन में 12.10 लाख रुपये की बढ़ौतरी हुई। यह बढ़ौतरी चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन मानों में परिपोषण के कारण हुई है।

(7) चूंकि उत्पादन की बिक्री ऋतु पर आधारित है और स्वभाविक रूप से उत्पादित पदार्थ अपनी भौलफ लाईफ तक ही सीमित है इसलिए योजनाबद्ध वाल्यूम को पूर्ण रूप से काम में नहीं लाया जा सका।

उत्पादन दामों में हुई वृद्धि के मुकाबले समानान्तर रूप से बीयर के विक्रय मूल्य में वृद्धि इसलिए नहीं की गई क्योंकि बाजार में इसके भोयर की कीमत को गिराना नहीं था। वर्ष 1987-88 में इस स्थिति में सुधार हुआ है और बीयर के विक्रय मूल्य में की गई वृद्धि से बड़े हुए उत्पादन दामों का ठीक तरह से समंजन हो गया है।

Target achieved by Housing Board

68. Shri Raghu Yadav: Will the Minister for State for Housing be pleased to state-

(a) the financial and physical target achieved by the Haryana Housing Board during the last five years; and

(b) the administrative charges incurred by the said Board during the said period?

आवास राज्य मंत्री (श्री सुभाश चनद कटियाल):

(क) वास्तविक उपलब्धियां वित्तीय उपलब्धियां (कायों, भूमि, प्रासासकिय व ब्याज आदि पर राजकीय खर्च)

कुल नम्बर 1624 मकान 5670.86 लाख रुपये

(ख) 482.36 लाख रुपये

Industries having head officers outside the State

70. Shri Kundan Lal Bhatia: Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) whether there are any industries in the State which have their head offices outside the State and send their manufactured goods on consignment basis without paying any tax to the State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to prohibit these industries from having their head offices outside the State together with the time by which a decision in the matter is likely to be taken?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) जी हां। लेकिन जहां कहीं भी हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 की धारा 9 के अधीन कर देय है, वसूल किया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री हीरा ननद आर्य: स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था जिसमें लिखा है कि केन्द्रीय मंत्री ने एक अधिकारी को धमकी दी थी। जिसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों में सनसनी फैली हुई है। उसका क्या हुआ।

Mr. Speaker: Arya Sahab, that is under consideration.

श्री कैलाश चन्द भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी 22 तारीख को एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का दिया था, उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: Sharma Sahib, your short notice question is also under consideration.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कैथल क्षेत्र के गांव बरोट के किसानों के अत्यधिक बिजली प्रभार वसूल करने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Call Attention Motion No. 8 from Shri Surinder Kumar Madan, M.L.A. regarding realizing of excess electricity charges from the farmers of village Brout of Kaithal area. I admit it. Shri Madan may read his notice and the Minister concerned may make the statement there after.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि कैथल क्षेत्र के गांव बरोट के किसानो को लूटा जा रहा है। उनसे बिजली के बिलो पर 100 रुपये तक अतिरिक्त राशि ली जा रही है। इस संबंध में किसानो में भारी रोश तथा असंतोश व्यापत है। इसलिए सरकार इस मामले में तथा उक्त बिलो पर की जा रही अधिक वसूली को रोकने की ओर ध्यान दें।

वक्तव्य

(1) सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मदान साहब ने अपनी काल-अटेंशन नोटिस में कहा है कि किसानो को लूटा जा रहा है। स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड सरकार का बनाया हुआ है और वह एक स्टैच्यरी बोडी है। लुटाई तो डकैत किया करते है। इसलिए इस भाब्द पर मुझे आपत्ति है।

Now I make the statement.

हरियाणा राज्य बोर्ड ने बिजली देने के निमित्त अपने कार्यालय आदे 1 दिनांक 31-12-1987 द्वारा बिजली आपूर्ति के भातों के भात नं0 22 में सं गोधन करके तथा प्रतिभूति (सिक्योरिटी) जमा करने की दरों में सं गोधन करके प्रतिभूति जमा तथा बिजली के मीटरों के लिए सिक्योरिटी जमा कराने की दर बढ़ा दी थी। घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मामले में टैरिफ (दर) में सं गोधन ओर मासिक आधार से द्विमासिक आधार पर बिजल बनाने के कारण, बिजली के बिलों के सम्भव भुगतान न करने के मुकाबले जमा प्रतिभूति को अपर्याप्त समझा जाता था इसलिए इस सं गोधन की आव यकता महसूस की गई। इसी प्रकार बिजली मोटरों के लिए प्रतिभूति जमा में सं गोधन की आव यकता मोटरों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

पेहवा परिचालन मण्डल द्वारा गांव बरोट के किसानों से ली जा रही अतिरिक्त धनराशि 1 बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुसार है। उपभोक्ताओं से इस तरह की वसूली पूरे राज्य में की जा रही है।

दरों में सं गोधन के परिणामस्वरूप घरेलू आपूर्ति को बिजली प्रदान करने के लिए जमा प्रतिभूत की दरों में यह वृद्धि 1 किलोवाट लोड तक 10 रुपए प्रति किलोवाट तथा 1किलोवाट से ऊपर के लिए यह वृद्धि 15 रुपए प्रति किलोवाट तक है। वाणिज्यिक बिजली आपूर्ति के लिए यह वृद्धि किलोवाट लोड तक 20 रुपए तथा 1 किलोवाट से ऊपर के लोड के लिए यह वृद्धि 50

रुपए प्रति किलोवाट है। कृशि सम्बन्धी आपूर्ति पूरे राज्य में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओ से जमा प्रतिभूति के सं गोधित दरों की वसूली जाती है। बोर्ड के निर्देशानुसार अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए उपभोक्ताओ को एक महीने का नोटिस दिया जाना है तथा ऐसा न करने पर उपभोक्ताओ की बिजली आपूर्ति को काटा जाना है। उपभोक्ताओ को असुविधा से बचाने के लिए धनराशि को बिलों के माध्यम से चार्ज किया जा रहा है। तो भी उपभोक्ताओ द्वारा बिलों के भुगतान की पूरी धनराशि को एक मु त अदा करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अब यह फैसला किया गया है कि उपभोक्ता अब अपने बिलों का भुगतान जून तक तीन बराबर किस्तों में कर सकते हैं तथा उनके कर्नैक्शन इस कारण उस अवधि तक नहीं काटे जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्या इस सिक्योरिटी पर इन्टरैस्ट दिया जायेगा? सिक्योरिटी किसानों की धरोहर है, ईमानत होती है इसलिए क्या बिजली बोर्ड उस पर ब्याज देगा या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अभी ऐसा कोई विचार अन्दर कंसीड्रेशन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, सिक्योरिटी के लिए तो अलग से नोटिस जाना चाहिए। मेरे पास यह बिल मौजूद

है। इस बिल के अन्दर कहीं नहीं लिखा गया है कि किस किसलिए यह पैसा लिया जा रहा है। किसान तो अनपढ़ है इसलिए उसे बताया जाये कि यह पैसा किसलिए लिया जा रहा है। पडोसी गांव में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एक ही गांव में ऐसी क्यों किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: बिल से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। नोटिस जरूर दिया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो मेरे नोटिस में लायें, जो भी कमी होगी उसे दुरुस्त कर दिया जायेगा।

(2) कृषि राज्य मंत्री द्वारा जिला भिवानी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुंडी से चने की फसल के क्षतिग्रस्त होने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Minister of state for Agriculture will make a statement on the calling attention motion given by Shri Hira Nand Arya regarding damage of crop of gram by sundi in district Bhiwani and its adjoining areas, which was admitted on 25th March, 1988.

कृषि राज्य मंत्री(श्री बलबीर सिंह): सुण्डी चने की फसल को गम्भीर नुकसान पहुंचाती है हालांकि हरियाणा में चने की फसल पर इस कीड़े का गम्भीर प्रकोप हर साल नहीं हुआ है। किन्तु इस वर्ष मार्च महीने के मध्य में भिवानी जिले में, विशेष कर चने की पछेती फसल पर, इस कीड़े का गम्भीर आक्रमण हुआ

है। जिले में चने के कुल 71000 हैक्टेयर क्षेत्र में से 52500 हैक्टेयर पर इस कीड़े का प्रभाव पडा है। भिवानी के अतिरिक्त कई अन्य जिलो में भी इस सुण्डी का हल्का प्रभाव देखा गया है, जिससे गुडगांव, जीन्द, रोहतक और सिरसा जिलों में 1000 से 2000 हैक्टेयर तथा हिसार जिले में 5000 हैक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ है। इस वर्ष राज्य में चने के तहत कुल रकबा 2.80 लाख हैक्टेयर है जो कि सामान्य वर्ग की तुलना में केवल 40 प्रति ात है। इस वर्ष चने की कम बुआई सूखा के कारण हुई है।

भिवानी जिले में 11,12 और 13 मार्च को कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा चने की फसल पर कहीं कहीं सुण्डी देखी गई। इसका प्रभाव अधिक क्षेत्र में फैसले की आ ांका से उप कृषि निदे ाक भिवानी ने अपने फिल्ड स्टाफ को तुरन्त इस काम पर लगाया कि वह अपने अपने क्षेत्रो को समझाए और सुण्डी से प्रभावित अपने खेतो में सुण्डी मार दवाईयां एण्डोसल्फान और मोनोक्टाटोफास छिडकने के लिए उकसाये। यह कीड़े मार दवाईयां किसी सरकारी ऐजैन्सी के द्वारा खरीद कर नहीं रखी गई थी क्योंकि एकतो खुले बाजार में आम मिल रही है और दूसरा इन पर किसी सबसिडी की व्यवस्था भी नहीं है।

भिवानी जिले में इस कीड़े का प्रकोप 18 मार्च, 1988 से गम्भीर हो गया। इससे निपटने के लिए उप कृषि निदे ाक भिवानी ने दवाई छिडकने वाले 227 पम्प 17 क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों और 5 पौधा संरक्षण से संबंधित कृषि विकास

अधिकारियों के पास पहुंचवा दिये, जिससे की यह पम्प छिडकाव के लिए बिना किसी किराये के किसानों को तुरन्त दिये जा सके। कीट ना एक दवाईयों ओर पम्पो को भीघ्न प्रभावित खेतों तक पहुंचाने के लिए पांच मोबाईल सुक्वेड बना दिये गये। एक एकड में छिडकी गई दवाई की लागत 35 से 40 रुपए आती है। भुरु में तो किसानों में यह दवाई अपने खर्चे पर खरीदने के लिए संकोच था किन्तु कृशि अधिकारियों ओर कर्मचारियों के द्वारा उन्हे यह समझाया गया कि यह दवाईयां किसी संस्था से मुफ्त या सबसिडी पर नहीं मिलेगी तो किसान दवाईयां खरीदने और उनका अपने प्रभावित खेतों मे छिडकाव करने के लिए आगे आने लगे।

अपर कृशि निदे एक ने 18, 19 और 20 मार्च को भिवानी जिले का दौरा किया जिस बीच वहां के उप कृशि निदे एक ने उन्हे सारी स्थिती से अवगत करवाया। 21-3-1988 को अपर कृशि निदे एक के मुख्यालय में वापिस लौट आने पर स्थिती पर आगे विचार किया गया और उप कृशि निदे एक से सम्पर्क स्थापित करके पूछा गया कि क्या उन्हे स्थिती से निपटने के लिए किसी अतिरिक्त सहायता की आव यकता है। उप कृशि निदे एक ने जाहिर किया कि उनके पास जितने पम्प और कर्मचारी उपलब्ध है उन्ही की सहायता से वह समस्या पर काबू पा लेंगे तथा किसी अतिरिक्त सहायता की आव यकता नहीं थी।

फिर भी गुडगांव से 200 अतिरिक्त स्प्रे पम्प भिवानी पहुंचाये गये है और गुडगांव तथा करनाल से एक एक मोटर गाडी

भी वहां भेजी गई है। मुख्यालय से एक संयुक्त कृषि निदेशक भी आवेक प्रबन्ध और देख रेख के लिए भिवानी पहुंच गया है। 24 मार्च को वित्तियुक्त कृषि ने उपायुक्त भिवानी से सम्पर्क करके उन्हें सलाह दी कि कीड़े से बचाव की कार्यवाही का वह स्वयं संचालन करे और उसी दिन से फसल पर दवाई के छिड़काव की कार्यवाही की उपायुक्त भिवानी भी निगरानी कर रहे हैं। उप कृषि निदेशक भिवानी से 25 मार्च को भी सम्पर्क किया गया और उसने स्पष्ट किया कि अब किसान छिड़काव के लिए दवाई और पम्प प्राप्त करने हेतु आ रहे हैं और आता है कि प्रभावि क्षेत्र में दवाई का छिड़काव महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा। जिन दूसरे जिलों में छोटे छोटे क्षेत्रों में कीड़े का प्रकोप देखा गया है उन जिलों के उप कृषि निदेशक भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उससे निपटने के लिए इसी प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सुण्डी से चने की फसल को कितना नुकसान होगा इसका तुरंत अनुमान लगाना कठिन है किन्तु समय पर की जा रही छिड़काव की कार्यवाही से यह नुकसान बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।

इसके साथ ही स्पीकर साहब, भिवानी जिले के बारे में मैं एक ताजी सूचना देना चाहता हूँ कि कुल 52500 हैक्टेयर प्रभावित क्षेत्र में से लगभग 22000 हैक्टेयर में दवाई का छिड़काव कराया जा चुका है। और आज भाम तक 26000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में छिड़काव हो चुका होगा। जिला प्रशासन और

जिला कृषि अधिकारियों की ओर से विशेष मुहिम के रूप में यह कार्य करवाया जा रहा है। दवाई की कोई कमी नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा लम्बा चौड़ा ब्यान दे दिया और एक ड्रामें से अधिक कोई बात साबित नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि सरकार चने को बचा नहीं पाई। जिस तरह से सरकार ने ओलावृष्टी के नुकसान की सहायता दी है क्या उसी तरह से चने की फसल के नुकसान के लिए भी सरकार सहायता करेगी?

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने बताया कि कृषि विभाग ने कोई संतोशजनक काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मैं यह जरूर कहूंगा कि तीन चान दिन की देरी हुई। उसका कारण यह था कि किसान यह सोच रहे थे कि उन्हें सबसिडी पर दवाई मिलेगी लेकिन हमारे समझाने पर आज किसान बड़े जोर भाोर से दवाई छिडक रहा है। जो इन्होंने मुआवजे की बात कही उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, इवाई की कमी के कारण फसलें 50 प्रति ात से 100 प्रति ात तक खराब हुई है। भविश्य में ऐसा न हो इन्होंने इसके लिए क्या प्रबन्ध किया है?

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, दवाई की कमी के कारण कोई फसल खराब नहीं हुई। यह तो प्राकृतिक प्रकोप हुआ,

कीडो ने अचानक आक्रमण कर दिया। आगे के लिए भी हम दवाई की कमी की वजह से फसल खराब नहीं होने देंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं अपनी प्रिविलेज मोशन के बारे में एक सबमिशन करना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: Your privilege motion has been received by the Secretary. I have not read it so far.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपके बारे में एक बड़ी सीरियस बात कही गई है कि आप उस सवाल को टाल मटोल करते रहे। ठीक है प्रैस हमारी फोर्थ एस्टेट है लेकिन उसे आप पर रिफ्लैक्ट करना नहीं करना चाहिए था, सदन के अध्यक्ष की नीयत पर भाक नहीं करना चाहिए था और न ही मेरे माननीय अजीज मैम्बर की नीयत पर भाक करना चाहिए था। (विघ्न) स्पीकर साहब, यह बड़ी सीरियस बात है और इसका उचित नोटिस लिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Your privilege motion was received by the Secretary at 3.05 p.m. I have received it only 2-3 minutes back. This will be examined.

डा० साहब, फरीदाबाद कम्प्लैक्स ऐडमिनिस्ट्रेटिव की रिप्लेसमेंट वाले सवाल पर सप्लीमेंटरी पूछने के लिए जब मैं आपको बुलाने लगा तो आप हाउस से चले गए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे सामने चूंकि यह कागज आ गया इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ इसी को ले लिया जाए। (हंसी)

वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, अब 1988-89 के बजट पर जनरल डिस्कान रिज्यूम की जाएगी। 25 तारीख को श्री बृज मोहन गुप्ता बोल रहे थे। वे अपनी स्पीच रिज्यूम करें।

डा० बृज मोहन (जगाधरी): स्पीकर साहब, मैं उस समय गवर्नमेंट डाक्टरज के बारे में यह कह रहा था कि हरियाणा के अन्दर बहुत सी डिस्पेंसरियों और अस्पतालो में जगह खाली है। मेरा उसके लिए एक सुझाव है कि सरकार को उन डाक्टरज को प्राइवेट अलाऊ कर देना चाहिए। भायद यह तजुर्बा कामयाब हो जाए और इससे जो जगहें अस्पतालो और डिस्पेंसरियों में खाली पडी है, वे पूरी की जा सके। इसके अलावा मुझे कल ही पता लगा है कि जगाधरी सिविल अस्पताल के लिए मैंने जो एक मांग की थी कि वहां पर एक कैजुएलिटी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, वह भायद खोलने जा रहे है। वह सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है। वहां पर जो इंडस्ट्रीज है, वे भी ऐसी है जो तेजी से कोन बनाने वाली इंडस्ट्री है। वहां पर एक्सीडेंटस भी बहुत ज्यादा होते है और गम्भीर एक्सीडेंटस भी बहुत होते है। आलरेडी वहां पर जो अस्पताल है,

अगर उसमें कैजुएलिटी डिपार्टमेंट भी हो जाएगा तो उससे वहां पर सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, मैं एक प्रार्थना करूंगा कि टाईम की कमी को देखते हुए आप जल्दी वाईड अप करने की कोशिश करें।

डा० बृज मोहन: बहुत अच्छा जी। मैं अपनी बातें जरूर जल्दी कहूंगा। मेरा कहना यह है कि एक तो वहां पर कैजुएलिटी डिपार्टमेंट जरूर खोला जाना चाहिए क्योंकि वह सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है। अगर वहां पर डाक्टर्स पूरे होंगे तो इससे लोगों को और मरीजों को सुविधा होगी। इससे तीन डाक्टर्स वहां पर आ जायेंगे। मैं एक बार फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इस डिमांड पर गौर किया जाए ताकि यह जो डिमांड मैंने यहां पर रखी है, उसको थोड़ा सा पूरा किया जा सके। (घंटी) अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगें जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा। मेरे हल्के में कुछ सड़के बहुत जरूरी हैं। अगर मंत्री जी यह नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वह सड़क खुण्डेवाला से मुसिम्बल तक बननी चाहिए। उसका नाम बलकार सिंह भाहीद मार्ग रखा गया है। उस सड़क को अगर मुसिम्बल गांव से मिला दें तो लोगों को काफी सुविधा होगी। इसके अलावा हमारा इलाका ऐसा इलाका है जहां पर फलड लगता है। जब फलड आता है तो लोगों को देहातो से निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। ये सड़के जो मैं अभी बता रहा हूँ, इनको बनाना फलड की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। एक है

तलाकौर से बाल छप्पर। एक है सुलतानपुर से मुस्तफाबाद। एक है कंजल से हाफिजपुर। एक है काबलपुर से गोलहनी। एक है सुढेल से रुलहा खेडी। एक है सारन बस स्टैंड से गांव की फिरनी तक। यह जो सडक है यह गांव में जाती है और कच्ची सडक है। लगभग पौना किलोमीटर की लम्बाई होगी। इसी तरह से एक गांव हमारा बंटा हुआ है। जो सडक को मिलाना है वह है फरीदपुर से कूलपुर तक। मैं यह कहूंगा कि इसी तरह से एक सडक सभापुर ग्राम की भी बनाना जरुरी है जो यमुना नगर के पास है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मेरे हल्के में पिछले दिनो सरकार के आने के बाद एक टैम्पोरेरी पुलिस पोस्ट बिलासपुर के पास बैठायी गई थी। वहां पर मेला मंचतीर्थी लगता है। कुछ टैंान हो गयी थी इसलिए वहां पर पुलिस पोस्ट बैठाई गयी थी। मैंने मांग की थी कि उसको परमानेंट बनाया जाए क्योंकि थाना छप्पर उस इलाके से काफी दूर पडता है। अगर वह पुलिस पोस्ट परमानेंट बना दी जाती है तो वह बीच में आ जाती है क्योंकि थाना छप्पर का वहां से भी आगे इलाका है। पता नही परमानेंट करने की बजाए किन कारणों से वह पुलिस पोस्ट हटा दी गयी है। मैं यह प्रार्थना अपने मुख्य मंत्री महोदय से करुंगा कि पंचकूइया मे जो टैमपोरीरी पुलिस पोस्ट चालू की गयी थी, अगर उसको फिलहाल परमानेंट नही कर सकते तो टैम्पोरीरी तौर पर तो अव य ही चालू कर दिया जाए अगर हो सके तो उसको परमानेंट कर दिया जाए। वहां पर पहले एक डिस्पेंसरी बनाने की स्कीम भी थी। वहां पर कपालमोचन का जैसे मेला लगता है,

उसके कुछ दिन पहले वहां पर मेला लगता है। वहां पर आजकल डिस्पेंसरी नहीं है। हेल्थ मिनीस्टर महोदया यहां पर बैठी हुई है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि वहां पर एक डिस्पेंसरी की बड़ी मांग है। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि वह इसके अलावा दो-तीन अस्पतालों के बारे में भी जरूर ध्यान दें। मुस्तफाबाद में जो अस्पताल है, वहां पर खास तौर पर िाकायत है कि वहां पर डाक्टर का अभाव है या जो डाक्टर वहां पर लगे हैं उनकी ड्यूटी का समय कम है। उसको ध्यान में रखकर वहां पर उसके ठीक किया जाए। स्पीकर साहब, सब से बड़ी बात मैं स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आ आप खत्म करिए।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, दो स्कूल एक मुस्तफाबाद का हैं और दूसरा मुसीम्बल का है। ये दोनों पहले ही हाई स्कूल हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बाहरवीं तक कर दिया जाए। इसके लिए मैं सरकार का बहुत ही आभारी हूंगा। इन भाब्दों के साथ, आपके कहने के मुताबिक इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री नर सिंह ढांडा (पाई): अध्यक्ष महोदय, 1988-89 का जो बजट हमारे उप-मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि वाकई मे चौधरी देवी लाल की

सरकार किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों और दसतकारों की सरकार है। इसमें जो ब्यौरा दिया गया है उसमें बताया गया है कि हम 31 प्रतिशत के करीब बिजली पर खर्च करेंगे, 17 प्रतिशत के करीब सिंचाई पर खर्च करेंगे और 190 करोड़ के करीब समाज सेवाओं पर खर्च करेंगे। इस बजट में पूरी डिटेल्स से सारी बातें लिखी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। इस चुनाव से पहले हरियाणा संघर्ष समिति के नेता चौधरी देवी लाल और डा० मंगल सैन हर स्टेज पर लोगों से कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बुढ़ापा पेंशन देंगे। चौधरी देवी लाल ने हर स्टेज पर कहा कि अगर हमारी सरकार होगी तो कुछ कर्जे माफ करेंगे और दरख्तों में आधा हिस्सा किसानों का होगा। स्पीकर साहब, और भी बहुत सी सुविधाओं के बारे में चौधरी देवी लाल और डा० मंगल सैन ने कहा। स्पीकर साहब, जहां तक कर्जे माफ करने की बात है, कांग्रेस के टाईम में बड़े भारी मेले कर्जों के बारे में लगे और कांग्रेसी सरकारी सम्पत्ति को लुटाते रहे। जब चौधरी देवी लाल ने कर्जा माफ करने की बात कही थी तो चौधरी बंसी लाल ने कहा था कि मैं राजीव गांधी की इजाजत से कर्जे माफ कर सकता हूँ। चौधरी देवी लाल कर्जा माफ नहीं कर सकता लेकिन चौधरी देवी लाल ने यह साबित कर दिया, लोक दल, बीजेपी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि कर्जे माफ किए जा सकते हैं। स्पीकर साहब, जब गांव गांव के लोगों के पास लैटर जाते हैं कि आपका इतना मूलधन माफ कर दिया, इतना ब्याज माफ कर दिया तो किसान लोग, मजदूर और छोटे दुकानदार तथा

मेहनतकाली लोग बड़ी राहत महसूस करते हैं। उन लोगों को चौधरी देवी लाल और डाक्टर मंगल सैन की बात याद आती है जो वे स्टेजों पर कहा करते थे। वे कहते हैं कि ये लोग जो कहा करते थे उसको इन्होंने पूरा कर दिया है। स्पीकर साहब, बुढ़ापा पेंशन सारी स्टेट में दी गई है। चार चार किंतां उन लोगों के पास पहुंच गई हैं। स्पीकर साहब, कोई भी बुढ़ा आदमी चाहे वह किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है उसको पेंशन दी गई है। अगर उनको कहा गया कि दस रुपए इसमें से भेजो तो वे लोग कहते हैं कि चार सौ रुपए ले लो। पेंशन देने से उन लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। पहले उन बुढ़ों का दवा दारु का कोई इन्तजाम नहीं था। अब पेंशन मिलने से वे दवा दारु का इन्तजाम कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने दरख्तों में किसान का आधा हिस्सा रखा है। हम पहले कहा करते थे कि किसान के जिस खेत में कीकर या सफेदा के पेड़ लगे हैं उनसे किसान की फसल को काफी नुकसान होता है। जहां पर ये पेड़ हैं वहां पर फसल नहीं होती। चौधरी देवी लाल की सरकार ने हमारी उस बात को माना और उन पेड़ों में किसान का आधा हिस्सा कर दिया है। इसी तरह से, स्पीकर साहब, जब हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान बार बार इंटरव्यू पर जाते थे और निराशा होकर लौटते थे तो उनको बहुत दुख होता था। उनको किराए के लिए खर्चा भी करना पड़ता था और उनका सिलैक पेंशन भी नहीं होता था। आज हरियाणा के बेरोजगार नौजवान महसूस करते हैं कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने उन बेरोजगार नौजवानों का, बुढ़ों का,

किसानों का और मेहनतकश लोगों का तथा मजदूरों का बहुत भला किया है और चौधरी देवी लाल की सरकार सही मायनों में जनता की सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस बजट में शिक्षा के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में, सड़कों और भवनों के निर्माण के बारे में बहुत सा प्रोविजल रखा गया है। तरक्की के कामों की तरफ खास ध्यान दिया गया है। सचमुच ही यह बजट प्रजापंसा के काबिल है। हरियाणा प्रदेश के अन्दर पिछले दिनों काफी सुखा रहा जिसके कारण उन्नति के कामों में, विकास के कामों में थोड़ी सी ढील रही लेकिन इस बजट से ऐसा मालूम हुआ है कि इस बजट के द्वारा हमारी इस दयालु सरकार ने किसानों और गरीब वर्ग की काफी मदद की है। इस बजट से किसानों को काफी राहत मिली है लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने पाई हल्के का ध्यान इस सदन के द्वारा अपनी सरकार को दिलाना चाहता हूँ कि 1976 से 1987 तक इस हल्के में अपोजीटिव लोग ही रहे हैं जिस कारण से मेरा यह हल्का पिछड़ा रहा और यहां पर कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया। चाहे जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तो भी कांग्रेस के विरुद्ध यहां से आदमी आया। इसीलिए वहां आज तक कोई विकास नहीं हो सका। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि 1970 से लेकर आज तक गांव धौंसा से खनौदा तक की तीन किलोमीटर का सड़का का टुकड़ा है वह नहीं बनाया गया

है। और अगर कहीं धौंस से खनौदा तक जाना हो तो लोगों को कम से कम 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इसी तरह से कठवाड से मुंदली का जो रास्ता है और दूसरा बाकल ओर बरोरा का रास्ता है, ये दोनों जगह केवल तीन किलोमीटर के सड़क के टुकड़े न बनने के कारण लोगों को काफी दूर दूर होकर जाना पड़ता है। बाकल से करोरा को अगर जाना हो तो तीन जिलों कुरुक्षेत्र, करनाल और जीन्द में से लांघ कर जाना पड़ता है। स्पीकर साहब, आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन छोटे छोटे सड़क के टुकड़ों के न बनने के कारण लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों से मेरे हल्के का विकास बिल्कुल रुका पड़ा है जिसकी तरफ आज तक किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। चाहे वह नहर का मामला हो, चाहे किसी स्कूल के अपग्रेडेशन का मामला था और चाहे किसी हस्पताल का मामला था, किसी भी लिहाज से आप ले लें, पाई हल्के को हर लिहाज से पिछड़ा हुआ रखा गया है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे इलाके की बहबूदी की ओर भी कुछ ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, पिछले मैंने चौधरी भजन लाल जी से एक प्रश्न के द्वारा पूछा था कि आदमपुर में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं चाहे प्राइमरी से मिडल और चाहे मिडल से हाई और पाई हल्के में कितने अपग्रेड किए गए हैं तो उन्होंने जबाब दिया कि

आदमपुर में 31 और पाई में केवल एक। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है तो उन्होंने कहा कि वह इलाका बैकवर्ड है और जब यह पूछा गया कि वहां पर नौकरियां क्यों ज्यादा दी गई हैं तो कहते हैं कि इलाका फारवर्ड है। इस तरह की बातें कह करके जनता को गुमराह किया जाता रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चौधरी देवी लाल जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार से यह पूरी तरह से आगे बांधे बैठे हैं कि पाई हल्के के अन्दर चाहे वहां स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे सड़को और भवनो की बात हो, अब यकीन ध्यान दिया जाएगा। गुलियाना और साँगरी में आप जाकर स्कूलो की हालत देखें तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी छतें गिरने वाली हैं। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने स्कूलो के अपग्रेडेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया था लेकिन इस हमारी लोकप्रिय सरकार के आने पर कुछ उम्मीदें बनी हैं कि यह इस ओर ध्यान देगी। मैं इस सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि साँगरी का इलाका चूंकि लोहारु से ज्यादा बैकवर्ड है इसलिए इस और सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे हल्के में बहुत गांव ऐसे हैं जो कि नहर की टेल पर हैं वहां लोगों को आबपाणी के लिए पानी न मिलने के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं और साथ में कुछ छुट-पुट पानी की चोरियां भी होती रहती हैं। कांग्रेस के टाइम पर जो नहरों की लाइनिंग का काम था, वह भी अच्छा नहीं था। उन में से पानी रिसता रहता

है और पानी रास्तों में ही रह जाता है जिसकी वजह से पानी आखिर तक नहीं पहुंच पाता। इस ओर सरकार को खास तवज्जोह देनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए चौधरी देवी लाल जी ने ठीक ही किया है कि जो पानी की चोरी करता है उसको दो बार पानी की बारी से महरुम कर दिया जाए। यह बहुत अच्छी बात की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। वहां पर ट्यूबवैल कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उस इलाके के जितने गांव हैं, वे सभी टेल पर हैं। इसलिए वहां पर नहर का पूरा पानी आखिर तक नहीं पहुंच पाता है लेकिन आज किसान इस बात को सोचता है कि हमें इस लोकप्रिय सरकार से पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा के अंदर दूसरे इलाकों में स्कूलों के अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, नहरें बनवाइ जा रही हैं, भवन निर्माण किए जा रहे हैं और हस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है उसी तरह से हमारे इलाके के लोग भी इस चौधरी देवी लाल जी की सरकार से यह उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे इलाके में भी इस तरह के तरक्की के काम करवाएगी और हमें भी कुछ राहत मिलेगी जिस तरह से दूसरे इलाकों को इस सरकार ने दी है। मैं अध्यक्ष महोदय अपनी सरकार से इस बात की पूरी उम्मीद करता हूं कि यह सरकार मेरे हल्के पाई को हर लिहाज से उपर उठाने का प्रयत्न करेगी ताकि इसका विकास हो सके।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार विमर्श चल रहा है। हमारे वित्त मंत्री महोदय जोकि उप मुख्य मंत्री भी है उन्होंने चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का 1988-89 का पहला बजट पेश किया है। उन्होंने 600 करोड़ के करीब का प्लान बजट और साढ़े 1400 करोड़ रुपए का नान प्लान बजट प्रस्तुत किया है जबकि पिछले वर्ष का 439 करोड़ रुपए का प्लान बजट था। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से बजट प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। पिछली कांग्रेस सरकार ने चुनावों के बहाने से सारे साधनों को बिखेर दिया था और इस ढंग से सारे साधन अव्यवस्थित कर दिये थे कि उनको सही करना बहुत मुश्किल था। चुनावों के नाम पर हरियाणा के भोले भाले लोगों को उस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहकाया। उस सरकार ने कहीं पर किसी काम के लिए नींव पत्थर रख दिया और कहीं पर लोगों से यह कह दिया कि हम यह काम करेंगे। कहीं पर बिजली के खम्भे डाल दिए और कहीं पर बिजली की तारें डाल दीं। इस तरह से करके उस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस हद तक पहुंचा दिया था कि उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। यदि चौधरी देवी लाल जी की सरकार नहीं होती तो पता नहीं हरियाणा के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल पाता या नहीं। इसलिए चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको यह कडिट जाता है और वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि से हरियाणा की गाड़ी

लाइन पर चढा दी। इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती रही। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान होने के नाते जिस प्रकार से इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था उस सरकार ने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, एक केस आपके सामने आया है जो कि स्प्रे पम्प के बारे में है। उसमें 205 रुपए सैंट्रल एड दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई। इस प्रकार से इस मामले में 410 लाख रुपए कम सबसिडी दी गई। इस बारे कंसर्ड और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जिन लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई थी उन लोगों के मार्च 1985 से लेकर आज तक कोई चालान पे नहीं किए गए। चालान पे इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उनकी बीच में मिली भगत हो जाती है। इस प्रकार के लोग अब भी हैं। पिछले साल 1987-88 में जो कीटनाक दवाईयां खरीदी गई वह एक करोड 51 लाख रुपए से अधिक की खरीदी गई थी। वह दवाईयां इसी महीने की 25 तारीख को खरीदी गई थी। यदि उन दवाईयों की खरीद के बारे में यह कह दिया जाए कि उसमें सरासर किसानों को लूटा गया है तो गलत नहीं होगा। मैं तो यह कहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी के समय में किसानों के साथ इस तरह की लूट हो जाए तो उसके बाद बचने के लिए कोई चारा नहीं रह जाता है। इसके अलावा एक बड़ी गजब की बात देखने में आई है। एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होता है। वह जिस डिलर से सैम्पल लेता है उसका सारा पता बता देता है कि उसका सैम्पल

किस लैबोरेट्री में भेजा जाएगा। इसके अलावा उस इंसपैक्टर के पास एक कोड होता है ताकि वह डिलर वहां तक पहुंच सके। उन इंसपैक्टर को यह हिदायतें हैं कि जो दवाईयों के सैम्पल लिए जाएं वे हिसार और करनाल की लैबोरेट्रीज में भेजे जाएं क्योंकि यदि दूसरी किसी लैबोरेट्री में सैम्पल भेजा जाए तो वह 250 या तीन सौ रुपए फीस ले लेती है। यदि क्वालिटी कंट्रोल इंसपैक्टर दवाईयों के सैम्पल लेकर लैबोरेट्री को भेजते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार की पूरी पूरी गूंजाइ रह जाती है क्योंकि ये डीलरज को यह बता देते हैं कि उनका सैम्पल कौन सी लैबोरेट्री में भेजा जाएगा जबकि उनको उस बारे में नहीं बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐल्ड्रीन के 11 सैम्पल तो दवाई खरीदने के पहले लिए गए थे पिछले दिनों कीटना एक दवाईयां गई जिस पर 1,53,17,681 रुपए खर्च किए जिसमें से छः सैम्पल फेल आए। इसी प्रकार से एस्टोलीन दवाई के 38 सैम्पल लिए गए थे इनमें से 21 पास हुए और बाकी सैम्पल फेल पाए गए थे। सिर्फ दवाई को खरीद से ही यह संबंधित बात मैं नहीं कर रहा। अध्यक्ष महोदय, यदि सही दवाई की खरीद की जाती तो एक तो किसान का जो पैसा बर्बाद हुआ है वह बच सकता था और दूसरे जो किसानों को और सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हुई है वह बच सकती थी। अगर दवाई की ठीक खरीद की होती तो फसलों में जो बीमारी (कीड़े आदि) लगी है वह न लगती। दवाई सिर्फ डीलर ने ही गलत सप्लाई नहीं की बल्कि सरकारी एजेंसी जैसे हैफेड वगैरा ने जो दवाईयां खरीदी है, वे भी ठीक नहीं पाई गईं। इतना ही नहीं

आई० एस० आई० मार्क चीजे जो किसान अपने लिए खरीदते हैं वे भी नाम तो आई० एस० आई० मार्क होती है लेकिन असल में कुछ और होती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पिछे सरसो पर चेपा लग गया था। किसानो ने सरसो को चेपे से बचाने के लिए जो दवाई खरीदी वह भी बेकार थी। इसी प्रकार से कई स्थानो पर चने की फसल भी 50 प्रति ात से लेकर 100 प्रति ात तक खराब हुई है। जब किसान लोग या हमारे जैसे ि ाकायत करते हैं तो उनके खिलाफ ऐव ान सिर्फ लाईसिंसीज कैंलि करने तक ही लिया जाता है। बाद में किसी न किसी तरीके से उनका लाईसैंस रिस्टोर हो जाता है। यदि लाईसैंस रिस्टोर नहीं हो पाता है वे उसी लाईसैंस को किसी दूसरे के नाम से लेकर अपना काम चलाते रहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो लोग किसानो को धोखा देते हैं उनके लिए सरकार ऐसा काई कानून बनाए जिससे वे बच न सके। सरकार किसानो को होने वाले खराये के लिए खुद संबंधित डीलर के खिलाफ प्रासिक्यू ान करें, क्योंकि किसान तो बेचारा पहले ही गरीबी का मारा हुआ है। वह तो कुछ कर नहीं पाता और न ही उसके पास इतना समय होता कि वह गलत दवाई देने वाले डीलर के खिलाफ अपने हर्जाने के लिए केस लडता फिरे। सरकार खुद को प्रोसीक्यूटकरके किसान को हर्जाना दिलवाने की को ि ा ा करे ताकि किसान को बर्बाद होने से बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्प्रिंकलर सैटस की खरीद के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। स्प्रिंकलर सैटस जो इरीगे ान डिपार्टमेंटकी खरीद होती है उसमें और जो किसान अपना लोन

लेकर कही ये स्प्रिंकलर सैटस खरीदता है, की कीमत में 97 रुपए 80 पैसे 20 फूट के एक पाईप में अन्तर होता है। इस के साईज मे, लम्बाई में या दूसरी तरह की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता लेकिन किसान को सिंचाई विभाग के जरिए अधिक पैसो पर यह सैट मिलता है। पीछे एक बार लोकदल पार्टी की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी मैम्बरान साहेबान का यह विचार था कि किसान के लिए बिचौलिया प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए। जब इसका हम जिक्र करते है तो हमें उतर मिलता है कि इससे गडबड अधिक होगी। मै बताना चाहूंगा कि गडबड हमें उतर मिलता है इससे गडबड अधिक होगी। मै बताना चाहूंगा कि गडबड अब कौन सी कम हो रही है। अब भी तो संबंधित महकमे के लोग बैंक वालो से या डीलरो से मिल कर गडबड करते है। किसानो से बैंको वाले और डीलर्ज दोनो पैसा लेते है। किसान को बिचौलियो से कोई चीज खरीदने के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए देने पड रहे है। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान को डायरैक्ट पेमेंट की जाए ताकि किसान की लुटाई कम हो सके। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय मै एक और चर्चा करना चाहता हूं। पिछले चुनाव के वायदे के अनुसार देहात के पिछडे, हरिजन और गरीब लोगो को पंचायत की भामलात जीमन से प्लाटस दिए। इसी तरह से भाहरो में भाोशित और पिछडे और हरिजनो को भी प्लाटस देने का वायदा किया था लेकिन भाहरो में हाउसिंग प्लान को मैने देखा है इसमें पिछले तीन सालो से कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर

कुछ पैसे का प्रावधान किया गया था तो म्यूनिसिपल कमेटी की गन्दी बस्तियों के लिए किया गया था। 1986-87 में तीन करोड़, 1987-88 में एक करोड़ से ज्यादा और 1988-89 में भी एक करोड़ का प्रावधान किया जाए। चुनाव के दौरान और भी वायदे किए थे कि हुडडा की ओर से जो गडबड घोटाला हुआ है उसके लिए एक जांच समिति बैठाएंगे और जब तक वह समिति फैसला नहीं करेगी तब तक किसी किस्म की कीमत प्लोट होल्डर्स की नहीं बढ़ाएंगे। वह जांच समिति भायद अभी बैठायी नहीं गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्लॉट होल्डर्स के साथ जो गडबड की गई है उसके लिए जांच समिति बैठाई जाए। दूसरे जो पहले कौलानाइजर्स से पचास परसेंट डिवलपमेंट चार्जिज लिए जाते थे अब कौलोनाइजर्स की बजाए प्लॉट होल्डर्स से सैंट परसेंट लिए जाते हैं। इस बारे में भी सरकार विचार कर ले तो अच्छा रहेगा। उपध्यक्ष महोदय, आप यह भी जानते हैं कि लोक राज लोक लाज से चलता है। इसलिए चौधरी देवी लाल का यह नारा कि भ्रष्टाचार बन्द करो, वह बहुत अच्छा है। सरकार ने जो ऐन्टी करप्शन बोर्ड बनाया है, उसमें काफी सफलता मिल रही है। लेकिन मैं आपके जरिए प्रार्थना करुंगा कि लोक आयुक्त की भी नियुक्ति की जाए ताकि जो हमने वचन दिया था उस वचन के मुताबिक काम कर सकें। हमारी सरकार ने और भी बहुत से काम किए हैं। हमारी सरकार ने जितनी जल्दी से काम किया है उसका सारे हिन्दुस्तान में रिकार्ड है चाहे वह कर्जा माफी का है, चाहे बुढापा पेंशन का है और चाहे कहत में चारा सप्लाई का है।

इसी प्रकार से बिजली की सप्लाई में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश की सरकार ने इतनी जल्दी से इतने काम नहीं किए।

इसी तरह से मैं शिक्षा के लिए भी कहना चाहूंगा। शिक्षा में प्राइमरी स्कूल मुख्य है। प्राइमरी शिक्षा का डायरेक्टोरेट अलग से होना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रमोशन के लिए मौका मिल सके। ऐसा करने से वे अपने काम में अधिक दिलचस्पी लेंगे। मैं आपके द्वारा यह भी गुजारि करूंगा कि ऐजुकेशन के सिलसिले में पिछली सरकार ने कई घोशणाएं की थीं। उन घोशणाओं को लागू किया जाए। जिस प्रकार पी0 टी0 आई0 को तीन ऐडवांस इंक्रीमेंट देना, हिन्दी अध्यापको को संस्कृत अध्यापको के बराबर ग्रेड देना आदि है। इसी प्रकार के मुख्य अध्यापक को गजटिड करार दिया गया था लेकिन अभी तक वे आर्डर इम्पलीमेंट नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें इम्पलीमेंट करें।

भिवानी के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने ऐलान किया था कि सूखाग्रस्त इलाके के जो बच्चे कालेज में पढ़ते हैं उनकी फीस माफ की जाएगी लेकिन वे आदेश अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वे आदेश तुरन्त जारी किए जाएं ताकि पिछड़े और कहत से पीड़ित लोगों को ठीक समय पर सहायता मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पैंशन के जो नये ग्रेड लागू किये गये हैं, वह जनवरी 1986 की बजाए

1 जनवरी 1988 से लागू किये गये हैं (विधन्) मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि यह ग्रेड जनवरी, 1986 को दिए जाएं। इस बारे पुनर्विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं प्रार्थना करुंगा कि जिस तरह जो मकैनिकल कर्मचारी 240 दिन से ज्यादा की सेवा पूर्ण कर लेते हैं उनको रैगुलर कर दिया जाता है उसी तरह से शिक्षको के लिए भी मैं चाहूंगा कि 240 दिन की सेवा करने पर उन्हे भी रैगुलर किया जाए। इससे उन्हे बडी राहत मिलेगी। पहली सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर करने का वायदा किया था और उस समय चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से यह आदेश जारी किए गये थे:—

“After careful consideration it has now been decided that the services of all the workcharged employees working in the Haryana State, who have completed 4 years or more continuous service on 31st December, 1986 should be regularized.”

मकैनिकल कर्मचारियों के लिए यह फैसला किया गया था। यह कर्मचारी दस हजार से कम नहीं होंगे जिन्हे इससे लाभ मिलता। पिछली सरकार अपने किए हुए वायदे से बैकआउट कर गई है लेकिन मैं चाहूंगा कि हमें पिछली सरकार के उस फैसले का आनर करते हुए जिन मकैनिकल कर्मचारियों की सेवा 240 दिन की पूर्ण हो चुकी है उन्हे रैगुलाईज करने के कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं प्रार्थना करूंगा कि देहात के लिए स्कूलों तथा ऐजूके इन की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन कर्मचारियों को हाउस रेंट नहीं दिया गया उनको पांच प्रतिशत बैंकवर्ड अलाउंस दिया गया है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हाउस रेंट के साथ साथ यदि बैंकवर्ड अलाउंस भी दे दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं बतट में कमी को देखते हुए इस बारे में एक सुझाव रखना चाहूंगा कि जो कर्मचारी देहात में घर के पास रहते हैं और जो कर्मचारी भाहर में अपने घरों में रहते हैं उनको हाउस रेंट न दिया जाए। जो कर्मचारी देहात में अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिड हो, क्योंकि देहात में आने जाने के साधनों की कमी है, और जो कर्मचारी भाहर से बीस किलोमीटर के एरिया में अपने घरों में रहते हैं, उन्हें हाउस रेंट न दिया जाए। इस प्रकार धन की कमी कुछ हद तक दूर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मालिक और मजदूर के बीच में इंडस्ट्रीयल झगडे होते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन झगडों को निपटाने के मामले श्रम विभाग को न दिए जाएं बल्कि सरकार द्वारा सीधे ही ट्रिब्यूनल को सौंपे जाएं। कानून में इस आठव को संशोधन भी कर दिया जाना चाहिए। मजदूरों ने भी इस सरकार को पावर में लाने के लिए बहुत सहयोग दिया है। अतः इससे उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी और उनके दुख दर्द भी कुछ कम होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्यमें स्प्रिंकलर पम्प सैटो पर टैक्स की छूट नहीं है। सैन्टर गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रिंकलर पम्प सैटो की खरीद पर सबसिडी दी जाती है। हरियाणा में ऐग्रीकल्चर औजारो की खरीद में दस हौर्स पावर की मोटर पर टैक्स माफ है लेकिन स्प्रिंकलर पम्प सैटो पर टैक्स की माफी नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है। मैं यह निवेदन करुंगा कि सरकार इस टैक्स को माफ करने की कृपा करे ताकि किसानो को इससे लाभ मिल सके। सबसिडी के लिए 90 लाख रुपए की राशि का प्रोविजन किया गया है जबकि साठ-सत्तर लाख रुपये तो सेल टैक्स ही ले लिया जाता है। किसान को धन जुटाने में दिक्कत आती है। उसको बिचौलिये ही खा जाते है। इसलिए मैं अनुरोध करुंगा कि स्प्रिंकलर पम्प सैटो पर टैक्स माफ कर दिया जाए और सबसिडी चाहे न दी जाए। यदि सबसिडी भी दी जा सकती है तो यह बहुत अच्छी बात है। (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अन्य प्रदेशों की भांति खादी बोर्ड की चीजों पर और झोटे बुग्गी पर बिक्री कर समाप्त होना चाहिए। इसी तरह से हमारी सरकार ने अनेको कदम उठाए है उनके साथ साथ मैं यह भी प्रार्थना करुंगा कि जहां मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया है, मोरनी हिल्ज का बनाया है उसी तरह से एक डैजर्ट बोर्ड भी बनाया जाए ताकि डैजर्ट एरियाज के लोगो का भी भला हो सके। मुख्य मंत्री महोदय जब

पिछली बार 1977 में भी मुख्य मंत्री थे तो ये लोहारु में एक पौलैटैक्निक का ऐलान करके आए थे। इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में उसका बकायदा ऐलान किया था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद ये मुख्य मंत्री नहीं रहे और दूसरी सरकार ने उस पौलैटैक्निक को आदमपुर में भेज दिया। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी वजह से पौलैटैक्निक न बन सके तो आई० टी० आई की ही घोशणा कर दें। इन्होंने 21 दिसम्बर, 1978 को जलसे में यह भी ऐलान किया था कि हमारे वहां हैफेड द्वारा एक ऊन का मिल लगाया जाएगा। वहां पर वूल ग्रेडिंग सैन्टर तो है लेकिन मिल नहीं है। उस मिल के लिए फाइल तैयार हो गई थी लेकिन सरकार बदलने के कारण कोआप्रे इन मिनिस्टर दूसरे आ गए। उन्होंने वहां की बजाए उस मिल को भिवानी ले जाने का प्रयत्न किया। नतीजा यह हुआ कि वह मिल कहीं भी नहीं लग पाया। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले साल से उस ऊन मिल का ऐलान कर दें ताकि वहां के लोगो को भी सहारा मिल सके। जे० बी० टी० सैन्टर के लिए जो पिछले सै इन में आ वासन दिया था वह तो खुल ही जाएगा। धन्यवाद।

श्री मांगे राम (बहादुर गढ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1988-89 के बजट का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले बंसी लाल और भजन लाल तथा उनके एम० एल० एज० सारा बजट खुद ही खा जाया करते थे। पिछले 40 साल की आजादी के बाद रोहतक जिले के अन्दर सिर्फ 1977-78

में ही काम हुआ लेकिन कांग्रेस सरकारो ने रोहतक जिले में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। हमारे रोहतक जिले के अन्दर सडको की बहुत खराब हालत है। जैसे हिमाचल की सडके टेढी मेढी है, हमारी सडके उंची नीची है। हमारे बहादुरगढ थाने में कांग्रेस वालो के 11 ट्रक तारकोल के पकडे गए थे जिसे कांग्रेस वाले खा गए। मेरे हलके के अन्दर बहुत जूलम किया गया। वहां पर कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है और न ही कोई रोड है। सूखी रोडी पडी है। मेरे हलके के अंदर केवल एक पी0 डब्ल्यू0 डी0 का रैस्ट हाउस है वह भी औरंगजेब वहां से गुजर रहा था, वह बना गया। उसके अलावा एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, बहादुरगढ गेटवे आफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। 132 के0 वी0 का पावर हाउस झज्जर के अंदर है, कोसली के अन्दर है और रोहतक के अंदर है लेकिन बहादुरगढ के अन्दर नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे क्षेत्र से आज तक कोई कांग्रेस का आदमी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहादुरगढ के अंदर 560 फ़ैक्ट्रीज थी उनमें से 540 फ़ैक्ट्रीज वहां से उठकर बाहर चली गयी है। यह केवल कांग्रेसियों की गलत नीतियों के कारण गयी है। बहादुरगढ के अन्दर 132 के0 वी0 का पावर हाउस बनाया जाए ताकि वहां पर फ़ैक्ट्रीज दिल्ली से वापिस आ सके। पहले मेरे क्षेत्र के अंदर नहरी पानी की बहुत कमी थी और नहर की टेल तक पानी नहीं पहुंचता था। पिछले 5 साल के अन्दर ऐसी हालत नहीं रही है जितनी

अच्छी हालत अब की बार रही है। उसके लिए हमारे आई० पी० एम० साहब की जितनी तारीफ की जाये, वह कम है। पहली बार सारे हरियाणा में नहर की टेल तक पानी पहुंचा है। पिछले 40 साल के दौरान मेरे हलके में नहर की टेल तक कभी पानी नहीं गया। 38 गांव मेरे हल्के के अन्दर है 32 गांव नहरी पानी से भर गये। 28 गावों की मिट्टी जोहडो में से उठायी गयी। कांग्रेस की सरकार ने क्या कभी इस तरह से जोहड भरने थे? मेरे क्षेत्र की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं जितने दुख उ समय के बताऊ उतने ही थोड़े है। 1977 और 1978 के अन्दर चौधरी देवी ला की सरकार ने बहादुरगढ में वै य आर्य कन्या महाविद्यालय में बी० एड० की क्लासिज भुरु करवाई थी लेकिन उसके बाद 1982 में जब कांग्रेस के एम० एल० ए० वहां से हार गये तो उस महाविद्यालय में बी० एड० की क्लासिज बंद करा दी गयी। मेरी प्रार्थना है कि उस महाविद्यालय में बी० एड० क्लासिज दोबारा भुरु करवाई जाएं। यही नहीं, बहादुरगढ के साथ और भी बहुत सी ज्यादातियां की गयी। जैसे बहादुरगढ से चंडीगढ और बहादुरगढ से दिल्ली दो बसें चला करती थी वह भी कांग्रेस सरकार ने बन्द कर दी थी। लेकिन अब बहादुरगढ से चंडीगढ के लिए दो और बहादुरगढ से दिल्ली के लिए चार बसे चलने लग रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कल ही बी० डी० ओ० साहब से मिला था। मेरे पास आंकडे है। यह मेरे अपने आंकडे नहीं है। पिछले 5 साल के दौरान कांग्रेसी सरकार ने जितना रुपया मेरे ब्लॉक को दिया था, उससे ज्यादा रुपया पिछले 8 महीने के दौरान चौधरी देवी लाल

की सरकार ने दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ईमानदारी की बात बताऊँ। बसी लाल और उसका लडका सुरेन्द्र सिंह मेरे हल्के के अन्दर जाकर के 60 हजार रुपया मन्थली बोर्डर का एरिया होने के नो लिया करते थे। (व्यवधान एवं भाोर) यही नहीं चौधरी तैयब हुसैन ने जो डी0 एस0 पी0 लगवाये थे, उनसे 45 हजार रुपया महीने का लिया करते थे। यह तो रिकार्ड की बात है। मैं आज कांग्रेस के 5 एम एल ए को निमंत्रण देता हूँ कि वह मुझे एक जगह भी ऐसी दिखा दें। चौधरी देवी लाल का राज तो राम राज के समान है। अगर इस राज में कोई भी पैसा लेता हो तो बता दें। इनके टाईम में तो रेहडी वालो से पुलिस वाले केले ले लिया करते थे, रिक् गा वाले को बिना किराये दिये ले जाया करते थे। मैं और क्या क्या बताऊँ? मैं 1982 में चण्डीगढ से बहादुरगढ जाया करता था। जगह-जगह पुलिस की वर्दी वाले खडे रहते थे और ट्रक वालो को धेरे रहते थे।

चौधरी तैयब हुसैन: इस बात के लिए हमें ट्रफिक पुलिस की तारीफ करनी चाहिए।

श्री मांगे राम: नहीं जी, मेरे पास भी उस वक्त ट्रक था। मेरे से भी वे मन्थली लिया करते थे। (गोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): इनसे नहीं, इनके ड्राईवर और कंडक्टर से मन्थली लिया करते थे, इनका यह तात्पर्य है।

चौधरी तैयब हुसैन: यह कोई लाईट बात नहीं है। इसकी सीरियसली समझ कर कहने की कोशिश करनी चाहिए।

16:00 बजे

श्री मांगे राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस सदन को मन्दिर समझता हूँ। मैं जब तक मन्दिर नहीं हो आता तब तक एक चाय का प्याला भी नहीं पीता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के साथ जितना जुल्म कांग्रेस के राज में किया गया उतना कभी नहीं हुआ। मैं तो लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे नागफन के बीज खत्म कर दिया उसी तरह से जनता कांग्रेस का नामोनिशान मिटा दें। चौधरी देवी लाल ने चार पांच लाख रुपया एक महीने में भेज दिया उससे मेरे यहां अस्पताल बन गया। ग्यारह लाख रुपया चला गया उससे मिनि सैक्रीटेरिएट बन गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां चाय पीने का भी अच्छा इन्तजाम हो गया है। मैं इतना ही कहकर खत्म करता हूँ।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले बोल चुके हैं।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मैम्बर्ज भी हैं जो दोनों विशयों पर बोले हैं। इसलिए मुझे भी बोलने का समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाए।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी तो बोलना है
(गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाए। सदन के कुछ रुल्ज है।
आप उनके मुताबिक चलें।

श्री रघु यादव: हम आह भी भरते है तो हो जाते हैं
बदनाम,

वे कत्ल भी करते ळे तो चर्चा नही होती। (गोर एवं
व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री वेद सिंह मलिक।

श्री वेद सिंह मलिक (कैलाना): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो 1988-89 का बजट पे ा किया है, मै उसके बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में कोई टैक्स नही लगाया गया बल्कि किसान, मजदूर और व्यापारियों को छूट दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स घटाएं गए है, कोई नया टैक्स नही लगाया गया है। इसके लिए मै अपनी सरकार को बधाई देता हूं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बडी ही सूझबूझ से काम किया है। कोई टैक्स नही लगाया है बल्कि टैक्स कम किए है। उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सी चीजें है जिन पर इस सरकार ने टैक्स कम किया है। सुखे के बावजूद इस बार बिजली की पोजी ान

बहुत बढ़िया रही है। मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि सदन के नेता ने और सिंचाई तथा बिजली मंत्री ने जितनी बिजली इस बार हरियाणा के किसानों, दस्तकारों, और उद्योगों को दी है कांग्रेस के राज में कभी नहीं मिली। सूखे के बावजूद किसानों को इस बार बिजली के बारे में कोई शिकायत नहीं रही। इस बारे में सरकार की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बूढ़े लोगों को जो पेंशन दी है उसके लिए भी यह सरकार बधाई की पात्र है। इससे गरीब और बूढ़े लोगों को बहुत भला होगा। इस सरकार ने भूमि विकास बैंक का ट्रैक्टरों का दस हजार का कर्ज माफ करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हलके में तहसील गन्नौर है लेकिन वहां पर आज तक कोई सरकारी कालेज नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कालेज का निर्माण कराना चाहिए। गन्नौर से सोनीपत दूर पड़ता है और सम्भाला भी दूर पड़ता है। इसलिए एक तहसील है लेकिन तहसील का कोई बिल्डिंग नहीं है। तहसील का दफ्तर कमेटी के दफ्तर की बिल्डिंग में लगाया जाता है। तहसील की बिल्डिंग के लिए जमीन एक्वायर कर रखी है लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गन्नौर में तहसील की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, गन्नौर तहसील होने के बावजूद वहां पर कोई न तो बस डिपो है और न ही सब-बस डिपो है। वहां पर गावों में बस

सर्विस न के बराबर है। सोनीपत से एक दो बसें वहां आती हैं लेकिन गन्नौर से कोई बस कही नहीं जाती। सोनीपत या पानीपत के लिए भी कोई बस नहीं जाती।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस के साथ मैं यहां सदन के सम्मुख एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार गन्नौर के अन्दर टेलीफोन ऐक्सचेंज लगाना चाहती है जिसके लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। भोश सारा खर्चा भारत सरकार ही वहन करेगी। इसलिए मेरा अपनी सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस तरफ खास तवज्जोह दे ताकि वहां पर टेलीफोन ऐक्सचेंज का निर्माण करवाया जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे इलाके में बहुत कम यानि न के बराबर डिस्पैन्सरीज हैं। कही भी जाओ केवल 10 गावों के पीछे एक डिस्पैन्सरी मिलेगी जो उन सारे इलाके को फीड करती होगी। तो आप स्वयं ही यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी गन्नौर तहसील में डिस्पैन्सरी की बहुत कमी है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहां पर और डिस्पैन्सरी खोली जाए।

जहां तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, इस बारे में हमने मुख्य मंत्री महोदय को पहले भी कहा था और आज मैं इस हाउस में माध्यम से ट्रांसपोर्ट मंत्री से कहना चाहता हू कि गन्नौर जी0 टी0 रोड पर स्थित है, वहां पर लम्बे रुल्ज वाली बसें, जैसे चण्डीगढ से दिल्ली व अम्बाला से दिल्ली जाने वाली बसें नहीं

रुकती है जिस कारण से लोगो को काफी दिक्कतो का सामना करना पडता है। इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि इस तरह की लम्बे रुट्स वाली सभी बसें वहां रुक कर जानी चाहिए। यह समस्या कई बार सरकार के सामने रखी गई है। इसी तरह से सडको की हालत भी मेरे हल्के में बहुत खराब है। कई सडके टूटी फुटी पडी है उनकी मुरम्मत नही हो रही है। चौधरी देवी लाल जी की सरकार आने के बाद सडको की हालत काफी हद तक सुधरी है। एक आध सडक हमारे हलके में बनी भी है और मुरम्मत भी हुई है। फिर भी कुछेक सडके ऐसी है जिनकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरुरी है क्योकि लोगो को आने जाने में काफी दिक्कत होती है।

इसी तरह से मै बिजली लाइनो के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बिजली की लाईने गावों के उपर से होकर जाती है जिनको जल्दी से जल्दी बदला जाना बहुत जरुरी है। इसके लिए मै आई पी एम साहब से दरखास्त करुंगा कि उन लाईनो को जल्दी ही बदलवाया जाए। उनके न बदले जाने से लोगो को नुकसान होगा। मै आपको बताना चाहता हूं कि गांव बेगा में जोहड में नही रही पांच भैंसो को बिजली का करन्ट लगा और वे मौके पर ही मर गयी। इसलिए उन लाईनो को जल्द से जल्द ही बदलवाया जाए ताकि लोगो को कोई परे ानी न हो।

इसी तरह से चौपालो के बारे में भी मै जिक करना चाहूंगा कि कई चौपालो की छतें टूटी पडी है। बहुत बुरा हाल है

और उनके पास छतों की मुरम्मत के लिए पैसा नहीं है। हमारे सोनीपत में गन्नौर ब्लॉक में सब से कम पैसा दिया गया है। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे ब्लॉक को चौपालों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि चौपालों की छतों की मुरम्मत करवाई जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, जन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी एक अर्ज है कि हमारे हल्के में लोग डिग्गियों के पानी को नहीं पीते, ट्यूबवैल्ज का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि जो पानी खुले खालों से आता है उसमें लोग कपड़े भी साफ करते हैं और मवेशी भी उन खालों में पानी पीते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के में पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं। इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल्ज लगाए जाएं। इसके अलावा मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जो वाटर पाइप लाइन है वे बिल्कुल खराब हो चुकी है जिसके कारण वहां पर पानी की सप्लाई चालू नहीं है। मेरे हल्के में एक गांव आहूलाना है वहां पर वाटर पाइप लाइन बिल्कुल खराब हो चुकी है और काफी दिनों से वह लाइन खराब है उस गांव में लोगों के लिए पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर फिरनी में लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है इस

दिक्कत को दूर करवाया जाए। एक घसौली गांव है जिसके अन्दर पिछले दिनो ओले पडे है। अगले ही दिन मुख्य मंत्री जी उन गांवो में गए थे और मै भी उनके साथ था। इस बारे में मै राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि हमारी वहां पर एक दो पटवारियों के बारे में वि कायत है उनको वहां से बदला जाए क्योंकि कई जमींदार हमारे पास आते है और कहते है कि हमारी गिरदावरी गलत हुई है। इसके अलावा मै एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में कहना चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके इस नहर को मुकम्मल करवाया जाए। मै अपने साथी कांग्रेसियों से भी कहूंगा कि वे इस नहर को मुकम्मल करवाने के बारे में सैंटर गवर्नमेंट से सिफारिश करें। जितनी जल्दी हो सके इस नहर को बनवाया जाए ताकि हमारे एरिया को भी पानी मिल सके। मै चौधरी तैयब हुसैन से कहूंगा कि वे इस नहर को जल्दी बनवाएं क्योंकि सैंटर में आपकी सरकार है इसलिए आप ही इसको जल्दी बनवा सकते है। यदि यह जल्दी बन जाएगी तो हमारे एरिया की दिक्कत दूर हो जाएगी।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला—महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से बजट पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओ ने ज्यादातर बजट के पक्ष में ही अपने विचार व्यक्त किए है। मुझे एक बात की भी खुशी हुई है कि पक्ष की तरफ से भी कुछ मेरे भाई रघु यादव जैसां ने, और दूसरे कई पक्षो के भी

ऐसे महानुभाव है जिन्होंने अपनी तरफ से बजट की कुछ आलोचना की है।

श्री उपाध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी आपको बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है इसलिए आपने अपने हल्के के बारे में जो बातें कहनी हैं वही कहें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से अकेला ही बोल रहा हूँ इसलिए मुझे कम से कम डबल टाइम तो मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले महामहि गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उस समय बोलते हुए मैंने सरकार की अच्छी उपलब्धियों और अच्छे कामों को जो मेरी समझ के व विचार के मुताबिक ठीक थे, मान्यता दी थी। उसी आधार पर मैं बजट के विषय में अब कहना चाहूंगा कि यह बजट अधकचरी कर्जे माफी और पैन् इन रुपी बैं गारण्टियों के सहारे पर खड़ा है। अगर सरकार कुछ कदम पैन् इन और अधुरे कर्जे माफी की योजना को अपनी उपलब्धि मान ले तो और बात है। अगर सारी चीजों का गौर से अध्ययन किया जाये तो इस सरकार ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के मुताबिक कार्यक्रमों को कुछ हद तक अनुकरण करने की कोशिश की है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार ने पिछले समय में विपक्ष में रहने के बावजूद भी पिछली सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को अपनी मान्यता प्रदान की है। (विध्वन्) माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पब्लिक ने क्या किया? इस बारे में मैं इन्हे

बताना चाहूंगा कि पब्लिक ने तो 1977 में भी अपना फैसला दिया था और अब भी अपना फैसला दिया है। आगे भी अपना फैसला देगी। (विधन्) उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने अपने बजट भाषण में सबसे पहले जिक्र किया है कि इस सरकार में जनता ने जो वि वास दिया है वह अभूतपूर्व वि वास है उसे हम कायम रखेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री हमारे पूज्यनीय हैं। (विधन्)

चौधरी तैयब हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हे रोकिए। हमारा एक मैम्बर ठीक बोल रहा है तो इसे ये बार बार क्यों बोलने से रोक रहे है?

Mr. Deputy Speaker: You should address the Chair and talk relevant. There is no need to reply. (Noises).

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट से बाहर की कोई बात नहीं कह रहा। आप बजट के पहले पेज को देखें। इसी पेज में इन्होंने लिखा है कि जनता ने हमारी सरकार को अभूतपूर्व वि वास दिया है। इसी बारे में मैं कह रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इनका ताजा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने इस सरकार से क्या अपेक्षा की थी और इस सरकार ने जनता को क्या दिया? इस सरकार के बनने के कुछ ही महीनों में भाई-भतीजावाद और हुड्डा कांड जैसे आक्षेपों की वजह से सरकार को इस्तीफे देने पड़े। यह इस सरकार की पहली उपलब्धि इतने कम समय में मेरे ख्याल से इतनी जल्दी हिन्दुस्तान में कहीं

नहीं हुई होगी। अगर मैं कहीं पर गलती पर होऊंगा तो जो साथी साहेबान बैठे हैं बता देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बजट का मदो को, नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने की जो मन्ता जाहिर की है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट का और इस बजट का भी अध्ययन किया है। यहां पर आर्य साहब ने और एक दो दूसरे साथियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा के सारे विकास का मलियामेट कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नुक्ताचीनी में जाना नहीं चाहता। मैं अपनी बात कहना अपना फर्ज समझता हूँ।

मैं बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा बना तो यहां पर कुछ नहीं था। सारा हरियाणा एक रुखा सूखा प्रदेश था। जिस समय हरियाणा बना उस समय इस हरियाणा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हरियाणा अपना अस्तित्व कायम रख पायेगा और हरियाणा में दो अढ़ाई साल के पीरियड को छोड़ कर कांग्रेस की ही हकूमत रही है। जिस समय हरियाणा प्रदेश बना उस समय यह ग्याहरवें नम्बर का प्रदेश था लेकिन आज सारे हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है। मैं यह आंकड़े इसलिए देना चाहता हूँ कि रुलिंग पार्टी के माननीय सदस्यों ने काफी जिक्र किया था। जिस समय हरियाणा बना उस समय यह कृषि के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था। अपना गुजारा भी नहीं कर पाता था। उस समय 25.92 लाख टन अनाज पैदा होता था लेकिन आज आप देखिए कि पैदावार 70 लाख टन तक के लगभग पहुंच गयी है।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम विलास भार्मा): आन ए
प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, बडे खेदकी बात है कि
आपके बार बार कहने के बाद भी हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य
अपना ऐक्सप्रेषन इस तरह से देते है जैसे हरियाणा के बजट के
संबंध में ही न बोल रहे हो बल्कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट को री-प्रेजैन्ट
कर रहे हो। ये बहुत पुराने सदस्य है। इन्हे बजट के बारे में
बोलना चाहिए। जब भी ये कोई बात बोलते है तो ऐसा लगता है
जैसे सैन्ट्रल गवर्नमेंट को री-प्रेजैन्ट कर रहे हो। ये हरियाणा
असैम्बली के मैम्बर है। ये अपने हलके की समस्या के बारे में
कहे। जब भी केन्द्र के बारे में पक्षपात की बात आती है तो इस
तरह की बातें करते है। इसके बारे में मैं आपकी रुलिंग चाहता हू।
माना कि ये कांग्रेस पार्टी के मैम्बर है लेकिन पिछली बातों का
जवाब देना इनका हक नहीं बनता। आज के दिन हरियाणा सरकार
धडाके से चल रही है। सरकार ने बजट पे ठोस किया है, इसकी
कापी इनके पास है। वे कोई सुझाव दें या किसी नीति की
आलोचना करें। जब ये बोलते है तो पिछले आंकडे लेते है। इसी
प्रकार से तैयब हुसैन जी भी पिछले आंकडे देते है। ये सैन्ट्रल
गवर्नमेंट के री-प्रेजैन्टेटिव के नाते यहां नहीं है और न ही ये
पार्लियामेंट के मैम्बर है, ये असैम्बली के मैम्बर है। ये यहां बार
बार पिछली सरकार की सफाई देते है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये
विद इन लिमिट और विद इन प्रोविजल बोले। क्या दिल्ली की
सरकार की सफाई देने की जिम्मेदारी इनकी है? कांग्रेस के एम0
पी0 यहां बैठे हुए है। वे यहां सफाई देते रहते है। पिछली सरकार

का कोई वारिस नहीं था। पिछली सरकार की परफौरमेंस ठीक न होने के कारण लोगो ने उसे भगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी का आदर करते हैं लेकिन पता नहीं ये सो रहे हैं या कोई और ही बात पर विचार कर रहे हैं। मैंने अभी तक यहां पर केन्द्रीय सरकार का कोई जिक्र नहीं किया। मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं। पता नहीं कौन सी आवाज में ये बोल रहे हैं? जब सत्ता पक्ष की ओर से गलत आंकड़े दिए जाते हैं और कांग्रेस की बुराई करते हैं तो ये चुपचाप बैठे हुए हंसते रहते हैं। उन गलत आंकड़ो को सही करने के लिए हम ये आंकड़े देते हैं और जो सत्ता पक्ष की तरफ से गलतब्यानी की जाती है, उसके जवाब में जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है तो फिर चिल्लाने लगते हैं (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीर पाल सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य श्री मांगे राम जी ने अपने हलके के पिछडेपन की बातें कही थी। उनके बारे में इनको क्या ऐतराज है? आज यह कहते हैं उनके हलके में छः महीने में गढढे पड गये हैं और चालीस साल में उन गढढो को दूर नहीं कर सके जो दूसरो के हलके में पडे हुए हैं। अगर विरोधी पार्टी के लोग

आज सत्ता में आए है, और अपने हल्के की समस्याओं के बारे में कहते हैं तो इनको क्या दर्द होता है?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस की बुराईयां करने से ये उसकी उपलब्धी और मान्यताओं को खत्म नहीं कर सकेंगे। इन सारी बातों को प्रदेशों के लोग जानते हैं। जहां तक पेय जल की बात है, ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि 85 परसेंट उसी कांग्रेस ने पेय जल मुहैया किया था। (विधु) उपाध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा इन्डस्ट्री के लिहाज से पिछड़ा हुआ था आज यहां 77 हजार से उपर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं। अगर हिन्दुस्तान में पांच ट्रक्टर्ज बनते हैं तो तीन ट्रक्टर्ज हरियाणा में बनते हैं। यह गौरव भी प्रदेशों को ही हासिल है। इन डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इनका जिक्र गवर्नर साहब के ऐड्रेस में भी हो गया था। ये मान्यताएं और उपलब्धियां इनके कहने से कम नहीं हो सकती। जहां तक बजट का ताल्लुक है, बजट में कृषि के लिए जो व्यवस्था है वह काफी कम है। (व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Mr. Mahender Partap ji, do not waste time of this august House. Do not be irrelevant.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, सिंचाई और बिजली के लिए 285 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। अगर पिछले कांग्रेस बजट को देखा जाए ओर इन

दोनो बजटो का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह बजट कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 12 या 13 प्रति सैत कम बनता है। पिछले बजट में करीब 352 या 354 करोड रुपये की राशि सिंचाई तथा बिजली के लिए उपलब्ध करवाई गई थी और आज इस सरकार ने 285 करोड रुपए का बजट इस आय के लिए रखा है यानि 47 प्रति सैत जबकि 1987-88 में यह 60 प्रति सैत बनता था। इस प्रकार इस बजट से सरकार की किसान सम्बन्धी नीति और प्रोग्राम परिलक्षित होते है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सरकार से यह कहूंगा कि कृषि हमारे राज्य का बेस है। वैसे तो उद्योग भी हमारी अर्थ-व्यवस्था के बेस है। कृषि क्षेत्र के लिए जितना पैसा कांग्रेस सरकार के समय में मिल रहा था उसको देखते हुए तो इस बजट में उसे बढ़ाया जाना चाहिए था परन्तु वर्तमान सरकार ने उसे बढ़ाने की बजाये घटाया है। इसके साथ ही पिछले बजट के मुकाबले में अब तक रुपये का जो अवमूल्यन हुआ है और जो मंहगाई बढ़ी है उसको मैंने इस में शामिल नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय ने वर्तमान बजट को पिछले बजट की अपेक्षा कम किया है। हमारी सरकार ने अपने 1987-88 के बजट में 585 करोड रुपये का प्रावधान योजनागत बजट में किया था। जो बजट हमारी सरकार ने 1986-87 के लिए पेश किया उसमें हमारी सरकार ने सवा पांच करोड से 565 करोड तक बढ़ाया जो कि सरकार की विकास नीति का द्योतक है। इस सरकार ने उसको घटा कर 438 करोड यानि करीब 150 करोड

रुपये कम किया है। (व्यवधान) गुप्ता जी, जहां तक जिम्मेवारी का ताल्लुक है, कांग्रेस राज में बजट कभी भी घटाया नहीं गया। अगर एक ही साल में इसे घटाने की बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर ही आती है। ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी, अब आप वाईण्ड अप करिये क्योंकि आपको बोलते हुए 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बोलना भुरु ही किया है। मुझे कुछ और समय दीजिए। (विघ्न) केन्द्र सरकार ने रिजर्व बैंक को आदे 1 दे रखे है कि किसी भी स्टेट को ओवर ड्राफ्टिंग की इजाजत न दी जाए। जब ओवर ड्राफ्ट नहीं हो सकता था, जून में आपको सत्ता मिल गई थी, बजट अप्रैल से भुरु होता है, और बजट का सारा पैसा इकटठा एक दम पूल में नहीं आता तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपये का घाटा कैसे छोड़ा? जहां तक रिजर्व बैंक के खातो का ताल्लुक है, हर भानिवार को रिजर्व बैंक के साथ सारे बैंको के खातो का जमा और खर्च मिलान होता है, उसके मुताबिक 45 करोड़ रुपये उस समय खाते में जमा है। यह रिकार्ड की बात है। अगर फिर भी यह बात ये कहते ळे तो सत्य पर पर्दा डालना ही होगा। (विघ्न एवं भाोर)

उप-मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): जो बातें तैयब हुसैन जी कह चुके हैं, उन्हीं बातों को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने वे सभी बातें नोट कर रखी हैं और उनका जवाब दूंगा।

Mr. Deputy Speaker: Mr. Mahender Partap Singh, no repetition please.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिटेल्स बताई हैं कि रिजर्व बैंक के खातों का मिलान इस बात का सबूत है। इन्होंने 45 करोड़ की बात की है। मैं तो आंकड़ों और रिकार्डों की बात बता रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की उपलब्धियाँ और भाव के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें पहले भी इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है कि हरियाणा सरकार दे आ में सबसे ज्यादा गन्ने का साथ दे रही है। भावों में आठ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ौतरी की गई है। लेकिन आज अधिकतम मूल्य 32 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बता दूँ कि ऐसा कहकर केवल लोगों को भ्रमाने की कोशिश की गई है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने माना है कि सी० ओ० जे०-64 गन्ना कुल 11.7 प्रति आत ही बोया जाता है। सी० ओ० जे०-64 किस्म के गन्ने का भाव हरियाणा में 28 रुपये प्रति क्विंटल था जो कि अब बढ़ा कर 32 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इस प्रकार इस में 4 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाये गये। मीडियम गन्ने का भाव

पहले 27 रुपये प्रति क्विंटल था जो कि अब बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल किया गया और जनरल कैटेगरी के गन्ने का भाव 25 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 28 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इस प्रकार इन दोनों गन्नों की किस्मों में 3-3 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की गई है। पता नहीं ये गलतब्यानी कैसे करते हैं? आठ रुपये प्रति क्विंटल बढौतरी का कौन सा हिसाब है, मैं इस समझ नहीं पाया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस भाव का ताल्लुक है, यू0 पी0 के भाव में और हमारे भाव में कोई फर्क नहीं है। यू0 पी का भाव 28 रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन वहां पर किसानों से भाडा 50 पैसे प्रति क्विंटल लिया जाता है। हमारे यहां यह भाडा सवा रुपये और डेढ रुपये लिया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा भाव साढे छब्बीस रुपये रह जाता है। मुझे याद है और अखबारों में भी आया था कि सरकार बनने से पहले इनकी पार्टी ने गन्ने का भाव 35 रुपये प्रति क्विंटल मांगा था, लेकिन ये इलैक्शन से पहले और बाद की बातें हैं। उन बातों को सरकार कहां तक पूरा कर पाती है यह देखने की बात है। मैं कहता हूँ कि गलत उपलब्धियों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जहां तक शिक्षा की बात है शिक्षा के बारे में मैंने एक सवाल पूछा था। शिक्षा एक बुनियादी जरूरत है और शिक्षा के बिना समाज का सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। लेकिन पिछले इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि इस साल 10 जमा 2 प्रणाली मिडल व हाई का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। तो इस नजरिए

को विकासी नीति कहा जाए यह आप स्वयं फैसला कर सकते हैं। यहां पर कर्जा माफी का बहुत जिक्र आया। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इस पर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय बहुत कुछ कह चुका हूँ। लेकिन जनता आज भी भ्रम में पड़ी है, जनता को यकीन नहीं है कि कोआप्रेटिव का 44 करोड़ रुपया दे जायेंगे या नहीं। यहां पर सूखा राहत के लिए भी जिक्र आया है। इनको सूखा राहत के लिए 37.5 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से मिले हैं। इसके अलावा इन्होंने माना है कि 3.5 करोड़ रुपया सूखा राहत कोश में भी आया है जो विभिन्न सोर्सिज से आया है। उसमें से सरकार ने सूखा राहत देने की कोशिश की होगी। सारे प्रदेश में सरकार इसके लिए कितना कर पाई है, मुझे उसकी असली जानकारी नहीं है इसलिए मैं यहां पर गलत बात नहीं कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट और जनता से करोड़ों रुपये इस काम के लिए लिया गया है। लेकिन सूखा राहत के लिए फरीदाबाद को जो ऐलोकेशन दी गई है वह केवल दो लाख रुपये खर्च है। जिस जिले को ये सूखा ग्रस्त कहते हैं उस पर केवल दो लाख रुपये या थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। चार कांस्टीच्यूएंसीज के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वहां पर न के बराबर खर्च किया गया है। इसके अलावा कहीं कोई राहत कार्य नहीं हुआ। इससे ज्यादा सूखा राहत को और क्या मजाक हो सकता है वहां के लोगो ने सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से चारा खरीदा है। (विघ्न) हमारे वक्त में भी सरकार ने राहत कार्य में व्यक्तिगत तौर पर

कै 1 आदि के रूप में देने की भरपूर को 1 1 की थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सरकार के आदर्शों का एक नमूना रखना चाहता हूं। लक्ष्मी कान्त प्यारे लाल नाइट करनाल और फरीदाबाद में मनाई गई थी। मैं सरकार की उस नीति की चर्चा यहां पर करना चाहता हूं जिस के तहत सरकार को तो सिर्फ लगभग 10-12 लाख रुपये मिल सके लेकिन जिन लोगों की अखबारों में भी काफी चर्चा की गई जो बीच में बिचौलिया थे, भागे करने वाले थे, उन्होंने 30 लाख से ऊपर रुपया अपनी जेबों में डाल लिया। जनता का पैसा इस भाग में खर्च होकर जनता के असली काम में न आये, यह तो भार्म की बात है। सरकार की अविवेकपूर्ण नीति का इससे ज्यादा और क्या नमूना हो सकता है। पंजाब समझौते, एक वाई एल और सुरक्षा पट्टी का भी यहां पर सवाल आया।

श्री उपाध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं। आप कृपया वाईड अप करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: बहुत अच्छा जी, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मैं इसके लिए पहले भी जवाब दे चुका हूं। भारत सरकार ने देश के हित को देखते हुए इस बात की को 1 1 की है कि पंजाब और दूसरे जो अहम मामले हैं, उनको हल किया जाये। इस बारे में हाउस के फ्लोर पर कई बार चर्चा हो चुकी है। इसी हाउस में कई बार एस0 आइ0 एल0 पर भी बहस हो चुकी है। उसके लिए कांग्रेस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे जो साथी यहां पर कह रहे थे वे पंजाब समझौते के बारे में अगर

इंदिरा जी के फैसले की हिमायत करते तो भाायद बात ही कुछ और होती। लेकिन उस वक्त उन्होंने उस अवार्ड की हिमायत नहीं की वरना वह फैसला लागू हो गया होता। पंजाब समझौता और एस० वाई० एल० का एक ऐसा मामला है जिसकी हम ईमानदारी के साथ हिमायत करते हैं। इसका सवाल हमारी लाईफ लाईन से जुड़ा है। हम उनसे पीछे नहीं हैं। चौथे वेतन आयोग का भी यहां पर जिक्र आया है कि पहली स्टेट है जिसने यह दिया है। अगर हमारे साथी इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो उस वक्त पी० डबल्यू० डी० के पन्द्रह हजार के करीब कर्मचारी जिनकी नोटीफिके 1 न भी हुई पडी है ऐडहाक पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में पिछली सरकार ने यह प्रोविजन किया था कि पक्का किया जायेगा लेकिन उनको आज तक भी पक्का नहीं किया गया है। उनको पक्का कर दिया जाए। जहां तक एम्पलाईज को पै 1 न देना का ताल्लुक है, केन्द्रीय सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारि 10 के अनुसार इसे 1-1-1986 से लागू किया है। मैं तो सरकार की ठीक भावना तब मानता जब चौथे वेतन आयोग की सिफारि 10 के अनुसार सैंटर की तरह से 1-1-1986 में पै 1 नरो के लिए भी इसे यह लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष: कृप्या आप वाईड अप करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा तो नहीं कहता। आखिर में मैं इतनी ही बात कहूंगा कि जहां तक सरकार की इस बात का ताल्लुक है कि कर

नहीं लगाये गये, मेरे एक साथी ने जिक्र किया कि यह कर-मुक्त बजट है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कर-मुक्त नहीं है। कर लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। बजट से पहले ही बिजली की दरें बढ़ाई गईं, बस किरायों में वृद्धि की गई हालांकि डीजन के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। भाहरों में यह हालत है कि पानी और सीवरेज के रेट्स पहले के मुकाबले एकदम डबल कर दिये गये। मैं यह समझता हूँ कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ यह अन्याय है। अगर कर बढ़ाये ही जाने थे तो ठीक रहे तो व बैलेनस को ध्यान में रखकर ऐसा करते। बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, भाहरों में, बिजली के मीटर की सिक्क्योरिटी 130 रुपये मीटर पुराने कंज्यूमर्स से ली और ऐक्सट्रा ली जा रही है। किसान का 50 रुपये पर मीटर, 100 रुपये, 200 रुपये और 400-500 रुपये मीटर लोड के हिसाब से हो रहा है। इस हिसाब से मीटर की सिक्क्योरिटी के रूप में पुराने कंज्यूमर्स से चार्ज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब कर पहले ही बढ़ा लिए गये थे, तो दोबारा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जहाँ तक सुखा कार्यों का ताल्लुक है, आज स्टेट की जो हालत है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ तो हम सैंटर से रुपया मांग रहे हैं कि हमें वह इसक लिए पैसा दे लेकिन दूसरी तरफ मंत्रियों की तनख्वाह और टी0 ए0 डी0 ए0 डबल किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बड़े ही भार्म की बात है। ऐसे समय तो कम से कम हमें जनता के प्रति अपने फर्ज का ध्यान रखना चाहिए था और अगर कुछ व्यक्तिगत त्याग भी कर सकते तो अच्छा था। उपाध्यक्ष

महोदय, जहां तक विकास कार्यों का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने बजट के दो आंकड़े और टारगैट्स हैं, वे भी पूरे नहीं किए गए हैं। इससे जाहिर होता है कि विकास कार्यों में कई बहुत बड़े प्र न चिन्ह लग गये हैं। इसे देखते हुए मुझे एक बात याद आती है। मैं जरा कह दूं तो धीरपाल जी उस पर चौंकेगे तो सही। मैंने पहले ही कह दिया कि जहां तक सरकार की कारगुजारी और उपलब्धियों का ताल्लुक है अगर उनके बारे में न कहा जाए तो वह ठीक नहीं होगा। ठीक नौ महीने के बाद इस ि। ु रुपी बजट का जो जन्म हुआ है कर्जा माफी व रघु जी की बेरोजगारी सेना को निरीह व मायूस अवस्था में वह हम कांग्रेसी सदस्यों की तरफ देख रहा है कि मुझे सम्भालो। उपाध्यक्ष महोदय, आज विकास कार्यों की हरियाणा के अन्दर जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं है कि हुड्डा कांड गूंज रहा है कहीं राठी कांड गूंज रहा है और कहीं और दूसरे कांड गूंज रहे हैं (गोर एवं व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय, आपने रघु यादव को बोलने का समय नहीं दिया। इस बारे में मैं कहावत सुनाता हूं। रघु यादव के गांव में एक बूढ़ी महिला थी। उस गांव में एक चक्की खोटने वाला आ गया। उसने उस बुढिया को कहा कि माई चक्की खुटवा ले। बुढिया ने कहा मैं तो बड़े दिन से इंतजार में थी। जब वह चक्की खोटने लगा तो चक्की पर उल्टी सीधी चोटें मानी भुरु कर दी। (गोर एवं व्यवधान) चक्की टूट गई। बुढिया पानी लेने गई हुई थी। उस आदमी ने सोचा कि बुढिया की चक्की टूट गई है अगर जल्दी लौट आई तो तेरी खासी मुरम्मत होगी। वह अपने औजार

लेकर भागने लगा। जल्दी में वह छींके से टकरा गया। उसका माथा छींके से लगा। छींके पर एक हाण्डी रखी थी। वह गिर गई और टूट गई। वह आदमी जल्दी में भागा और आगे किवाड से जा टकराया। किवाड की चूल टूट गई। वह तेजी से भागा। सामने से बुढिया आ रही थी। जल्दी में वह बुढिया से टकरा गया और उसका पानी का घडा टूट गया। बुढिया ने कह रमलू तेरा सत्याना । जाए। तूने बहुत बुरा किया, तेरे लिए कित बैठ के रोऊं। (गोर एवं व्यवधान) रमलू ने कहा माई घर जाएगी तो देखकर रोएगी। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हरियाणा के विकास कार्यों की ठीक उस बुढिया की तरह की ही हालत है। आगे चलकर जो भी इसे देखेगा वह रोयेगा। (गोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को वित्त मंत्री जमा उप-मुख्य मंत्री ने जो बजट पे । किया उसके लिए वे बधाई के पात्र है क्योंकि उन्होने कोई कर नहीं लगाए। मुझे डर लग रहा था कि जनता में जाएंगे और अगर कही टैक्स लग गए तो जनता को क्या कहेंगे। टैक्स न लगाकर ये प्रदे । की जनता के बधाई के पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होने जनता के सामने बिल्कुल साफ पिक्चर रखी है और इन्होने कोई बात छुपाई नहीं है। इन्होने कहा कि भारत सरकार ने नया फाइनेंस कमी । न अप्वायंट किया लेकिन हरियाणा सरकार से इस बारे मे नहीं पूछा।

उपाध्यक्ष महोदय, टर्म्ज आफ रैफरेन्स के अन्दर यह जरुरी होता है कि ह इस बारे में स्टेट सरकारो से पूछे। इस दे 1 में संघीय अर्थात् फ़ैडरल स्ट्रकचर है लेकिन केन्द्रीय सरकार उसको तोडने पर आमदा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यूनिटरी फार्म और गवर्नमेंट नही है। यहां फ़ैडरल फार्म आफ गवर्नमेंट है और स्टेट की तथा सैंटर की पावर्ज बहुत क्लीयरली डिफाइन्ड है। हर पाच साल के बाद जब भी कमी इन अप्वायंट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट से सलाह जरुरी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय एजेन्सी हरियाणा में तथा दूसरे राज्यों से पैसा वसूल करती है उसका बंटवारा राज्य सरकारो को देना होता है। केन्द्रीय सरकार ने टर्म्ज आफ रैफ़ैन्स को एक तरफ उठाकर रख दिया और हरियाणा की बात को अनदेखी कर दिया। मै पुरजोर अल्फाज में केन्द्रीय सरकार की मुरम्मत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने सैंटर में जो बजट पे 1 किया उसमें इन्कम टैक्स ऐक्ट भी एक सं गोधन का जिक्र किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, सैव इन ए (सी) में कहा गया है कि चाहे भाराब के ठेके, जंगलात या स्कैप आदि निलाम होंगे तो उसमें से 100 रुपये के पीछे 60 रुपए को इन्कम माना जाएगा और उस 60 रुपये का 20 परसैंट पहले जमा करवाना पडेगा। इस सैव इन का प्रदे 1 के कई मुख्य मंत्रीयों ने जमकर विरोध किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी विरोध किया लेकिन कौन सुनता है। डिप्टी स्पीकर साहब, सब बातें अनसुनी कर दी गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने किसी की भी नही सुनी और अपनी मनमानी की। मेरे

अपोजी इन में बैठे भाई, महेन्द्र प्रताप सिंह जी, तो भायद चले गये है लेकिन तैयब साहब बैठे है, सदा ही इस बजट के खिलाफ कहते है। मैं उन से पूछता हूं कि आप की सरकार का बजट क्या बहुत अच्छा था जो जनता ने आपकी नसबन्दी करके यहां पर भेजा है? (हंसी) यानि भाई कर के यहां पर भेजा है। उस समय तो बडा भाोर किया करते थे, थंपिंग किया करते थे। वैसे तैयब साहब यह महसूस किया करते थे कि बजट वाकई सही नहीं था लेकिन क्या करते, सरकार में तो रहना था। चौधरी देवी लाल जी की बात नहीं मानी, अगर मानते तो ठीक रहते। फिर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि चन्दा लेते समय रसीदों के नाम बताओ कि किस किस से पैसा लिया गया? मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तैयब जी पूछ कर क्या करोगे? क्या आप भी वहां पर पहुंचोगे? उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मुख्य मंत्री महोदय की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि पहले इनके वक्त में मुख्य मंत्री कोश में रुपया जाता था, वह जाता था अपनी राहत के लिए लेकिन अब जो मुख्य मंत्री कोश में रुपया जाता है वह जनता की राहत के लिए जाता है। (तालियां) इनको इतना कहते हुए सच्चाई का ध्यान रखना चाहिए लेकिन इन्होंने तो यहां पर ऐसी बात कहनी ही नहीं जिसमे सच्चाई हो। मैं अपने भाई तैयब साहब से पुछना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स ला में कौन संोधन ला रहा है? वह भारत सरकार ला रही है। उसके लिए उसकी निन्दा न करें तो क्या करें? आखिरकार यही फोरम है और ऐसा कहना हमारा कांस्टीच्यू इनल राईट है। This is the proper forum where we

can criticize it. (interruptions) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कुछ नहीं कहता। नाना पालकी वाला जोकि भारत वर्ष के माने हुए वकील है और कानून के विशेषज्ञ है उन के बहुत से आर्टिकलज है जो कि इस वक्त मेरे पास है। अगर मैं उनको पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा।

Mr. Deputy Speaker: Dr. Sahib, Wisdom lies in brevity.

श्री मंगल सैन: ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद में यह कहना चाहता हूँ कि सूखे के दिनों में भी केन्द्र की सरकार ने हमारी मदद नहीं की लेकिन हमने सीमित साधनों के होते हुए भी किसानों को सस्ते दामों पर चारा उपलब्ध करवाया। हमारे ये भाई इससे नाराज हैं उल्टा हमसे बार बार पूछते हैं कि उन रसीदों के नाम बताइए। मैं तो आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें, इन्हीं बातों से सन्तोश करना चाहिए कि यह सरकार लोक लाज से चल रही है। अभी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह कैबिनेट रीफ़ाल की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सैन्टर की सरकार की कितनी बार रीफ़ालिंग हुई है। मेरे खयाल में पौने दो दर्जन बार तो हो चुकी है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने यह देखना होता है कि सरकार कैसे चलानी है और कैसे ठीक चल सकती है। मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि जो मैम्बर उन्हें पसन्द आए उसको अपनी कैबिनेट में ले सकते हैं। यह उनकी इच्छा है, यह उनका

प्रिरोगेटिव है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र जो कांग्रेसी बेंचो पर बैठे हैं इन्होंने रीकंसाइल नहीं किया। तैयब साहब कभी कांग्रेस में कभी अपोजी उन में आते जाते रहे हैं। हमारे भाई महेन्द्र प्रताप इस समय हाउस में नहीं हैं, उठकर बाहर चले गए हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहता था कि उनको लोकदल पार्टी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उनको असैम्बली का मुह दिखा दिया। पहले तो वे लोकदल की टिकट पर ही जीत कर आए थे। (इस समय चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह सदन में आ गए) डिप्टी स्पीकर साहब, भाई महेन्द्र प्रताप सदन में आ गए हैं मैं इन्हीं का जिक्र कर रहा था कि ये पहले लोकदल की टिकट पर ही चुनाव जीत कर आये थे। वे मेरे भाई इस बात को इंकार नहीं कर सकते। 1982 में मेरे भाई हमारे साथ चुनाव जीत कर इस असैम्बली में आए थे लेकिन बाद में ये उधर ट्रेजरी बेंचिज की तरफ चले गए। यह इखलाफ का तकाजा है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर इनको ऐसा ही करना था तो पहले ये असैम्बली से त्यागपत्र देते और उसके बाद चुनाव जीत कर आते फिर हम देखते कि इनको लोकदल चुनाव जीतने देता या नहीं मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं भूल चुक हो ही जाती है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जहां तक 1982 के चुनावों का ताल्लुक है इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे इनकी मदद मिली थी जिसके लिए मैं इनका भुकीया अदा करता

हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 1982 के चुनावों का ताल्लुक है उस समय कांग्रेस की वेव थी उसी समय मैं लोकदल और बी० जे० पी० के सहयोग से इस हाउस में आया था लेकिन 1987 में जब लोकदल पार्टी की कांग्रेस के खिलाफ वेव थी उस वक्त मैं इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त करा कर आया हूँ और 29000 वोटों से जीत कर आया हूँ। इसके अलावा यदि मैं और बात कहूँ तो उस लाईन में बड़े बड़े लोग आ जायेंगे क्योंकि ये बातें कई बार हो चुकी हैं।

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी ही बात अर्ज कर रहा था कि इन मेरे भाई साहब को इस अगस्त हाउस में हर बात बुरी दिखाई दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, रही बात जमानत जब्त कराने की तो राजनीति में ऐसा ही चलता है कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है इसमें कभी भी किसी को नखरा नहीं करना चाहिए। because pepe are supreme. Sir, वे जो करें वह ठीक है। मैं तैयब साहब से कहना चाहता हूँ कि रास्ता बिल्कुल साफ है और मंजिल सामने है, अर्जुन की तरह दिखाई दे रही है कि दिल्ली की राजनीति पर हमारा कब्जा होने वाला है। आपने यह कैसे कह दिया कि हमारी सरकार दि ग्राहीन है। We are very well in direction and we are having patritic spirit, Sir.

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने फरमाया है कि सरकार ने सुखे की राहत के लिए किसानों की कोई मदद नहीं की। इसी प्रकार से यहां पर जिक्र आया कि करनाल में कोई स्टार नाईट

हुई है। ऐसी नाईटो का आयोजन चैरीटेबल संस्थाओ द्वारा होता रहता है। जिस आदमी ने इस नाईट का आयोजन करवाया उसके बारे में मैं क्या कहूँ? ऐसे व्यक्तियों के बारे में माया, मनोहर कहानियों में जिक्र आता रहता है। माया, मनोहर कहानी में किसी कंवलजीत सिंह नाम के व्यक्ति का जिक्र आया है। सुबह जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे कोई कहने लगा कि डा० साहब आप क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन चीजों के बारे में भी कभी कही पर जिक्र करना पड़ सकता है। जिस कंवलजीत सिंह व्यक्ति का जिक्र आया है उसके बारे में मैं यह कहूँगा कि यह कहां से गलत आदमी आया है, इसके बारे में सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कांग्रेस के लोगो में तो पुरानी आदत है और इन्होंने सारे हथकंडे देखे हुए हैं और अपनाए हुए हैं। ये इस सरकार के बनने पर कहते थे कि यह सरकार नहीं चलेगी। फिर इन्होंने भाोर मचाया कि इतने रुपए ले लिए, उतने रुपये ले लिए लेकिन अपनी बात नहीं कहेंगे। भजन लाल कोई दुध का धोया हुआ या राख का मांजा हुआ नहीं है। इनको पहले अपनी आदत ठीक करनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है, मुख्य मंत्री जी तो इस समय हाउस में बैठे नहीं हैं, भाायद मेरी बात सुन रहे होंगे। हरियाणा में एक लोकायुक्त कानून बनाया जाना चाहिए। केरल में वहा की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें वहां के सी० एम० साहब, के रि तेदार ही नहीं बल्कि जो नजदीकी लोग राजनीति में हैं या दूसरे हैं यदि उनकी आय से अधिक सम्पत्ती होगी तो उनकी भी

जांच हो सकती है। चौधरी देवी लाल संघर्ष के बूते पर लडाई लड कर चीफ मीनिस्टर बने है और इस लडाई में हमने भी उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर लडाई लडी है। हम ऐसी तपस्या को आंच नहीं आने देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त कानून बनाये जाने के बारे में मैं सुझाव दूंगा कि चाहे सदन की समिति बना ली जाये या चौधरी देवी लाल जी या गुप्ता जी कोई समिति बना लें, जो सारे देश भर के कानूनों का अध्ययन करके एक ऐसा कानून बनाए जिसके तहत सभी लोग पकड में आ सकें और आगे से कांग्रेसी भी कोई हेरा फेरी न कर सकें तथा केन्द्र भी हमारे कानून की नकल करने पर मजबूर हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात मैं मैं तबरे के तौर पर कहना चाहता हूँ। हरियाणा की पुलिस के बारे में बोलते हुए मैंने गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जिक्र किया था। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि लैण्ड ग्रेबिंग का मैंनेस थोडा सा सिर उठा रहा है। इसके बारे में मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसे सख्ती से दबा दिया जाए। पीछे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें कही थीं। उसी संबंध में मैं आज फिर कहता हूँ। जिन लोगों की लाटरी निकलती है उनसे कुछ लोग यदि एक लाख रुपये का इनाम है तो सवा लाख रुपए देकर टिकट खरीद लेते हैं और अपने काले धंधे के पैसे को सफेद में बदलने की कोशिश करते हैं। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ चाहे वे कोई अफसर हैं या और कोई काले धन्धे करने वाले व्यक्ति हैं, सख्त

कार्यवाही की जाये। हमारी सरकार अपने भ्रष्टाचार बन्द के नारे को असली रूप दे और बिजली व पानी का आम लोगो के लिए प्रबंध करे ताकि आने वाली पीढी यह कह सके कि किसी समय यहां पर सुनहरे काम करने वाली सरकार रही थी जिसने भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो बातों की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी वकीलो द्वारा की जा रही हडताल के संबंध में दिया था। आप भी वकील हैं और बहुत सारे साथी भी वकील हैं। मैंने भी वकालत पढी है लेकिन काला कोट नहीं पहना है। मुझे भी मजबूरी में वकालत पढनी पडी क्योंकि यहां आने पर इस संबंध में ज्ञान अनिवार्य हो गया था। वकीलो द्वारा सारे देश में हडताल काफी दिनों से चल रही है। हमारी सरकार को दिल्ली की सरकार से कहना चाहिए कि इस हडताल को लम्बा न खिंचवाया जाए। (विधन्) हमारे यहां पर भी मुकदमें लटक रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वकीलो की हडताल का जिक्र कर रहा हूं। चण्डीगढ़ के वकील तो भूख हडताल पर बैठे हैं। एक अफसर के लिए यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार केन्द्र पर दबाव डाल कर इस हडताल को समाप्त करवाये ताकि यहां के केशो का निपटारा हो सके।

17:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे हलके रोहतक के अन्दर एक

यूनिवर्सिटी है। वहां पर काफी समय से वाईस चांसलर नहीं है। वहां पर पहले एक ऐसा वाईस चांसलर भी रहा है जिसने नम्बरो मे गडबड करवाई है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि वहां पर ऐसा वाईस चांसलर लगाया जाये जो पालिटिकल न हो बल्कि शिक्षाविद हो चाहे वह हमारे स्टेट का हो या दूसरे प्रदे का। यूनिवर्सिटी का वातावरण शिक्षा पढने और पढाने का होना चाहिए। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि करनाल में जो लिबर्टी भूज फ़ैक्टरी हे उसके अन्दर हडताल चल रही है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने उनके बारे में कह दिया कि आप अपना गुड आफिस इस्तेमाल करके हडताल खत्म करवा सकते है। लेकिन जो लोग मरण व्रत पर बैठे हुए है उनकी तरफ भी तो हमें देखना है। यह सरकार किसान, मजदूर और मेहनतकशों की सरकार है। इस सरकार के सामने पुजीपति इस बात का जोर दिखाए कि मजदूरों को मिनिमम वेजिज नहीं दे, मनमर्जी से किसी मजदूर को निकाल दें और लेबर कमीशन की भी न सुनें तो बहुत ज्यादाती है। इसलिए मैं मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ साथियों से कहूंगा कि उन मरने वालों को मरने से बचायें।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे काफी टाईम दिया है उसके लिए आपकी बडी मेहरबानी है। इस बजट में मुख्य बात यह भी है कि हमारी सरकार बिजली और विशेष ध्यान दे रही है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि बिजली की प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट पार्टिज को भी आमंत्रित किया है। यह बहुत अच्छा

काम है। बिजली, कृषि विकास और घरों के लिए हमारे यहां पर्याप्त नहीं मिल रही है इसलिए उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी उन्हें बधाई देता हूँ ऐसा करने से आयादा के लिए बिजली में सुधार होगा।

इसके साथ साथ मैं एक बात गुप्ता जी से ओर कहना चाहता हूँ। गुप्ता जी के पास बहुत लम्बा चौड़ा वित्त विभाग है लेकिन उसके साथ ही उन्हें स्थानीय निकाय विभाग भी दिया हुआ है। उस विभाग के अफसरों में बड़ी बेअदबी आ गई है। वे समझने लगें हैं कि हम ही मालिक हैं और यु चुने हुए नुमायंदे कुछ नहीं हैं। दूसरे मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कमेटियों को दिल खोल कर पेसा दिजिए। जहां पर चीफ ऐग्जिक्टिव ऑफिसर आपके इ पारे को नहीं समझते, आपकी मं ता को नहीं समझते ओर आपकी भावनाओ का आदर नहीं करते उनके साथ वैसा ही सलूक कीजिए। इन बातों को कह कर मैं बजट का समर्थर करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

कामरेड हरपाल सिंह (टोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पे ता किया है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए खडा हुआ हूँ। इस बजट स्पीच में केन्द्र और राज्यों के संबंधी के बारे में भी जिक आया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हिन्दुस्तान में जहां भी विपक्ष की सरकार है उनके साथ पैसा देने के केन्द्रीय सरकार की ओर से भेदभाव किया जाता है। उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। यह केन्द्र की लगातार नीति रही है कि

विपक्ष के साथ भेदभाव किया जाता है। केन्द्र और राज्य के आर्थिक और राजनैतिक संबंधों को तय करने कासवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ मैं कर्जा माफी के बारे में कहना चाहता हूँ। कर्जा माफी का जो कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन एक बात सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस कर्जा माफी में छोटे खेतीहर मजदूर, छोटे दुकानदान, कारीगर और गरीब किसान नहीं आये हैं, क्योंकि इन लोगों ने नै ननेलाइज्ड बैंको से कर्जा लिया हुआ था। इस कर्जा माफी का फायदा जागीरदार और बड़े बड़े जमींदारों ने उठाया है। जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उन्होंने इसका फायदा उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सर छोटू राम का भी जिक्र आया है। देहात कज्र राहत का कानून छोटूराम ने पास किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। उस कानून के पिछे आधारभूत बातें थी। अदालत की डिक्री से किसी किसान का घर, बर्तन, बैलगाड़ी, पशु, जमीन, 25 मन अनाज, खेती के औजार और गितवाडा नीलाम नहीं किया जा सकता था। इस कानून को हरियाणा में दोबार से लागू किया जाए। आज भी हमारे पास िकायतें आयी है। फतेहाबाद में मलौरी धर्मपत्नी श्री मातु राम कुम्हार काठमंडी के घर को 26 हजार में नीलाम किया गया है। यह 20-2-88 की बात है। यह एक छोटा कारीगर था। इसी तरह गन्नौर और सम्हालखा में भी जमीन, नीलामी के नोटिस इलू हुए हैं। जब हमारे मुख्य मंत्री जी चुनाव के समय सभी पार्टियों को साथ लेकर चले थे तो उस समय हमारा नारा था कि खेतीहर

छोटे मजदूर, गरीब किसान, और छोटै कारीगरों के कर्जे माफ करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस समय चौधरी देवी लाल जी जनता से कहा करते थे कि एम एल एज असैम्बली में भेड बकरिया चराने के लिए नहीं जाते बल्कि वहां कानून बनाते हैं और हम कर्जे माफी का कानून पास करेंगे। वर्तमान सरकार जो कि कर्जा माफी की हिमायत का दावा करती है और सर छोटैराम का नाम लेती है इससे मैं निवेदन करूंगा कि वह कम से कम कोओप्रेटिव ऐक्ट की धारा-67 को समाप्त करें, जो कांग्रेस ने कोओप्रेटिव ऐक्ट में जोड़ दी थी। इस ऐक्ट के अन्तर्गत को-ओप्रेटिव वाले कर्जदारों को कच्ची जेल में भेज सकते हैं और चालीस दिन तक के लिए बन्द रख सकते हैं। इन चालीस दिनों का उसका खाने पीने का खर्चा उसके कर्जे में एड कर दिया जाता है। मैं सरकार से पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि यह सरकार इस काले कानून को अमैंड करें अथवा इसे समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बैंक या कर्जा देने वाली किसी निजी संस्था को छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, या कारीगर को कर्जा देने के लिए कानून की जरूरत रहती है। कानून बनाने के लिए एम0 एल0 ए की जरूरत रहती है। मेरे ख्याल में आज इस सदन के अंदर ऐसे एम0 एल0 एज0 की कोई कमी नहीं है। ऐसा कानून पास करे जिससे छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, या कारीगर बैडली अफैक्टिड होते हों। कानून के तहत कोई भी निजी संस्था या बैंक जो ऋण देते हैं वे कर्जदार को उसकी जमीन की नीलामी को नोटिस देते हैं, उसके मकान की नीलामी का नोटिस

देते हैं, उसकी जायदाद की नीलामी का नोटिस देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कानून पर पाबन्दी लगाई जाए ताकि इस तरह की नीलामी की घटनाओं को रोका जा सके।

इस बजट में बेरोजगारी भत्ते का कोई जिक्र नहीं है। मैंने हरियाणा के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से बेरोजगारों के आंकड़े एकत्रित किए हैं। इस समय हरियाणा के रोजगार कार्यालय में 299525 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इनमें से 4165 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पिछले इस साल से रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं और उन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा 42855 लोग ऐसे हैं जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पिछले पांच साल से दर्ज हैं और वे इस इंतजार में हैं कि कोई सरकार आएगी और उन्हें रोजगार देगी। ऐसे बेरोजगारों के लिए "बेरोजगारी भत्ते" का प्रावधान होना चाहिए। यद्यपि इस समय सरकार के पास पैसे की कमी है तथापि सरकार प्रयत्न करके इसके लिए प्रबन्ध कर सकती है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जिन लोगों की दस हजार रुपये प्रतिमास से ज्यादा की आमदनी है उनके कर्जे माफ न किए जाएं और दस हजार रुपये प्रतिमास से ऊपर की आमदनी वालों पर बेरोजगारी टैक्स लगा दिया जाए और इस तरह जो पैसा मिलेगा उससे बेरोजगारों का कम्पनसेट किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप दो मिनट में वाइण्ड अप करें।

कामरेड हरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय और दिया जाए क्योंकि गवर्नर ऐड्रेस पर भी मैं नहीं बोल पाया। मैंने 25 तारीख को बोलने के लिए नाम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष: अभी उप-मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी देना है। इसलिए अपनी बात को ब्रीफ करके जल्दी समाप्त करें।

कामरेड हरपाल सिंह: धन्यवाद जी। जहां तक बेरोजगारी भत्ते का ताल्लुक है, इस बजट में बेरोजगारी भत्ते का कोई प्रोविजन नहीं है। हिन्दुस्तान की कई राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। इसके साथ ही मैं शिक्षा नीति पर कुछ कहना चाहूंगा। बजट के अन्दर नवोदय स्कूल खोले जाने का जिक्र है। 'नवोदय स्कूल स्कीम' केन्द्रीय सरकार की स्कीम है। इस बारे में पिछले सत्र में भी जिक्र हुआ था कि सभी पार्टियों को मिलकर केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि यह शिक्षा नीति बन्द नहीं होनी चाहिए। इस शिक्षा नीति के अन्दर जो नए स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें कुछ अमीरों के बच्चों को पढा कर बयूराकेट बनाया जाएगा ताकि उनसे प्रशासन का काम लिया जा सके। आम जनता की पढाई का इस शिक्षा नीति में कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा के अन्दर इस समय दो युनिवर्सिटियां हैं। जैसे अभी डाक्टर साहब ने कहा है कि इन दोनों युनिवर्सिटियों में वाईस चांसलर नहीं है। इस प्रकार विविद्यालयों में अव्यवस्था फैलती है। इन विविद्यालयों में वाईस चांसलर लगाए जाएं

ताकि शिक्षण संस्थाएं ठीक तरह से काम कर सकें। इसके साथ साथ मैं आबकारी नीति के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। आबकारी नीति से ऐसा जाहिर होता है कि जैसे 19वीं सदी के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने चीन में एक अफीम की नीति लागू की थी, इस आबकारी नीति में उसकी पुनरावृत्ति कर दी गई है। जब 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री बने थे उस समय हमारा यह नारा था कि हम भाराब को आम जनता से दूर ले जाएंगे। आज 50 भाराब के ठेके फालतु खोल दिए लेकिन स्कूलों का प्रावधान नहीं किया। इसके साथ साथ ठेकेदारों को यह भी लाइसेंस दे दिए गए हैं कि वे ठेके के अन्दर लोगों को भाराब पिला सकते हैं। जो आदमी पहले अपने घर पर भाराब पीने से डरता था अब उसको लाइसेंस दे दिया गया है कि वह ठेके में बैठकर पी सकता है। सरकार को यह चाहिए कि वह भाराब को महंगी करे यानि उस पर और टैक्स लगाए। उस पैसे से सरकार शिक्षा के लिए साधन जुटा सकती है। इसके साथ साथ ऐक्साइज के अन्दर बहुत बड़ा घपला है। ठेकेदारों को सरकारी जीपें भाराब सप्लाई करती हैं। क्योंकि अफसर ठेकेदारों से मिले हुए हैं। मेरे हलके के अन्दर जो ठेका है वहां पुलिस की जीप से भाराब सप्लाई होती है। वहां पर नाजायज भाराब सप्लाई की जाती है इसलिए सरकार इन बातों के बारे में गौर करें। सरकार लगजरी गुडज पर टैक्स लगा कर पैसा इकट्ठा कर सकती है। सरकार भाराब के ठेको को कम करे। इसके साथ साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नई शिक्षा नीति के बारे में सदन के अन्दर

अपनी स्टेटमेंट दें ताकि हमें पता लग सके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई नीति, जो आम आदमी को अनपढ़ बनाने की नीति है, उस पर हमारी सरकार क्या सोच रही है। जहां तक बिजली की पैदावार का सवाल है, मैं मंत्री जी को उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। पुरानी सरकार ने थर्मल प्लांटों का भट्टा बैठा दिया था। वे लोग थर्मल प्लांटों के निर्माण कार्य में पैसा खा गए और घटिया सामान वहां पर लगा गए थे। वर्तमान सरकार ने उस सभी प्लांट को ठीक तरीके से चलाया और सूखा होते हुए भी बिजली की सप्लाई को ठीक रखा। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमारे थर्मल प्लांट्स की कैपेसिटी कम है। राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी 61 परसेंट है और हमारी 34 परसेंट है। (विघ्न) मंत्री जी बता रहे हैं कि अब 41 प्रति एत हो गई है, मैं इसके लिए भी इन्हे मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि इसे और सुधारा जाए। फरीदाबाद के पास जो इन्द्रपस्थ थर्मल प्लांट है उसकी कैपेसिटी 71 प्रति एत है। जहां तक लाइन लोसिज का सवाल है अभी भी बिजली बोर्ड के अन्दर भ्रष्टाचार है। अभी भी किसानों से रि वत के पैसे लिए जाते हैं। किसी किसान ने कनैव एन लेना हो, बिजली की लाइन लेनी हो, तो किसान से पैसे लिए जाते हैं। हमारे यहां लाइन लोसिज 20 प्रति एत है जबकि नै एनल लैवल पर यह 15-20 प्रति एत है। इसका मतलब यह हुआ कि 5-6 प्रति एत बिजली की चोरी होती है। बड़े बड़े अफसर कारखानेदारों से मिलकर चोरी करवा देते हैं। वे बहाना लगा देते हैं कि लाइन खराब है। जहां तक खेत मजदूर का सवाल

है बजट के अन्दर कर्मचारियों का जिक्र किया गया है। चूंकि हरियाणा के अन्दर केन्द्र की वह सरकार जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की नीतियों को अपनाती थी, जो जागीरदारों की हिमायती थी, उसके चलते भूमि सुधार कानून को कभी लागू नहीं किया गया।

हमारे हरियाणा के अन्दर अभी भी कुछ गांव हैं। मेरे पास दो गांवों से पंचायतें आयी हैं। एक तो नारायणगढ़ के पास का कोई गांव है कि वहां पर सैंकड़ों एकड़ जमीन सरप्लस की निकाली हुई है, अभी तक भी जिन लोगों को वह अलौट की गयी है, उनको कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसी तरह से बालसमन्द हिसार के पास एक गांव है, वहां पर भी सरप्लस की जमीन जिन लोगों को अलौट हुई थी, उनको कब्जा नहीं दिलवाया गया है। अभी तक भी वहां पर बेनामी लोग अपना हल चला रहे हैं। जिन किसानों की वह जमीन मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी है। न ही उसको विकसित करने के लिए कुछ पैसा ही दिया गया है। इसके साथ ही मैं एक और दरखास्त करना चाहता हूं। अब हदबंदी और मुरबदाबन्दी के दौरान कुछ ऐसी जमीन बचत की आयी है, जो कुछ गांवों में भी है और बाहरों में भी है। मेरे अपने गांव के अन्दर ऐसी 10-12 एकड़ जमीन है। वह जमीन मुरब्बाबन्दी और हदबन्दी के बाद बचत की जमीन निकली है। हो सकता है कुछ दूसरे गांवों में भी ऐसी जमीन हो और कुछ में हो सकता है न भी हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां कहीं पर भी ऐसी बचत की जमीन है, वह जमीन वहां की पंचायतों को दी जाए और बाहरों

की जमीन वहां की कमेटीज को दी जाए, ताकि वह अपना गुजारा चला सके और खर्चा कर सकें।

श्री उदय भान (हसनपुर-अनुसूचित जाति): आदरणीय स्पीकर साहब, हमारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो बजट इस हाउस में रखा है, उसमें उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। घाटे का जो बजट इस सरकार को विरासत में मिला था, उसके बावजूद भी ऋण माफी और वृद्धावस्था पेंशन जैसे कार्यों से जो अतिरिक्त बोझ पड़ा है, उस के बावजूद भी सरकार ने किसी भी किस्म का कर न लगा कर जनता का जो विवास पहले से ही बहुत था, उसको प्राप्त कर लिया है। इसमें कुछ एक बातों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। सरकार ने ऋण माफी का जो काम किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। इस बारे में मैं भी अपना अनुरोध और सुझाव सरकार के सामने रखना चाहूंगा। हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड क्लासिज निगम और वीकर सैव निगम, जो गरीब और कमजोर तबके के लोगों को ऋण देती है, वह ज्यादातर ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा दिया गया है। मेरा कहना यह है कि सरकार इस बारे में विचार करके जो राष्ट्रीयकृत बैंको के कर्जे इन निगमों द्वारा दिए गए हैं, वे भी इस कर्जे माफी में शामिल किए जाएं। इसके अलावा जिस तरह से 10000 रुपया ट्रैक्टर का माफ किया गया है, हरिजन कल्याण निगम ने भी कुछ हरिजन बेरोजगार नवयुवकों को

ट्रक, टैक्सी और मैटाडोर के लिए कर्जे दिये थे, उन पर भी इसी तरह से 10000 रुपए की छूट की जाए।

अब मैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सरकार को यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में जितनी सराहना की जाए, उतना ही कम है। सरकार का यह काम बड़ा ही प्रशंसनीय है। इससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। और चरम सीमा पर पहुंच गयी है। इस बारे में मैं करूंगा कि हरिजन और गरीब तबके के लोग, गरीबी, कुपोषण और भाषा की वजह से 65 वर्ष तक नहीं जी पाते। इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। इनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाए।

शिक्षा नीति के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा ही किसी देश या प्रदेश की तरक्की का पैमाना होता है। मैं सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहूंगा जैसे सरकार ने पिछले वर्ष बताया था कि इस वर्ष प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड नहीं किया जाएगा। इस पर पुनःविचार किया जाए और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाए। जहां तक स्कूलों और कॉलेजों का ताल्लुक है, उनमें पूरा स्टाफ और सामान मुहैया करवाया जाए जिनमें अब तक नहीं है। मेरे यहां गवर्नमेंट कॉलेज होडल में, जो सात साल से गवर्नमेंट कॉलेज है, अभी तक भी कॉलेज की बिल्डिंग के लिए जमीन ऐक्वायर नहीं की गयी है। अभी उसके लिए सैक्टर 4 का नोटिफिकेशन एक साल से चल रहा है। उसके लिए अभी तक भी जमीन ऐक्वायर नहीं हुई

है। इसके लिए वर्ष 1986 में साइंस क्लाजि की ऐडमिशन भी भुरु हो गयी थी लेकिन पता नहीं क्यों उस सुविधा से हमारे इलाके को वंचित कर दिया गया। यह क्लाजि भिवानी में या किसी दूसरी कालेज में दे दी गयी। मैं इस बारे में सरकार से प्रार्थना करुंगा कि वह इस बारे में पुनः विचार करे और साइंस की क्लासिज हमारे उस होडल के कालेज में अवय ही खोली जाएं।

इसके अलावा गरीब बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आज जिन स्कूल और कालेजों के बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता है उनके मां-बाप की इन्कम दस हजार होनी चाहिए। मतलब यह है कि दस हजार की सीमा आजकल है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की जबरदस्त महंगाई के जमाने में एक चपरासी का वेतन एक हजार रुपए से ज्यादा का बनता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सीमा को दस हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए कर दिया जाए या जो इन्कम टैक्स पे नहीं करता उसको यह वजीफा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, “भ्रष्टाचार बन्द, पानी और बिजली का प्रबन्ध” यह नारा हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिया है। सरकार ने जो भ्रष्टाचार उन्मूलन सैल बनाया है यह बहुत ही अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक गिरी राज कि गोर विधायक होते थे। उन्होंने तमाम रुल्ज एण्ड रैगूलेशन ताक पर रखकर होडल की मण्डी में साढ़े तीन लाख की कीमत का प्लॉट सताइस हजार में ले लिया। उसके बारे में विजिलेंस की इन्कवायरी चल रही है।

इसके अलावा मण्डी में मार्केट कमेटी की एक गली बनी हुई है उस गली की उसने जबरदस्ती ऐन्काचमेंट कर रखी है। मेरा निवेदन है कि उस ऐन्काचमेंट को जल्दी हटवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कम्बोज।

श्री रघु यादव: उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई नई लिस्ट आई है। भायद उसमें मेरा नाम भी हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप बहुत बोल लिए है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज (इन्द्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 1988-89 का बजट सदन में पेश हुआ है यह बड़ा सराहनीय बजट है और मैं इसकी तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने और हमने मिलकर 1982 में भी यह बजट देखा था लेकिन उस बजट में और इस बजट में बहुत अन्तर है। जनता को सुविधा देने के लिए यह बजट बहुत अच्छा है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी यहां बेंटे हैं। मैं 1982-83 में जमीनो के स्कैण्डल के बारे में बोला था उस वक्त आप भी हमारे साथ थे। वह जमीन का स्कैण्डल कुछ बड़े बड़े आफिसरज बेंटे है, जिन में हरियाणा के आफिसरज भी शामिल है और दूसरे पोलिटीकल लोग भी शामिल है, ने किया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्कैण्डल 45000 एकड जमीन का स्कैण्डल है। उस वक्त मैं नया था और राजीव गांधी को भी इस स्कैण्डल

के बारे में लिखकर दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी हरिजनो की हमदर्द होने का दावा करती है, उनका हमदर्द होने का नारा लगाती है। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे, वे कांग्रेस के ही थे और उन्होंने ही हरिजनो को भाषण किया। वह जमीन हरिजनो को देनी थी। वही पांच आदमी है जो हरियाणा के अन्दर बोली लगाते रहे। नारायणगढ़ के रैस्ट हाउस में बैठकर बोली लगाई जाती थी और बड़े बड़े अफसर और पोलिटिकल आदमी हरिजनो की जमीन ले लेते थे। मैं यहां पर भजन लाल का नाम लेना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहा जाता है कि जो आदमी हाउस में नहीं है उसका नाम सदन में नहीं आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी जो भ्रष्टाचार करते हैं उनका नाम सदन में आना चाहिए। उनकी हाउस में निन्दा की जानी चाहिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम न करे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सब से ज्यादा नाम मनफूल सिंहजो भजन लाल का भाई था उसका लिया जाता था। एक दिन नारायण जो भजन लाल के मामा का लडका था और एक हरफूल सिंह ये लोग सारे हरियाणा के स्कैण्डल में शामिल थे। उप-मुख्य मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनकी इक्वायरी होनी चाहिए। जो जमीन गरीब लोगो को दी जानी थी वह चन्द लोगो के पास है। यह कैसे हो गया?

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और जमीन के स्कैण्डल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां सैक्टर 9 में एक दफ्तर है

वहां क्या हुआ करता था। उस दफतर में करतार सिंह नाम का एक ए० एस० ओ० था। वह जमीनो का डाटा बनाया करता था। कुछ लोग जो उधर पाकिस्तान में, रास्ते में मारे गए थे और उन लोगो के जमीनो के क्लेम यहीं पडे हुए थे जिनका कोई मालिक नही था। उस जमीन के नकली कागजात तैयार करवाए जाते थे और पावर आफ अटोनी के द्वारा उन जमीनो की नकली तौर पर रजिस्ट्री करवा ली जाती थी। इसी तरह से हरियाणा की पंचायत की जो जमीनें थी, उस पर चौधरी भजन लाल ने स्कैण्डल करवाए। पंचायत की जमीनो की रजिस्ट्री ऐसे ढंग से करवाई गई कि एक एकड की 16-16 एकड जमीन दिखाई गयी और जो बंजर जमीन थी उसको एक एक एकड का क्लेम पंचायत से 16-16 एकड दिलवाया गया। मै पिछली कांग्रेस की सरकार के वक्त भी इस हाउस में यह कहता रहा हूं। सबूत भी मैने पे र किए थे। लेकिन उस समय कोई सुनवाई नही हुई। मेरा दावा है कि अगर यह सरकार इस पर काबू पा ले तो इस सरकार को खरबो रुपए का फायदा होगा और खरबो रुपए का यह जमीन का स्कैण्डल पकडा जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि हमारी सरकार को इसकी पूरी तरह से जांच भी करवानी चाहिए ताकि जिन लोगो ने पंचायत की जमीनो पर गलत ढंग से कब्जे कर रखे है उन से वह जमीन छुडवाइ जाए और सही लोगो के हवाले की जाए। जो भी इसमें दोशी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसके साथ मेरी एक रिकवैस्ट है कि इसके लिए एक कमेटी भी बनायी जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: इसके लिए कमेटी बनी हुई है।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि इस बात की जांच करवाई जाए, दोशियों को पकड़ कर उन से वह जमीन वापिस ली जाए ताकि सही आदमियों के हाथों में वह जमीन जाए और वे उस जमीन का फायदा उठा सकें।

इससे अगली बात मैं अपने पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरे इन्दरी हलके की सडको की हालत बहुत खराब है। आज तक उन सडको की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। 1982 से 1987 तक मेरे हलके में कोई भी डिवलैपमेंट का काम नहीं हुआ है क्योंकि बदले की भावना से मेरे हलके को महरूम रखा गया है। जब से दे 1 आजाद हुआ है तब से लोग बाहर से आकर चुनाव लडा करते थे। अब जनता ने मुझे दोबारा ईमानदारी और प्यार से अपने उस हलके का प्रतिनिधी चुनकर यहां पर जनता की सेवा के लिए भेजा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे हलके की डिवलैपमेंट की तरफ खास ध्यान दिया जाए। पीछे जो भजन लाल की सरकार थी, वह वोटो की सरकार तो नहीं थी बल्कि नोटो की सरकार थी। उसको डिवलैपमेंट के कामों से क्या लेना था? जिस कारण से मेरे हलके में न तो कोई कालेज, न हस्पताल और न ही स्कूलों का इन्तजाम हुआ तथा न ही सडको की तरफ कोई ध्यान दिया गया। इसलिए मैं अपनी सरकार से, खासकर पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से

यह पूछना चाहूंगा कि मेरे हलके में कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जिन्होंने सड़क का मुहं तक नहीं देखा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे हलके में सड़को की बहुत बुरी हालत है उस की तरफ अब य ध्यान दिया जाए। मेरे हलके के लगभग 20 गांव ऐसे हैं जहां पर सड़को का बहुत बुरा हाल है। एक दूसरे गांव तक जाने के लिए कम से कम 40-40 किलोमीटर का ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि पी० डबल्यू० डी० मिनिस्टर महोदय मेरे इस सुझाव पर अब य ही ध्यान देंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब: इसके साथ साथ मैं एक और बात यहां आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यमुना के साथ साथ मेरी कांस्टीच्युएन्सी लगती है। वहां पर जमीनो के काफी झगडे हैं क्योंकि जब वहां पर बाढ आती है तो बाढ के कारण यमुना मोड काट कर कटाव करती है। जब पानी काफी आता है, तो बाढ यू० पी० की सीमा का छोड कर हरियाणा की सीमा में ज्यादा आई है। और वहां जो जमीन दोबारा निकली है उस जमीन के लिए किसानो में आपस में झगडे रहते हैं। हमारे उप मुख्य मंत्री जी हाउस में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो यमुना की दोबारा जमीन निकली है उसकी चकबन्दी होनी चाहिए। यदि उस जमीन की चकबन्दी हो जाए तो किसान लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। जमुना की जहां जहां पर भुरबरी जमीन निकली है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उस जमीन को कुछ प्रभाव वाली लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और गरीब किसानो

को नहीं मिलती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस जमीन की चकबंदी करके उसे किसानों में बांट दिया जाए ताकि उस जमीन का इस्तेमाल हो सके और किसानों के आपस में झगड़े भी न हों। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यू० पी० सरकार ने जमुना के साथ लगती हुई अपनी सीमा के साथ साथ बांध बना लिए हैं जिसके कारण हरियाणा की तरफ ज्यादा कटाव होता है जिससे हमारी जमीन बहुत तबाह हो जाती है। उस कटाव को रोकने के लिए हमें भी हरियाणा के साथ साथ लगती हुई जमुना की सीमा पर बांध बनाने चाहिए ताकि हरियाणा की जमीन की कटाव से जा सके। यदि बांध न बनाए जाएं तो हमारी तरफ बड़ी बड़ी ठोकरें बना दी जाएं ताकि हरियाणा की जमीन बचाई जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। बहन जी यहां हाउस में बैठी हैं। हमारा खादर का इलाका है। वहां पर इतने ज्यादा मच्छर पैदा हो गए हैं कि रात में लोगों को सोने नहीं देते। मंत्री महोदय को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन भावों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री हरि सिंह (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष 1988-89 का बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है। चाहे सरकार पर कर्ज माफी का, चाहे सुखे

का, चाहे ओलावृष्टी का और चाहे करो की दरों में कटौती करने का बोझ रहा हो फिर भी वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बजट पे । किया है और यह कर रहित बजट है । उपाध्यक्ष महोदय, बजट के घाटे को कैसे पुरा किया जा सकता है इस बारे में मैं अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा और उसकी तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे । इस बारे में मैं अपने लोकल बोडीज मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल कमेटीज की जो आज से 8 या 10 साल पहले लिमिट थी उसको बढ़ाया जाए ।

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम म्यूनिसिपल कमेटी की हद बढ़ा रहे हैं ।

श्री हरि सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिसार म्यूनिसिपल कमेटी की मिसाल देता हूँ और उसकी फाइल माननीय मंत्री जी के पास पहुंच गई होगी । यदि हिसार म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट बढ़ती है तो उस कमेटी को लगभग 80 लाख रुपए अतिरिक्त इन्कम हो जाती है ओर वह पैसा हिसार को डिवैल्प करने में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने हिसार टैक्सटाइल मिल बंद कर दी थी और उस मिल में पांच हजार मजदूर काम करते थे वे सारे बेकार हो गए हैं । पिछली सरकार के मुख्य मंत्री जी ने 1984 में यह ऐलान किया था कि यह मिल चलाई जाएगी लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि

उस मुख्य मंत्री ने उस टैक्सटाइल मिल का सारा सामान वहां से उठवा दिया और आदमपुर मंडी में अपने मिलने वालों की एक फैक्ट्री लगवा दी। इसके अलावा एक फैक्ट्री भाराब की लगाई हुई है। उसके बारे में भी सदन के अंदर काफी चर्चा हुई है। कैंटरोड के अधिकारी कर्मचारी हमारे भाई हैं। उस भाराब की फैक्ट्री ने सातरोड और हिसार के रहने वाले लोगों का जीना दुभर कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने हिसार टैक्सटाइल्स मिल को बंद करवा दिया था जिसके कारण वहां पर पांच हजार मजदूर बेकार हो गए थे। उस मिल की 400 एकड़ की जमीन 1953 में एक एग्रीमेंट के तहत एच0टी0एम0 को दी गई थी। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि एच टी एम को यह अधिकार है कि वह इस मिल चलाएं अन्यथा सरकार 30 दिन का नोटिस दे कर वह जमीन खाली करवा सकती है। वे 7 करोड़ की जमीन को 6 लाख रुपये में ले आएंगे। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि सरकार का 7 करोड़ रुपये का बजट में मुनाफा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हलके में आज से 30 वर्ष पहले 200 बैडज का अस्पताल बना था। उसकी आज के दिन बहुत ही खराब हालत है। मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खस्ता हालत को ठीक करवाया जाये। इसी प्रकार से मैं शिक्षा मंत्री जी

से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे हलके के जिन गावों के स्कूलों की बिल्डिंगें ठीक नहीं हैं, उनको भी ठीक करवाया जाए। इसी प्रकार से मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिसार से मेहन्दीपूर के लिए एक बस चलाई जाए। लोग मेहन्दीपूर को एक धार्मिक स्थान मानते हैं क्योंकि सुना जाता है कि जिन लोगों को बुरी आत्मा का असर है उनका वहां पर ईलाज होता है। मैं इन भावों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री विठ्ठल प्रसाद (अम्बाला भाहर): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं अगर यह कह दूँ कि भायद पहली बार ऐसा बजट पेश किया है जिसमें गावों के गरीब मजदूरों और लोगों की तरफ से भाहर के हर छोटे दुकानदार तथा अन्य तबके के लोगों की ओर ध्यान दिया गया है तो कोई गलत बात नहीं है। हमारी सरकार ने पानी देने का प्रबन्ध और भ्रष्टाचार बन्द करने का जो नारा लगाया था, उस पर अमल किया है। अब मैं पावर मिनिस्टर साहब को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा में भायद सबसे पहले नगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम लागू हुई थी। उस स्कीम के अन्तर्गत कोला डिस्ट्रिब्यूटरी मुकम्मल होने के बाद काफी जमीन सिंचित हो सकती है। दूसरे एक पंजौखरा ड्रेन भी बनाई जा रही है। इसकी कुल लम्बाई 19 किलोमीटर है। इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे अलौट करें और उसे कम्प्लीट करवाएं। इस पर साढ़े तीन करोड़

रुपये तो खर्च हो चुके हैं अब वहां पर केवल 20-25 लाख रुपये का काम होना बाकी रहता है। यदि यह काम पूरा हो जाए तो उससे 4654 हैक्टेयर भूमि को और सिंचित किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि नगरपालिकाओं का महकमा भी इनके पास है, भाहरों में नगरपालिकाओं के जरिये लोगों से प्लॉट के जो डिवलपमेंट चार्जिज लिए जाते हैं वे पूरे प्लॉट के न लेकर केवल फ्रंट साइड के डिवलपमेंट चार्जिज ले ताकि चुनावों से पहले किए गए वायदों के अनुसार इन लोगों को भी राहत मिल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं पीने के पानी की बाबत कहना चाहूंगा। वहां पर नहर से पीने का पानी का पहला फेज तो पूरा हो चुका है। दूसरे फेज के बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसे जल्दी भुरु करवाया जाए क्योंकि अब की बार बारि आ न होने की वजह से जो ट्यूबवैल लगे हुए थे उनमें पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण पीने के पानी की बहुत दिक्कत होती है। कई ट्यूबवैलज तो बन्द हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर सैकेण्ड फेज को भी जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश आ सरकार करे ताकि लोगों को पीने का पानी की दिक्कत न हो।

चुनाव से पहले जिस समय संघर्ष चल रहा था उस समय संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केसिज बनाये गये थे लेकिन वे अभी तक वापिस नहीं हुए हैं। इसके अलावा सन्

1982 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वर्करो पर जो मुकदमें बने थे वे आज तक चल रहे हैं। उन मुकदमों को वापिस लिया जाये।

दूसरी बात यह है कि नम्बर आफ टैक्सीज कम होने चाहिए। आधा परसेन्ट सँले कर 12 परसेन्ट तक टैक्सीज है। इनको घटाया जाये। दो तीन नम्बर आफ टैक्सीज होने चाहिए और हर अमैडमेंट क्वार्टरली होनी चाहिए यानी अमैडमेंट करने का समय निश्चित होना चाहिए। लाइसेंस लेने का और कैंसेल करने का या लाइसेंस में अमैडमेंट करने का ऐक्ट में समय होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिन लोगो पर पांच हजार रुपये तक टैक्स लगता है उन्हें अपील में जाने का अधिकार नहीं है। उन लोगो को अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए। चौथी बात यह कि ट्रिब्यूनल हरियाणा में केवल दो जगह होने चाहिए। यह परमानेंट तौर पर एक अम्बाला में और एक फरीदाबाद में होना चाहिए। ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या सैान जज लगना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मै शिक्षा के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। डी० पी० आई० की डिपार्टमेंटल परमोान होनी चाहिए। पहले इनस्पैक्टर्ज आफ स्कूलज़ होते थे वे स्कूलो को चैक करते थे। इसलिए इसके दो भाग होने चाहिए। एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हो और एक स्कूल की चैकिंग करने वाला भाग हो। पहले जब कोई इनस्पैक्टर स्कूल की चैकिंग के लिए

जाता था तो वहां पर लिख कर आता था कि उसमें क्या कमी है लेकिन अब वह चैकिंग नहीं होती है। अगर शिक्षा स्तर पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा अलब हो जाये और पढाई की चैकिंग करने वाला अलग हो जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि एस0 डी0 ओ0 के दफ्तर में टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए। अगर हमें किसी एस0 डी0 ओ0 से टैलीफोन पर बात करनी हो तो कर नहीं सकते। तीसरे बी0 ई0 ओ0 के नीचे तो स्कूल दिये जाते हैं उनका ठीक प्रकार से बंटवारा होना चाहिए। किसी बी0 ई0 ओ0 को बीस या पच्चीस स्कूल दिये हुए हैं और किसी को 60 स्कूल दिये हुए हैं। जो भी स्कूल उसको दिए जाएं वो उसके आफिस एरिया में ही होने चाहिए ताकि वह ठीक प्रकार से सुपरविजन कर सके, निरीक्षण कर सके। टीचर्स समय पर आते हैं या नहीं, समय से पहले तो नहीं जाते हैं, अगर स्कूल उसके एरिया में होंगे तो भली प्रकार से चैकिंग कर सकता है। एक बात और भी कहूंगा कि जो पब्लिक स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान है इसे भी चैक करे क्योंकि उनकी ओर रुझान रहा तो आम स्कूलों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जायेगा। वे अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में दाखिल करवाएंगे। यदि हम आम स्कूलों का स्तर उंचा करना चाहते हैं तो उनकी ओर से रुझान कम करना पड़ेगा। मुख्य मंत्री महोदय ने चुनावों से पहले जो लोगों से वायदे किए थे वे चुनाव के बाद तेजी के साथ पुरे किए। हमारे मुख्य मंत्री में लोगों का विश्वास जमा हुआ है। इसी तरह से नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने का जो वायदा किया था उन्हें भी पूरा किया गया। मुख्य मंत्री जी के

बिहाफ पर ही हमने लोगो से वायदे किए थे कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, सरकार ने जो वायदे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने नगरपालिकाओ का चुनाव करवाने का जो वायदा किया था उसे भी पूरा किया जिससे अब भाहरों में गंदगी के ढेर दिखाई नहीं देंगे और भाहर सही मायनो में भाहर दिखाई देंगे। मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि नगरपालिकाओ की हालत बड़ी खस्ता है। सी० ई० ओ० तथा ई० ओ० का बोझा सरकार ने इन पर और डाल दिया। इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि उपरोक्त दोनो अधिकारियों में से एक अधिकारी का वेतन हरियाणा सरकार दे अन्यथा एक पद को समाप्त कर दिया जाये। इसके साथ भाहरो की हालत सुधारने के लिए और भाहरो को भाहर बनाए रखने के लिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओ को जैसे भी हो स्पै ाल ग्रांट दी जाए ताकि जो वायदे हमने आपके बिहाफ पर किए थे वे पुरे हो सके और जनता का वि वास इस बात में पक्का हो कि चौधरी देवी लाल की सरकार का कोई भी रिप्रैजैन्टेटिव जो बात कहता है वह निश्चित रूप से पूरी होती है। इन भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री हरनाम सिंह (ाहबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योकि आप ने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है। सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बजट में 32 करोड रुपये की कमी है और इस कमी को बढाने की

सम्भावना है। हमारी सरकार को पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी ताकि वह हरियाणा प्रान्त की सर्वांगीण डिवैल्पमेंट कर सके। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने कोयला, लोहा, डीजल, पेट्रोल आदि की कीमतें बढ़ाई है हमने उसे बजट के अन्दर नहीं आंका है। इसलिए हमारा खर्चा बढ़ेगा और हमें ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। इसी तरह से फोर्थ-पे कमी इन की जो रिकमेंडे इन जनवरी, 1986 से लागूकी गई है, उन पर जो पैसा खर्च होगा उसकी सरकार को जरूरत होगी क्योंकि इनकी ऐक्चुअल पेमेंट तो अब हुई है। और कई ऐसे काम हैं जिनसे हमारी सरकार का खर्च बढ़ेगा लेकिन उसकी जिम्मेवारी हमारी सरकार की नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की है। इस बात में कोई भाक नहीं कि तरक्की के लिए हमें बड़ी कोर्सा करनी पड़ेगी। इस बारे में मैं कुछ सुझाव दुंगा। सबसे पहले तो सरकार को अपने अखराजात में कमी करनी चाहिए और दूसरे सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे रोका जाए। इस काम में मेहनतकश मजदूरों और ईमानदान कर्मचारियों की मदद ली जाए। इसी प्रकार से रैस्टोरेंट और दूसरी ऐगो-इरत की जगहें हैं, जहां लोग 500/- रुपये एक दिन का किराया देते हैं और किमती भाराबे पीते हैं, ऐसी जगहों पर टैक्स लगाया जाये। (इसी समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) विवाह भाादियों में बिजली की फिजूलखर्ची को रोका जाए। लोग हजारों रुपये की बिजली विवाह भाादियों में खर्च कर देते हैं बिजली की कन्जम्प इन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बिजली को किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जाना

चाहिए। ऐसा फिजूल खर्च करने वाले लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए। इससे अगली बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वह है, पानी। हरियाणा के अंदर पानी का सवाल बहुत ही अहम सवाल है। इस बारे में एस0 वाई एल0 की बाबत कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय कल कांग्रेस के संसद सदस्यों ` मिले हैं और उनसे कहा कि वे जून, 1988 तक एस0 वाई0 एल0 का काम पूर्ण करवाए। इस बारे में मैं यह उचित समझता हूँ कि सभी पार्टियों को मिलकर केन्द्र सरकार पर जोर देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यमुना दरिया की बाबत कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सन् 19580 में यमुना नदी के पानी का बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे के मुताबिक यमुना का दो तिहाई पानी हरियाणा सरकार को और एक तिहाई पानी यू0 पी0 सरकार को मिला हुआ है। एक अप्रैल 1990 को यह मुहाइदा खत्म हो जाएगा। इस बारे में भी हमें वक्त रहते बात कर लेनी चाहिए। पानी का झगडा तो हमारा पहले से ही पंजाब के साथ चल रहा है, ऐसा न हो कि यह पानी का दूसरा झगडा भुरु हो जाए। इसलिए मैं सरकार से गुजारि ा करुंगा कि इस मसले की ओर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि पि चमी यमुना नहर हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरुरी है।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारा हथनी कुंड वैराज है उसके बारे में सिंचाई मंत्री जी ने बताया कि वह बनेगा, यह बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें डिले होती है और 1978 जैसा फ्लड फिर आ जाता है तो हरियाणा में बहुत बडी

तबाही मच जाएगी। इसलिए उसको जल्द बनाया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यू० पी० सरकार ने अपनी तरफ जमुना के दाएं किनारे पर एक नहर निकाली है। वह हथनी कुंड के उपर 3 किलोमीटर पर है और उससे उन्होंने 6-7 हाइड्रो पावर प्लांट भी बनाए हैं। हथनी कुंड के बिल्कुल सामने खारे का पावर हाउस बनाया जा रहा है। वहां से तीन किलोमीटर ईस्ट यमुना कैनल है। अगर हमने यह मसला तय नहीं किया तो वे जून से पहले नहर बना कर पानी अपने यहां ले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा बीस लाख एकड़ फीट पानी नदियों में बह जाता है और उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारे पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है इसलिए उस पानी का प्रयोग नीचे गए पानी को री-चार्ज करने के लिए किया जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र का इलाका हरियाणा की खेती का भंडार है। वहां पर धरती के नीचे के पानी से ही सिंचाई हुई है और पैदावार काफी बढी है। अब उस इलाके का पानी भी नीचे जा रहा है। पिछले 15 साल में वहां का पानी 60 फुट नीचे चला गया है। गरीब किसानों के ट्यूबवैल फेल हो गए हैं। गरीब किसान सब मरसीब ट्यूबवैल नहीं लगा सकता। इस समय हमारी खेती संकट में है। चितंग और राक्षी नदियों का पानी जमुना में डाल देने से हमारी सावणी की फसल होती थी। इसलिए इन नदियों के फलों को छोड़ना चाहिए ताकि पानी का प्रयोग हो सके। जहां तक बिजली का सवाल है मैं समझता हूँ कि पानीपत थर्मल प्लांट का तजुर्बा हमारे सामने है कि सरकार ने उसे कैसा बनाया था।

लेकिन जमुना नगर का प्लांट हम दिल्ली की सरकार को दे रहे हैं, पता नहीं वह भी कैसा बनेगा। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को सैंटर से पैसे लेकर यह प्लांट खुद बनाना चाहिए। बडा अफसोस है कि रोपड और जमुनानगर थर्मल प्लाट्स के लाइसेंस एक ही दिन जारी हुए थे लेकिन उनको तो पैसा मिल गया और हमें नहीं मिला। पिछली सरकार ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहां बिजली के सब-स्टे इन और अधिक बनने चाहिए। अब लम्बी लाईने है जो ओवर लोडिड है। इसलिए और सब स्टे इन बनने चाहिए ताकि लोड पूरा बांटा जा सके। जो ट्यूबवैल का ट्रांसफार्मर है वह दो पोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लम्बी लाइने होगी तो सरकार और किसान दोनों को नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भाहबाद और थानेसर का इलाका है वहां पानी नीचे चला गया। हमने बहुत भाोर मचाया कि हमारे यहां नहर बननी चाहिए। भाहबाद नलवी नहर और लाडवा नहर मंजूर भुदा है और पिछले बजट में इनके लिए एक करोड बीस लाख रुपये रखे गए थे लेकिन इस बजट में कोई पैसा नहीं रखा गया। मेरे पास पिछले सात साल और इस साल के बजट है। यह हमारी सातवी पंचवर्षीय योजना में मंजूर है और उसमें लिखा है कि यह नहर 1990 तक बन जाएगी। यह नहर पांच विधान सभा क्षेत्रों की सिचाई करेगी जिसमें स्पीकर साहब, का क्षेत्र सूरजभान जी का, कटारिया साहब का, गुदियाल सिंह का और मेरा क्षेत्र आता है।

इसलिए यह नहर बहुत जरूरी है, इसको जल्द बनाया जाना चाहिए। (घंटी) मैं अभी खत्म कर रहा हूँ।

पौल्यू इन का सवाल बहुत बड़ा है। हम पिछले दिनों कारखाने देखने के लिए जगह जगह गये थे। यह जो सरस्वती भुगर मिल है और वहां पर जो भाराब की फैक्ट्री है उका गन्दा पानी यमुना नहर में जाता है। वही पानी डंगरो के पीने के लिए हम जोहडो में डालते हैं और वह पानी पीने से डंगर मरते हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हमारे यहां पर बहुत हो रहा है। ऐसा ही हाल हमने फरीदाबाद में भी देखा है।

श्री अध्यक्ष: कामरेड साहब, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हरनाम सिंह: बहुत अच्छा जी। हम फरीदाबाद में एक रबड की फैक्ट्री देखने गए। वहां पर बहुत ज्यादा बदबू पैदा हो रही थी। वहां पर लोग नहीं रह सकते। इसके लिए सरकार ने फैक्ट्रीज के खिलाफ मुकदमें जरूर किये हुए हैं लेकिन कई-कई साल हो गये हैं। उनका जल्दी से फैसला कराने के लिए उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनायी जाये। आखिर में मैं एक बात मुजाजिमो के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री हरनाम सिंह: अच्छा जी, भुकीया।

उप मुख्य मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आज से 6 दिन पहले मैंने इसी सदन में वर्ष 1988-89 का बजट और उसके अनुमान प्रस्तुत किये थे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट चौधरी देवी लाल की सरकार का एक प्रोग्रेसिव और प्रगति मील बजट है। मुझे इस बात का गर्व है कि इतना भानदान बजट जिसकी सराहना चारों तरफ से हुई है, मैंने पेश किया। प्रैस में इसकी सराहना हुई। जनता में इसकी सराहना हुई। अध्यक्ष महोदय, भायद आपने पढा होगा कई समाचार पत्रों में तो लीडिंग आर्टिकल इसकी सराहना में लिखे गये हैं। हैड लाइन्स दी है कि टैक्स फ्री बजट। किसान को सहायता, मजदूर को रियायत, व्यापारी को सहूलियत और कर्मचारियों को सुविधा। यह अखबारों के अन्दर हैड लाइन्स आई है। अध्यक्ष महोदय, बजट क्यों भानदार है, इसके मैं दो तीन नमूने आपको बताना चाहता हूँ। जब यह साल भुरु हुआ, पिछला साल 1987-88 का तो पिछले साल का 34.63 करोड़ रुपए का घाटे का अनुमान था। हमारे हाथ में जब सत्ता की बागडोर आयी, हमने जब सत्ता को सम्भाला तो जैसी आर्थिक स्थिति थी वह मैंने पहले भी इसी सदन में ब्यान की थी। आर्थिक स्थिति इतनी बुरी और सोचनीय थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारे उपर 150-200 करोड़ की जिम्मेवारी थी, लाइबिलिटिज़ थी जो हमें पूरी करनी थी। हमारे कांग्रेसी भाईयों ने जो बातें उठायी हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं इस बजट की विशेषताएँ क्या हैं, वह बताऊंगा। इन हालात में जब कि सूखा पडा, हमने कर्जा माफी की, वृद्धों को

पैन् इन दी गयी और कर्मचारियों को बढी हुई तनखाह दी, इन सब के बावजूद भी जिस घाटे का अन्दाजा लगाया गया था, अध्यक्ष महोदय, हमने साल के अन्दर उस घाटे को 34 करोड से घटाकर 3 करोड रुपये पर ला दिया। 31 करोड रुपए का घाटा जो अन्दाजा लगाते थे उसको हमने पूरा किया है। वर्ष 1988-89 के अन्दर हमारा अनुमान है कि 36.32 करोड रुपए का घाटा होगा। मैंने अपने बजट भाषण में भी यह दिया है। सदन को भी याद होगा और जनता को भी याद होगा कि हम जो गैर योजना खर्च होंगे उनमें कमी करेंगे, किफायत करेंगे और अपनी वसूलियां बढाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो चारी पिछली सरकार के वक्त में हुआ करती थी, तरह-तरह के घोटाले हुआ करते थे, उन सब को हम बन्द करेंगे। हमने 9 महीने के अंदर ही ये बन्द कर कर दिखा दिये हैं। हमारे कराधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे ही सब फिगरज इस बारे में बता सकते हैं कि हमने कितनी ज्यादा रकम सेल्ज टैक्स की वसूल की है, दर बढाने से नहीं बल्कि जो लीकेज होती थी, जो पहले चोरी होती थी, उसको बन्द करके बढाई है। अध्यक्ष महोदय, 18:00 बजे, अगर आप किसी दूसरे प्रदेश की सरकार के बजट से हमारे बजट का मुकाबला करना चाहेगे तो पंजाब के निकट और कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। चण्डीगढ़ में हम दोनों एक छत के नीचे बैठते हैं और इसी विधान सभा की छत के नीचे दोनों सदन चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि हमारा घाटा 36.32 करोड का है और पंजाब में 239 करोड का घाटा है जबकि उनको 650 करोड रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त

हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने बागडोर सम्भाली थी तो चौधरी देवी लाल ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी लायबिलिटीज (देनदारियों) का देखते हुए केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा और उनसे प्रार्थना की कि हमें सौ करोड़ रुपए योजनागत खर्च के लिए और पचास करोड़ रुपए गैर योजनागत खर्च के लिए दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर दुख होगा कि उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): परसो जवाब आ गया है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मुझे नहीं मालूम कि जवाब आ गया है। अध्यक्ष महोदय जब तक मैंने बजट प्रस्तुत किया तब तक कोई जवाब नहीं आया था। अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमसे बहुत आगे है। पंजाब के साधान हमसे बहुत ज्यादा है। यह ठीक है कि पिछले तीन चार साल से वहां हालात खराब रहे हैं। ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है लेकिन कृषि उत्पादन में, नहरों के वाटर अलाउंस में, बिजली उत्पादन में और टैक्सो से आमदनी में वह हमसे आगे है। हमारे पास उतने साध नहीं हैं जितने उसके पास हैं। आज हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिल्ली गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष और अधिकारियों से बातचीत की।

बातचीत करके जो योजना हमने मंजूर करवाई वह छः सौ करोड रुपए की है। पिछले साल की योजना 430 करोड रुपए की थी। अध्यक्ष महोदय, पंजाब की केवल सात सौ करोड की योजना मंजूर की गई है। पहले पंजाब की योजना 850 करोड रुपए की मंजूर की गई थी लेकिन उस पर पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार होने के बाद 150 करोड रुपए काट दिए क्योंकि पंजाब वालों ने कहा कि हम रिसोर्सिज नहीं जुटा पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट योजना में किसानों को, छोटे व्यापारियों को और विधार्थियों को मतलब यह कि सभी लोगों को राहत दी गई है। बजट योजना में मैंने सब कुछ विस्तार से बता दिया है। मैं उन सब बातों को अब नहीं दोहराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार से विरासत में हमें जो घाटा मिला उसके लिए हमने केन्द्र से सहायता की प्रार्थना की लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बावजूद भी आप सब को खुशी होगी कि चुनाव से पहले हमारे नेता चौधरी देवी लाल ने जनता से जो वायदे किए थे, अगर मैं अति व्यक्ति से काम नहीं लूँ तो 80-85 प्रतिशत वायदे पिछले नौ महीनों में पूरे कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट की मोटी झलक है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, चौधरी वीरेन्द्र सिंह तो उनका कुछ और ही नाम लेते हैं लेकिन उनसे बलबीर पाल भाव कहते हैं, ने बजट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया पेश करते हुए कहा कि यह बजट कलरलैस है। महेन्द्र सिंह प्रताप ने कहा कि यह बजट नीरस है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये माफ़ करे, पिछले काफी अरसे से इन लोगों को

रस चखने और हर चीज में रंगीनी देखने की आदत पड गई है। ये हर चीज में रस और रंग तला ा करते है। मै इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इसमें और टैक्स लगा देते तो क्या इसमें रस आ जाता, रंगीनी नजर आती? अगर हम पुराने ढंग से चलते और हर चीज पर टैक्स लगा देते तो क्या इसमें रस आ जाता और महेन्द्र प्रताप सिंह को रस का घूंट मिल जाता। (गोर एवं व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, आप इन भाईयो ंसे कहे कि जरा दिल पर हाथ रख कर बैठै और सब्र से सुने, इतने उतावले न हों। मै कह रहा था कि हमारे हरियाणा प्रदे ा में एक कहावत है "अवसर चूकी डूमनी गाव आल पाताल" (हंसी) वास्तव में ये अवसर चूक गये है और आल पाताल गाते फिरते है कि 'मुहं बाया राग आया' यह कहावत इन पर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। वास्तव में इस बजट के अन्दर कोई बात ऐसी नही है जिसकी ये लोग आलोचना कर सकें। एक बात इन्होने कही कि बजट आने से पहले ही टैक्स लगा दिया तो फिर बजट में लगाने की क्या आव यकता थी? मेरे आदरणीय मित्र श्री राम विलास भार्मा जी ने बोलते हुए कहा कि जब भी कोई केन्द्र की चर्चा होती है तो ये लोग ये लोग अपने आप को केन्द्र सरकार का रिप्रंजैन्टेटिव मानते हैं और हरियाणा प्रदे ा की नही, हरियाणा विधान सभा का नही, बल्कि केन्द्र सरकार के प्रतिनिधी के तौर पर अपनी भुमिका अदा करते है। इस सदन के अन्दर वे रक्षा करते है, डिफैन्स करते हैं, अगर वे अपने केन्द्र सरकार के बजट की तरफ देखें तो इनको पता चलेगा कि हमने तो कुछ दिन पहले ही बढाया है और आज

नहीं आज से कई महीने पहले ही बढ़ाया था और यह भी इसलिए कि यह लोग जो कुएं और गड्ढे खोद गए थे, खजाना खाली कर गये थे, उसकी पूर्ती करने के लिए हमने बजट में कुछ बढ़ोतरी की है। लेकिन केन्द्र सरकार की कांग्रेस सरकार ने बजट आने से थोड़े समय पहले ही चीजों के दाम जैसे पेट्रोल, चीनी, कोयले, वगैरह के रेट्स बढ़ा दिये और जब बजट आया तो फिर और टैक्स भी लगा दिये। डाक व तार का भार भी लोगों पर डाल दिया, टेलीफोन के रेट्स भी बढ़ा दिये जो आज किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं रही कि वह अपने घर में इस को मैनटेन कर सके। हमें तो इसलिए रिसोर्सिज पैदा करने पड़े कि जब इनके नेता ने, प्लानिंग कमीशन के साथ बातचीत की, पता नहीं चौधरी भजन लाल थे, या चौधरी बंसी लाल जी थे, उन्होंने 584 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर करवाई और साथ में यह वायदा किया कि हम अन्य रिसोर्सिज से, अपने संसाधनों से 45 करोड़ रुपये के साधन जुटा देंगे। लेकिन उन्होंने एक पैसे का भी साधन नहीं जुटाया। अगर, अध्यक्ष महोदय, हम 92 करोड़ रुपये के रिसोर्सिज न जुटाते तो आज हमें 600 करोड़ रुपये की योजना आयोग से मंजूरी न मिलती। अगर 600 करोड़ रुपया मंजूर न हुआ होता तो आज हम अपने विकास की गति को तेज नहीं कर सकते थे। हम प्रदेश की समस्याओं को हल नहीं कर सकते थे। पानी और बिजली लोगों को नहीं दे सकते थे। यह सब काम हम नहीं कर सकते थे इसलिए हमें यह सारे रिसोर्सिज जुटाने पड़े।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और तैयब साहब ने यहां पर कही और साथ में मुहम्मद तुगलक की एक मिसाल भी दे दी। कही इतिहास में पढी होगी या इन्होंने कहीं से सुनी होगी। चौधरी साहब ने फरमाया कि यह सरकार बार बार बदलती रहती है अगर एक बार टैक्स लगा तो दूसरी ओर लोग आ गये तो विदग्धा कर लिया। मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहता हूँ कि इसी का नाम तो लोकराज है। हमारे नेता रोज कहा करते हैं कि लोक राज लोक लाज से चलता है। यह सरकार आपकी कांग्रेस की सरकार की तरह अडीयल सरकार नहीं है कि एक छोटे से अधिकारी को लेकर आज सारे हिन्दुस्तान का जुडीयल ऐडमिनिस्ट्रेटिव पैरालाईज हो जाए। आज महीनो से सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्टस तक तमाम वकील हडताल किए बैठे हैं लेकिन मेरे कांग्रेसी भाईयो की सरकार किरण बेदी के बारे में प्रतिशठा का प्रश्न बनाए बैठी हैं। वकीलो की हडताल के कारण करोडो लोग परेशान हैं। गावों से क्लार्क आते हैं, देहातो से भोले भाले लोग आते हैं खर्चा करते हैं वकीलो का फीस देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं, मैं तो क्लार्क भी नहीं रहा। देहात से जब कोई गरीब क्लार्क आता है तो और उसके वकील न मिले तो उसको अंधेरा नजर आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक जनता की भालाई का प्रश्न है वह आज सारे देश के अंदर ठप्प पडा है लेकिन हमारी सरकार ऐसी नहीं है। यह जनता की चुनी हुई सरकार है। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी जो भी फैसला करते हैं यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो उस कमी के बारे में

जनता के प्रतिनिधि आ कर समझाते हैं कि हमारे उपर टैक्स लगाने से प्रदेशों के व्यापार पर फर्क पड़ेगा। प्रदेशों का व्यापार रिफ्ट हो कर प्रदेशों के बाहर चला जाएगा। रेट आफ टैक्स ज्यादा होने से टैक्स की चोरी होगी या गुंजाइश होगी। इसलिए आप रेट आफ टैक्स न बढ़ाएं। एक बात डाक्टर साहब ने बताई थी और एक मैं बता देता हूँ। पिछले दिनों सैंटर गवर्नमेंट ने आयकर में संशोधन किया है कि पार्टनरशिप पर भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना की टाटा, बिडला, डालमिया जैसी बड़ी बड़ी फर्मज पर लगता है। अध्यक्ष महोदय, किसी व्यापार को चलाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है उसको 3 या 4 आदमी आपस में मिल कर चला सकते हैं। यदि तीन या चार आदमि मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं और साल में एक लाख रुपया कमा लेते हैं जो आजकल इस महंगाई के जमाने में कोई ज्यादा नहीं है तो उनके 50 हजार रुपए टैक्स में देने पड़ेगे और उनके पास 50 हजार रुपये बचेंगे। इस संशोधन से सारे देशों के अंदर होहल्ला मचा हुआ है। मैं यह बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस संशोधन से सरकार का कोई रैवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ऐसा करने से लोग टैक्स की ज्यादा चोरी करेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि इस तरह से करके जो कांग्रेसी सरकार सैंटर में बैठी हुई है वह खुद तो भ्रष्ट है ही लेकिन साथ साथ लोगों को भ्रष्ट बना रही हैं। यह सरकार लोगों को टैक्स की चोरी करने पर मजबूर कर रही है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों टिम्बर पर टैक्स लगाया गया लेकिन लोग चलकर हमारे मुख्य मंत्री जी के पास आए और उन्होंने

समझाया, जब उनकी बात चौधरी साहब की समझ में आ गई तो इन्होंने फौरन कहा कि इसको विदड़ा कर लिया जाए। हमने उसी समय विदड़ा कर लिया। यह सरकार जनता की बात मानती है और जनता की बात पर फैसला करती है। चौधरी तैयब हुसैन ने तुगलक की मिसाल दे दी। अब यह बात इन पर लागू होती है या हम पर लागू होती है ये अपने आप सोच लें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैंने सदन में गलत कहा है कि पिछली सरकार झाड़ू देकर गई है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो 45 करोड़ रुपए छोड़ कर गए हैं। इनसे कोई पुछने वाला हो कि ये हमारे उपर लायबिलिटी कितनी छोड़ कर गए हैं। इन्होंने तो बैलेंस बताया है कि इतना छोड़ कर गए हैं बैलेंस तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से आता है। हमें भी नहीं पता कि कितना बैलेंस है। ये भोखी किस बात की मारते हैं। इसके अलावा चौधरी तैयब हुसैन और महेन्द्र प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि इस सरकार ने चूंकि सिंचाई और बिजली पर कम खर्च किया है इसलिए यह सरकार किसानों की हितैशी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत इनको समझाना चाहता हूं कि मेरे पास पिछली सरकार के बजट की भी फिगर है कि इस पर उस सरकार का कितना प्रावधान था और हमारा कितना है। अध्यक्ष महोदय, महोदय खेती के अंदर पिछली सरकार ने 4363 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान किया था जबकि हमने 4661 लाख रुपये का प्रावधान किया है। रुरल डिवलैपमेंट के अंदर जरूर हमारी फिगर पिछली सरकार से कम रही है। इस काम के लिए इन्होंने 2589 लाख

रुपये रखे थे और हमने 1343 लाख रुपये रखे है। इसका कारण यह है कि ड्राउट रिलीफ का 1600 लाख रुपया मिलना था वह इस हैड से निकाल लिया है। इसलिए यह अमाउंट निकल जाने से इस हैड में हमारी कमी हुई है। कोओप्रे ान के लिए इन्होंने 661 लाख रुपये का प्रावधान किया था और हमने 685लाख रुपये का प्रावधान किया है। इरीगे ान एण्ड फलड कंट्रोल के लिए इन्होंने 12341 लाख रुपये रखे थे जबकि हमने 10225 लाख रुपये रखे है। इस बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ष 1987-88 के बजट में एस0 वाई0 एल0 नहर को पूरा करने के लिए 70 करोड रुपये रखे गए थे। इस नहर का काफी काम हो चुका है। इसलिए हमने इस काम के लिए 36 करोड रुपये रखे है क्योंकि 70 करोड रुपये में से 34 करोड के लगभग काम पूरा हो चुका है। क्योंकि जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए रुपये की अब आव यकता नहीं है। पावर के लिए इन्होंने 12200 लाख रुपये रखे थे और हमने 18283 लाख रुपये रखे है। नौन कन्जम्प ान सोर्स आफ पावर के लिए इन्होंने 30 लाख रुपये रखे थे और हमने 40 लाख रुपये रखे है। इण्डस्ट्रीज के लिए इन्होंने 800 लाख रुपये रखे थे और हमने 1050 करोड रुपये रखे है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने 3395 लाख रुपये रखे है जबकि इन्होंने 2362 लाख रुपये रखे थे। साइन्टीफिक कम्युनिटी के लिए इन्होंने 10585 करोड लाख रुपये रखे थे जबकि हमने इनसे डबल पैसे रखे है। (विघ्न) इकोनोमिक सर्विसिज के लिए इन्होंने 9 लाख रुपये रखे थे जबकि हमने 33 लाख रुपये रखे है। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से जनरल

सर्विसिज के लिए इन्होंने 340 लाख रुपये रखे थे और हमने 470 लाख रुपये रखे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, फिगरज बढने के अन्दर भी ये जरूर गलती कर गये हैं। (विघ्न) इन्होंने कहा कि हमने चौथा वेतन आयोग लागू कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसे लागू करके इन्होंने कौन सा तीर मार दिया? ये तो जबानी बात करके गये थे। इन्होंने घोशणा की थी लेकिन लागू हमने किया है। 135 करोड का बर्डन हमने उठाया है।

स्पीकर साहब, हुडडा की बात के उपर ये बहुत बोलते हैं। उस पर नाचते कुदते हैं। इन से पूछना चाहता हूँ कि वह क्या घोटाला है, क्या कोई प्लाटस बेचकर खा गये या किसी कालोनाइजर से पैसे खा गए, उस बात का पता तो लगे कि वह घोटाला क्या है? दो चार मिनट बोलते हैं कि घोटाला हो गया लेकिन आगे कुछ नहीं बताते कि क्या घोटाला हुआ है। चौधरी देवी लाल ने उस घोटाले को बन्द किया है। अगर इस बारे में आप मुझसे बहस करना चाहते हैं तो कर लें (विघ्न एवं भाोर)

चौधरी तैयब हुसैन: इस बहस को तो हरियाणा की जनता सुनेगी और हमें घोटाला बताने की क्या जरूरत है, सारी जनता जानती है।(विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि पिछले साल 70 करोड रुपया एस0 वाई0 एल0 के लिए रखा गया था। अब इस आने वाले साल में 36 करोड रखा है। इतने

पैसे की ही आव यकता एस0 वाई0 एल0 के लिए महसूस की गई है। अब मैं हुडडा की बात बतलाना चाहता हूं। सन् 1982-83 में ऐक्सटरनल डिवैल्पमेंट चार्जिज 167000 रुपये प्रति एकड के हिसाब से रखे गये। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि सन् 1985 में इन्हे घटा कर 131500 रुपये कर दिये गये। ऐसा क्यों किया गया इस बारे में हम में से ज्यादातर जानते होंगे। उसके बाद सन् 1985 में ही फिर रिवाईज किए गए। उन्हे फिर रिवाईज करके 142000 रुपए प्रति एकड कर दिया गया। जब यह मौजूदा सरकार आई तो इसने सोचा कि कालोनाइजर्ज बहुत ज्यादा कम कर रहे है। इसलिए चौधरी देवी लाल की सरकार आते ही हमारे इस विभाग के संबंधित मंत्री ओर अधिकारियों ने सोचा कि ये डिवलपमेंट चार्जिज बहुत कम है। उन्होने इसे बढ़ा कर 241000 रुपये कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी अर्से में हमारे मुख्य मंत्री महोदय जी के कानो में यह बात आई कि चौधरी बंसी लाल तो इसे तीन लाख रुपये कर गए थे, यह कम कैसे हो गया। मुख्य मंत्री जी ने वह फाईल मांगी लेकिन फाईल गायब थी। फाईल को गुम करने में किस की भारारत थी या इसके पीछे किन लोगोका हाथ था मैं इसकी डिटेल् में नहीं जाना चाहता। जब फाईल सामने आई तो पता लगा कि तीन लाख रुपये का तो उन्होने सोचा था। यह प्रपोजल बनाकर मंत्री जी के पास भेजी गई थी कि तीन लाख रुपये प्रति एकड ऐक्सटर्नल चार्जिज बढ़ाए जाएंगे। इस प्रपोजल को न तो पास किया गया और न ही इसे लागू किया गया। इस

प्रपोजल का इस्तेमाल तो केवल कौलोनाईजर को डराने के लिए किया गया।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, आपको अपनी बात कहने में अभी कितना समय और लगेगा ताकि उसी हिसाब से हाऊस का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: हाऊस की कार्यवाही आधा घण्टा और बढ़ाने की कृपा करें।

Mr. Speaker: The sitting of the House is extended by half an hour.

वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, तीन लाख का हौवा दिखाकर इन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया मुझे इस बात का ज्ञान नहीं (विघ्न) वह फाईन मंत्री जी के पास रखी हुई थी और दफतर मे नहीं आई। जो मंत्री इसके इन्चार्ज थे वे इसको दबा कर बैठे रहे। इस अर्से में सरकार बदल गई। तीन लाख रुपए के इस हौवे की आड में क्या घोटाला हुआ? (विघ्न) श्री तैयब हुसैन जी उस समय गृह मंत्री थे। उस समय तीन लाख का जो फैसला हुआ था वह लागू क्यों नहीं हुआ यह श्री तैयब हुसैन जी को देखना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, जब फाईन के बारे में इधर उधर बात चली और इस बारे में सरकार का पक्का

इरादा नजर आया कि सरकार उस फाईल को ढुंढवाने पर तुली हुई है तथा इस के लिए बढे से बडा कदम उठा सकती है। उसके बाद वह फाईल मिल गई और पता लगा कि तीन लाख की तो सिर्फ प्रपोजल ही थी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी सरकार ने 3.72 लाख रुपये ऐक्सटर्नल चार्जिज के किए। (व्यवधान) अखबारो मे तो पता नही क्या क्या निकलता है। यह बात उस समय तक अखबार में नही छपी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: तैयब हुसैन जी आप बैठिए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, जब तक यह फाईल नोटिस मे नही आई तब तक यह पता नही लगा कि बंसी लाल के समय में कोई प्रपोजल बनी थी। फिर भी हमने आते ही इसके बढा दिया। जैसे मैने बताया था कि 1.42 लाख से बढाकर 2.41 लाख कर दिया। तब तक यह खबर अखबार मे नही छपी थी (विघ्न)

Mr. Speaker: Tayyab Sahib, do not give him instructions. let him proceed. (interruption) No interruption, please.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मै एक बात यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सदन के संचालन के लिए और बिजनैस कन्डक्ट करने के लिए रुल्ज बने हुए है। मै आपके माध्यम से कांग्रेसी भाईयो से कहना चाहता हूं कि ये सदन में आपने से पहले जरा उन रुल्ज पर भी नजर डाल लिया करें।

अध्यक्ष महोदय, ये एण्टी करप्शन कमेटी का जिक्र करते हैं कि सैक्रेटरी ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने में कौन सी बड़ी बात हो गई क्योंकि त्याग पत्र तो दिए भी जाते हैं और वापिस भी लिए जाते हैं। इन्हें चाहिए था कि इस बोर्ड के बनाए जाने की भी सराहना करते क्योंकि चौधरी देवी लाल ने नारा दिया था 'बिजली पानी का प्रबन्ध, भ्रष्टाचार बन्द' उस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए चौधरी देवी लाल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जो इस काम में अच्छी भूमिका निभा सकता है। चारों तरफ से पता चला कि एक सत्य देव सिंह हुआ करते थे और निहायत ही ईमानदार आदमी के नाते उनकी भाँहरत थी। उनकी यह भाँहरत आज भी बरकरार है। किसी व्यक्ति का करोड़ों रुपया भी उसे खरीद नहीं सकता। सभी आदमी इस बात को मानते हैं विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी मानते हैं, सभी मानते हैं कि उससे ज्यादा ईमानदार आदमी हो ही नहीं सकता। चौधरी साहब ने उसको घर से बुलाया कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और मैं प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ। आप यह चार्ज सम्भालो। उन्होंने अपनी भाँहत रखी कि मेरी टर्म यह होगी वह होगी, मुझे इतना स्टाफ चाहिए और स्टाफ के अन्दर जितने मैम्बर होंगे उन सब को मैं चुनूँगा ताकि कोई कपट आदमी न आ जाए। उन्होंने यह भी भाँहत रखी कि मुझे कोई सिफारिश नहीं करे। तो जो टर्मज उन्होंने बताई वे सौ परसेंट स्वीकार की गई। इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार और इनके नेता प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। किसी समय काम काज की

प्रक्रीया में कोई बात उनहो अखर गई होगी इसलिए उन्होने इस्तीफा दे दिया होगा। जब उनको कन्वेंस करवाया गया तो वे काम पर आ गए और काम कर रहे है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और इस सरकार के नेता ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ चाहते है कि भ्रष्टाचार प्रदे 1 से खत्म किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मै यह बताना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है, भार्म आती है, कि जिस सरकार की ये लोग हिमायत करते है, जिसका यहां बैठ कर ये प्रतिनिधित्व करते है वह सरकार रक्षा सौदो के अंदर भी पैसे खा जाए। बोफोर्स कांड से तो हमारा सिर भार्म से झुक जाता है। हमारे नौजवान सिपी सरहदो के उपर दु मनो से लडते है और ये कमी न खाते है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज हमारे जवानो की जिन्दगी खतरे में है क्योकि उनको घटिया हथियार दिए गये थे। कमि 1 न तो ये लोग खा गए और जान खतरे में उस जवान की है जो सरहद पर खडा है। आज सरहद पर खडे जवान की जिन्दगी को ही खतरा नही बल्कि दे 1 की आजादी और अखंडता भी खतरे में पड गई है। (गोर) अध्यक्ष महोदय, फेयर फैंक्स का मामला आपने सुना होगा ओर अखबारो में भी पढा होगा कि क्या कुछ गडबड हुइ। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति, जो भासक और उनके दोस्त हजारो करोड रुपया इस दे 1 का लूट कर स्विस बैंको में जाकर जमा करवाएं वे कप 1 न की बात करते है, वे हम पर इल्जाम लगाते है। (गोर) अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगी कि यहां भजन लाल की सरकार थी और बाद में बंसी लाल की सरकार आई। मै केन्द्र की बात नही

करता यहां की बात करता हू। आपको पता है कि बदलियों के उपर फिस लगी हुई है। पांच हजार इसके, दस हजार इसके और दो हजार इसके। अध्यक्ष महोदय, नौकरियों में एच० सी० एस० के लिए दो लाख रुपए, तहसीलदार के लिए एक लाख रुपया और नायब तहसीलदार के लिए 50 हजार रुपए लिए जाते थे। हरियाणा का एक एक व्यक्ति इस बात का गवाह है कि यहां नौकरियां पैसा देने से मिलती थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बेकाइदगी करते हैं आप जरा इनको लगात लगाइयें। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह चैलेनज करता हू कि चौधरी देवी लाल की सरकार बनने के बाद यह साबित कर दें कि एक भी पैसा किसी ने नौकरी लगाने का या बदली करवाने का लिया हो। क्या उपलब्धि नहीं मानते हैं? हम भ्रष्टाचार को खत्म करने जा रहे हैं। मैं यह तो दावे के साथ नहीं कहता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा लेकिन चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में हम बहुत हद तक इसको बन्द कर देंगे।

यह कर्जे माफी की बात की बाबत कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब यह तो हो नहीं सकता कि हम बलबीर पाल भाह का लाखों रुपये का कर्जा माफ कर दें। चौधरी देवी लाल जी ने यह घोशणा की थी कि गरीब आदमी का या वीकर सैक उन का कर्जा माफ किया जायेगा। जो कर्जे के बोझ से दब चुका है और सांस भी नहीं ले पा रहा है, उसका कर्जा माफ किया जायेगा। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Please be silent. Let him proceed.
(Interruption)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, तैयब हुसैन यह कहते हैं कि कर्जा तो माफ हुआ ही नहीं है। यह कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। यह कहते हैं कि बजट में प्रोवीजन ही नहीं है। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांटस थी, उसके अन्दर 10 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रोवीजन था।

Chaudhri Tayyab Hussain: Sir, he should have replied to this point. We are not here to listen irrelevant things. (Interruption)

Mr. Speaker: Please have your seat. You have also talked about it. Now let him clarify.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ यह कहता हूँ कि 10 करोड़ रुपया कर्ज माफी के अगेन्स्ट हमने बैंकस को दिया था।

चौधरी तैयब हुसैन: आप जरा किताब पढिये। उसमें कही पर कर्ज माफी वाली बात नहीं है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अगर कर्ज का नाम नहीं आया तो क्या हुआ, मैं आपको अब जो बता रहा हूँ।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल उठाया था कि जहां पर सूखा पडा हुआ है, वहां पर सरकार क्या राहत देने जा रही है, इसका वह जरा जवाब दे दें।

Mr. Speaker: Arya Sahib, please have your seat. Are you Finance Minister or he is the Finance Minister? Let him proceed further. You have been given enough time to speak.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आप जरा ये फिगरज भी सुन लीजिए। हमने जो किसान है उनके 23मार्च, 1986 तक का जितना बकाया था, चाहे वह लोंग टर्म का था या भाार्ट टर्म का था, 10 हजार रुपये तक का सारा कर्जा माफ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, 544716 लोगो को इससे फायदा हुआ और 32717 करोड रुपये का बोझ सरकार के ऊपर पडा है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज, हरिजन, भूमिहीन या मजदूर है उनकी भी हमने कर्जा माफी की है। 108952 लोगो को इससे फायदा हुआ और 1 करोड 52 लाख 73 हजार रुपये का बोझ सरकार के ऊपर पडा है। ग्रामीण दस्तकारो का भी हमने कर्जा माफ किया है इस में 4153 लोगो के कर्जे माफ किये गये है इससे 1 करोड 11 लाख 86 हजार रुपये का बोझ पडा है। छोटै दुकानदार के भी हमने कर्जे माफ किये है। हमने 68260 ऐसे लोगो के कर्जे माफ किये है जिससे 1 करोड 82 लाख 42 हजार रुपये का बोझ पडा है। एसे टोटल 46 करोड 6 लाख 50 हजार रुपये हमने सहकारी बैंको को दिया है। जब इनकी सरकार गई और हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला तो सारी सहकारी कार्य प्रणाली ठप्प पडी हुई थीं। उस समय किसी गरीब को लोन नहीं दिया जा रहा था। पिछली सरकार ने कर्जे की प्रक्रिया बिल्कुल बन्द कर दी थी। इसके फलस्वरुप न तो कर्जे की वसूली हो रही थी और न ही किसान

को दुबारा कर्जा दिया जा रहा था। स्पीकर साहब, कर्जा माफी की योजना में जो पुराने डिफाल्टर्स हैं, जो क्रोनिक डिफाल्टर्स हैं उनको यह माफी की रियायत नहीं दी जाएगी। हमने कर्जा प्रणाली को फिर से भुरु किया है और अब किसान का कज्र दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए इस रबी में जब कि सूखे की स्थिति थी लगभग नब्बे करोड़ की राशि। बतौर कर्जे के दी गई है जबकि 1987 में 88 करोड़ दी गई थी और यह कहते हैं कि लोनिंग की प्रक्रिया बिल्कल बंद है। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि कर्जा माफी के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में दस करोड़ रुपये रखे हैं लेकिन मेन बजट में नहीं रखे। वह इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो कर्जे माफ कर रहे हैं वह बैंक अपने रिर्सोसिज से कर रहे हैं। इस वक्त हरको बैंक की पूंजी 250 करोड़ रुपए की है और अध्यक्ष महोदय, इस कर्जा माफी से बैंको को जो घाटा पड़ेगा उसको सरकार पूरा करेगी। यह गारंटी सरकार ने दी है इसलिए बजट में प्रावीजन नहीं किया है।

शिक्षा मंत्री (श्री खुर शिद अहमद): सारा काम अक्ल से होता है।

चौधरी तैयब हुसैन: हाई कोर्ट ने ऐजूके इन मिनिस्टर ने जो ऐफीडेविट दिया है वह भी तो अक्ल से ही दिया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये लोग कमिश्नल बैंकस की बड़ी बातें करते हैं कि कमिश्नल बैंक का कर्जा माफ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सहकारी बैंको का 59.68 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया है, निगमों के 8.36 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं और व्यवसायिक बैंको के कर्जे माफ नहीं किए। अध्यक्ष महोदय, 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी तो उन्होंने व्यावसायिक बैंको से कहा कि वीकर सैव इन को कर्जा दिया जाए। सारे बैंकस इंकलूडिंग रिजर्व बैंक प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप वीकर सैव इन को कर्जा दिलाएंगे तो कर्जा वसूल नहीं होगा और बैंक बैठ जाएंगे। उस समय एक कारपोरेट इन बनाई गई जिसका नाम था डिपोजिट एंड क्रेडिट इंशोरेंस स्कीम गारंटी कारपोरेट इन। यह कारपोरेट इन इसलिए बनाई गई कि अगर कोई लोनी कमजोर हो, गरीब हो, और वह कर्जा न दे पाए तो 85 प्रतिशत कर्जा बैंको को वह कारपोरेट इन देगी और पन्द्रह प्रतिशत बैंक खुद देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक की रकम गारंटी हो गई। यह कारपोरेट इन वैसे ही नहीं है। बैंक इस कारपोरेट इन को प्रीमियम देते हैं और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो क्लेम कर लेते हैं। वह क्लेम हमें कारपोरेट इन देती है। इस तरह से इन बैंको की रकम की सुरक्षा के लिए यह कारपोरेट इन बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, हमने कमिश्नल बैंको से यह कहा कि जो कई सालों से 162 करोड़ रुपये के कर्जे पड़े हुए हैं, आप इनको सेटल नहीं कर पा

रहे हैं। आपकी रकम ब्लाक हुई है और लोनीज भी डिफाल्टर्ज बने बैठे हैं। उनका काम बन्द पडा है और आगे उनको कर्जे नहीं मिल रहे हैं। आप मेहरबानी करे और कारपोरे इन से अपना क्लेम मांगे और उनका कर्जा माफ कर दें। (गोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि जितने बैंक वे कारपोरे इन को प्रीमियम देते हैं और कारपोरे इन का यह फर्ज है कि अगर कोई लोनी बैंक के पैसे नहीं लौटाता तो कारपोरे इन उनको क्लेम दे। हमने कमि रियल बैंको की मीटिंग बुलाई और सारी योजनाएं उनके सामने रखी कि तुम्हारी लोनिंग भुरु हो जाएगी और जो रकम ब्लाक पडी है वह आपके पास वापिस आ जाएगी। जो लोनिज है उनको राहत की सांस भी मिलेगा और वह उस रािा से अपना काम धंधा चला सकेंगे। साथ में हमने यह कहा कि आपकी मदद के लिए हर जिला लैवल पर हमने एक कमेटी बना दी है। ए० डी० सी० उसका चेयरमैन होगा और उसमें बी० डी० होगा। इनके अलावा उस क्षेत्र में जो बैंक काम करते हैं उनको दो प्रतिनिधी भी होंगे। आप एक एक की स्क्रीनिंग करके जो चीफ कायदे के मूताबिक ठीक बैठती हो उसको आप कर दें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इन कांग्रेस के भाईयो की क्या बात बतलाऊ? चाहिए तो यह था कि ये लोग हमारा साथ देते, हमारी मदद करते और अपनी केन्द्र सरकार को कहते या वित्त मंत्री से कहते कि यह तो बैंक के भले की बात है। प्रदेा व देा के भले की बात है लेकिन इस के साथ ही मैं आपको एक रहस्य की बात

बतलाता हूँ कि प्रधान मंत्री तक को यह खतरा हो गया कि अगर यह कर्जा माफी वाली बात में हरियाणा सरकार सफल हो गई तो इसका सारा क्रेडिट चौधरी देवी लाल जी को जाएगा, हरियाणा सरकार को जाएगा और फिर यह बात दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों मैं चौधरी देवी लाल जी के साथ दूसरे प्रदेशों में गया था। वहाँ हजारों लाखों किसान चौधरी साहब से मिले और कहने लगे कि साहब हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी इस बारे में कुछ कहे कि हमारे कर्जे भी माफ कर के हमें भी कुछ राहत दें। इस बात से डरते हुए इनके बड़े बड़े नेताओं ने कमिश्नरियल बैंक को यह हिदायत दी कि इनकी बात मानना नहीं हालांकि ये बातें बिल्कुल सही हैं और कायदे के अंदर ही आती हैं। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप सिंह जी आप बैठे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, यह गलतबयानी कह रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह गलतबयानी नहीं है। मैं चैलेन्ज करता हूँ कि अगर ये एक भाब्द भी गलत साबित कर दें तो मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी आप बैठिए। आप किस प्रोवीजन के तहत बोल रहे हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता हूँ आप इन से पूछिये कि कौन सी बात मैं गलत कही है। एक भी गलत बात बताएं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार का क्या क्रेडिट है? इसमें इनका क्या योगदान है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के क्रेडिट की बात करते हैं। आज बैंको में जो धन है, केन्द्र सरकार के खजाने में जो धन है, प्रदेश सरकार के खजाने में जो धन है, वह सारा धन जनता का ही है अगर बैंक या कोई दूसरा अदायरा या सरकार जनता के पैसे का उपयोग न करे और लापरवाही करे तो उसको रास्ता दिखाना, रास्ता सुझाना सरकार का भी काम हो जाता है और जनता का भी काम हो जाता है। हमने उनको सुझाया कि यह जनता का पैसा है अगर यह वसूली होगी तो और लोगो को कर्जा दिया जा सकेगा। लोगो के काम हो जाएंगे और लोगो को राहत मिलेगी। यह कायदे और कानून की बात है। उन्होंने मेरी बात को माना और मेरी बात से कंविंसहुए लेकिन उन्होंने मुझे कांफिडेंस मंले कर के एक बात बताई और कहाकि अपनी बात सही है लेकिन हम मजबूर हैं। यह बात उन्होंने मुझ से

कही। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे कांग्रेसी भाई जो नुक्ताचीनी की बात करते हैं यह खामखाह करते हैं इसके सिवाय इनके पास और कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी तैयब हुसैन और महेन्द्र प्रताप सिंह राबी व्यास के पानी की बात करते हैं और उसकी बात करके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। (गोर) यह भी कहते हैं कि हम प्रदेश के हित के लिए कोई भी बात कहने को तैयार हैं। इन्होंने भाह कमिशन के बारे में भी बात कही, उसके फैसले के बारे में भी बात कही और यह कहा कि भाह कमिशन का फैसला इम्पलीमेंट नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, भाह कमिशन का फैसला किने इम्पलीमेंट करना था? उसको केन्द्रीय सरकार ने इम्पलीमेंट करना था केन्द्रीय सरकार ने इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया? तैयब साहब की सरकार ने उसको इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया, इनके किसने हाथ पकड़े थे और इनको किसने रोका था? मुझे यह बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसको इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया? इसके बावजूद भी तैयब साहब सारा दोष पंजाब के लोगो पर डाले और कहे कि पंजाब के लोग मानते नहीं। मैं कहता हूँ कि पंजाब के लोग क्यों मानेंगे? पंजाब के लोग तो यह चाहेंगे कि चण्डीगढ़ भी उनके पास रहे, फजिलका अबोहर भी उनके पास रहे। राबी व्यास का पानी भी उनके पास रहे? जो वे इन्साफी का िकार हो उसकी मदद करनी चाहिए लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पडी कि भाह कमिशन के फैसले को

इम्पलीमेंट करें। मैं इन कांग्रेसी भाईयो से यह जानना चाहता हूँ कि 1972 में जो प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिया था उसका क्या बना?

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सैंस हो तो हाउस का टाईम 15 मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1988-89 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बनारसी दास गुप्ता: उस अवार्ड पर पंजाब के अन्दर दिवाली मनाई गई थी ओर हरियाणा के अंदर ऐजिटेंशन हुए थे। उस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल हुआ करते थे वे दो अढ़ाई लाख लोगों को लेकर दिल्ली गए थे। लोगों की जो आशाएं चण्डीगढ़ के लिए बनी हुई थी वे खत्म हो गई थी। जब चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया गया तो यहां पर ऐजिटेंशन हो गए। फिर हमने लोगों को समझाया कि चण्डीगढ़ सफेद हाथी है इसको लेकर क्या करेंगे? अबोहर-फजिल्का का एरिया हमें मिलेगा और साथ में 110 के करीब गांव मिलेंगे वहां पर सारे मुल्क से सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है। जो फजिल्का अबोहर का इलाका है

वह बहुत उपजाऊ है। तो लोग बाद में हमारी बात से सहमत हो गए थे। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 तक जीवित रही। यह मैं मानता हूँ कि वे बड़ी मजबूत नेता थीं। वे भी इस समझौते को लागू नहीं कर पाई थीं। रावी ब्यास के पानी के बारे में भी पंजाब वाले कहते थे कि इसमें हरियाणा का कोई हिस्सा नहीं है। यह झगडा भी हमारा पंजाब के साथ चलता रहा। 1976 में मैं हरियाणा का ओर ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री थे। 1976 में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोनों मुख्य मंत्रियों को बुला कर इस पानी का बंटवारा कर दिया। यह पानी था तो 72 लाख एकड फीट लेकिन 2 लाख एकड फीट पानी दिल्ली को ड्रिंकिंग वाटर के लिए दे दिया और 35-35 लाख फीट पानी पंजाब और हरियाणा को दे दिया। इस बंटवारे के बाद हमने कहा कि यह तो हमारे साथ ज्यादाती है। प्रधान मंत्री कहने लगी कि ज्यादाती कैसे है? पानी तो दोनों स्टेट्स को आधा आधा दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं क्लियर कर देता हूँ कि टोटल पानी था 15.85 मिलियन एकड फीट। इस पानी में से आठ मिलियन एकड फीट से ज्यादा पानी को राजस्थान के सूखे इलाके के लिए दे दिया गया हमने कहा कि हमारे पानी को राजस्थान को देकर एक गलत सिद्धांत काम कर दिया है। साथ ही हमने यह भी कहा कि पंजाब में तो वाटर अलाउंस ज्यादा है, हमारे यहां पर कम है, हमें पंजाब के मुकाबले पानी की ज्यादा जरूरत है। इस पर इंदिरा जी ने उस समझौते में एक लाईन और लिख दी कि जब कभी भी दरियाओ में पानी बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को दिया

जाएगा। पंजाब को 35 मिलियन एकड फीट से ज्यादा एक बून्द भी पानी नहीं दी जाएगी। मार्च, 1976में भारत सरकार के गजट में यह छपा है। लेकिन यह फैसला भी लागू नहीं हुआ। यह नहर बननी थी। एक करोड रुपया हमने मुख्यमंत्री (पंजाब) को नहर बनाने के लिए दे दिया और हमने कहा कि चलो आप नहर का प्रीलिमनरी काम भुरु करवा दो। लेकिन काम भुरु नहीं हुआ। बाद में सरकारें बदल गईं तो दो अढाई साल के लिए बीच में जनता पार्टी की सरकार भी सत्ता में आई। सरकारें आती रही ओर बदलती रही। 1981 के अंदर फिर प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तीनो मुख्य मंत्रीयो के बैठक बुला कर इस पानी का फिर बंटवारा किया। उसमें हरियाणा को घाटा तो रहा लेकिन हरियाणा के लोगो ने और नेताओ ने सोचा चलो कोई बात नहीं। दो साल के अंदर अंदर नहर की खुदाई तो हो जाएगी और यह नहर तैयार हो जाएगी। हरियाणा के लोगो ने यही सोचा चलो कम पानी सही, पानी तो मिला। लोगो ने यही सोचा कि जल्दी से पानी इस नहर के जरिये मिलना भुरु हो जाएगा। लेकिन मुझे दुख होता है कि श्री राजीव गांधी जी ने गददी पर बैठते ही हरियाणा के हितो पर कुठाराघात किया। राजीव लोंगोवाल समझौते में जो धारा 7 और 9 जोडी गई थी वह तो हरियाणा के हितो के बिल्कुल ही खिलाफ थी। दूसरे इंदिरा जी ने जो फैसला किया था उसको फाड कर एक तरफ डाल दिया। उन्होने इस समझौते के तहत ऐसी टर्म्ज एण्ड रैफरेंसिज डाल दी कि अबोहर फाजिलका भी हरियाणा से जाता रहा ओर चण्डीगढ भी हरियाणा से छिन गया। उसके बाद

मैथ्यु आयोग और दूसरे कई आयोग बने उनके नतीजे क्या निकले वह सब के सामने है। लेकिन हरियाणा को न अबोहर-फजिलका मिला, न चण्डीगढ मिला और न ही आज तक पानी मिल पाया है। उल्टा बढा हुआ पानी भी पंजाब को मिल गया। बडी बेइंसाफी की बात हरियाणा के लिए हो रही थी। हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने या किसी और ने कोई आवाज नहीं उठाई। सैंटर में चौधरी बंसी लाल राजीव गांधी जी की बगल में बैठते थे और राव वीरेन्द्र सिंह भी केन्द्र में मंत्री थे लेकिन उन्होंने हरियाणा के हितो के लिए कोई काम नहीं किया। उनको चाहिए था कि वे प्रधान मंत्री के पास जाते और पंधान मंत्री जी को कहते कि अकालियों को खुा करने के लिए हरियाणा के हितो पर छुरी क्यों चला रहे हो लेकिन इस तरु किसी ने ध्यान नहीं दिया। मै आपके यह भी बताना चाहूंगा कि उस फैसले की पुश्टी करने के लिए कांग्रेस पार्टी तथा विधायक दल की कार्यकारिणी ने अपनी अपनी बैठको में इस समझौते के समर्थन में प्रस्ताव पास किये। महेन्द्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि हमने राष्ट्र हित में इसका समर्थन किया है। अगर ये देा भक्ति की बात करते है तो ये मेरे से ज्यादा देा भक्त नहीं है।(विधन्) 19:00 बजे

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। मै आपकी रुलिंग चाहूंगा कि अब आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे है तो ये अपोजीान के मैम्बर बिना आपकी इजाजत के कैसे बोल रहे है? उन्हे बोलने की इजाजत न

दी जाये। दूसरे जो वे बाले उसे रिकार्ड न करने दिया जाये ताकि कल सुबह प्रैस में न आ जाये।

श्री अध्यक्ष: जो, मैम्बर बिना इजाजत के बोले वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर यह समझौता राष्ट्र हित में होता तो क्या इस समझौते के बाद पंजाब में हत्यायें बन्द हो गई? इस समझौते को हुए कितने दिन हो गये हैं लेकिन हत्यायें बंद नहीं हुई।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मैं कलेरीफिके 11 के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं कि चुनाव के बाद इस सरकार ने जो गवर्नर ऐड्रैस पढा उसमें सरकार ने यह माना है कि पानी हमें ठीक मिला है। पहली सरकार ने सही पैरवी की और सही फैसला हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: श्री तैयब हुसैन जी ने जो कहा है, वह ठीक है। हमने यह कहा था कि इंदिरा ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है उसको हम मानते हैं लेकिन हमने यह भी कहा था कि पानी कम दिया गया है, हमें ज्यादा पानी की जरूरत थी। हमने यह नहीं माना कि पूरा पानी दिया गया है हमने कहा कि हम ज्यादा पानी की आवश्यकता हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नर ऐड्रैस में जो बात लिखी थी वह ठीक थी।

इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला हरियाणा के हित में है। पहले पंजाब सरकार तो हमारा क्लेम ही नहीं मानती थी। कम से कम इराडी ट्रिब्यूनल ने हमारा हक तो एस्टेब्लिश कर दिया कि हरियाणा का राइट है। जहां तक पानी के क्वॉंटम का सवाल है उके बारे में हमने पहले ही कहा है कि पानी कम मिला है। इराडी ट्रिब्यूनल में मामला अभी चल रहा है। हमने फिर से अपील की है कि पानी का क्वॉंटम बढ़ाया जाये। मैं अभी समझौते की बात कर रहा था। अगर समझौता राष्ट्र के हित में हो जाता तो पंजाब में कत्लेआम बन्द हो जाता। पंजाब में यदि भांती हो जाती तो सारे देश में भांती हो जाती तो भायद हम इस घाटे को बर्दाश्त भी कर लेते। वह समझौता तो अपनी मौत आप मर गया। जब हरियाणा के साथ अन्याय हुआ तो एक माई का लाल नहीं बोला कि हरियाणा के साथ ज्यादाती हुई है, उस समय चौधरी देवी लाल जी ने खड़े हो कर कहा कि जब तक मेरे भारीर में प्राण है मैं हरियाणा के साथ बे-इंसाफी नहीं होने दूंगा। डाक्टर मंगल सैन जी बैठे हुए हैं, इन्होंने चौधरी साहब की आवज में आवाज मिला कर कहा कि मैं आपके साथ हूं। उस समय चौधरी देवी लाल जी ने इस्तीफा दिया, डाक्टर मंगल सैन ने दिया और जो दूसरे साथी श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हीरा नन्द आर्य, श्री हुक्म सिंह, श्री नर सिंह ढांडा, श्री भागी राम, श्री सम्पत सिंह, श्री लछमन सिंह कम्बोज, श्री मनफूल सिंह और डिप्टी स्पीकर श्री कुलबीर सिंह ने भी इस्तीफे दिये। सब ने गददी को ठोकर मार दी और अढाई साल तक संघर्ष किया। कांग्रेसी लोगो ने समझौते का समर्थन किया। आज कहते हैं कि

हम पानी के लिए लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाइयों का स्वागत करता हूँ, जो इन्होंने कहा है कि हम इस बात में आपका साथ देंगे। देर आए दुरुस्त आये। अध्यक्ष महोदय, जहाँ हमने सूखा पीड़ितों के लिए चार सौ करोड़ रुपया सरकार से मांगा था उसमें भी ये हमारी मदद करते। दूसरी किस्त मांगी है उसमें मदद करें। ओलावृष्टी के लिए 57 लाख मांगा है उसमें साथ दें और पानी के मामले में साथ दे तो बड़ी अच्छी बात है। इस प्रदेश के सांझे हित की जो बातें हैं यदि उनमें ये हमारा साथ दे तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कर्मचारियों की बात की और पेंशनरों के बारे में भी यह कहा कि उन्हें पेंशन 1 जनवरी, 1986 से दी जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के अतिरिक्त हमारे पक्ष के लोगों में से हीरा नन्द आर्य जी ने भी इस बारे में मुद्दा उठाया और डा. मंगल सेन जीने तो पहले ही यह आवाज उठाई थी कि फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट के तहत पर रिवाईज्ड स्केल जब से लागू हुए हैं तभी से यानी 1-1-1986 से ही मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा था अगर यह सरकार इसी मांग को मान ले तो हम यह मान लेंगे कि सरकार की उपलब्धियाँ बहुत ज्यादा हैं। इनकी इस बात को मैंने उसी समय नोट कर लिया था और चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी स्वयं मान लेंगे कि इस सरकार की उपलब्धियाँ वास्तव में बहुत ज्यादा हैं और इसमें कोई भाक की बात नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारे मैम्बर साहेबान ने जो जो मांगे रखी है, अब मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा श्री हीरा नन्द आर्य ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के लिए एक अलग से निदेशालय बनाया जाए। हम इनकी मांग पर विचार करेंगे। श्री आर्य इस बात को लिख कर हमें भिजवा दें। जहां तक स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है, वर्ष 1988-89 के लिए हमने यह प्रोविजन नहीं रखा है क्योंकि अभी विकास के काफी काम हमारे सामने हैं और आर्थिक स्थिति इतनी अधिक सरल और आसान नहीं हुई है। श्री वेद सिंह मलिक ने गन्नौर में नया कालेज खोलने के लिए कहा है, हम इस बारे में विचार करेंगे। श्री हीरा नन्द आर्य एम एल ए ने सुखाग्रस्त क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ करने के लिए कहा है। यह बात हमारे अंडर कंसिडरेशन में है। इस समय यह मामला फाईनैस विभाग के पास है और थोड़े ही दिनों में इस बारे में घोशणा कर दी जाएगी। (विघ्न)

मास्टर शिव प्रसाद, एम0 एल0 ए0 ने गांव मलिकपुर से गांव डडीना के बीच पुल बनाने की मांग की है। यह गांव पहले ही पुल से कनेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने गांव दुरलाना को सड़क से जोड़ने की भी मांग की है। यह गांव पहले ही सड़क से जुड़ चुका है। अम्बाला छावनी के लिए दोहरी सड़क धनाभाव के कारण अभी नहीं बनाई जा सकती। श्री बूटा सिंह, एम0 एल0 ए0 ने घग्गर नदी पर पुल बनाने की मांग की है। पैसा उपलब्ध हो जाने पर यह पुल बनाया जाएगा। श्री सरदूल सिंह, एम0 एल0 ए0

ने सफ़ीदों में 5 कमरों के स्कूल की मरम्मत की मांग की है। इस मरम्मत पर 1.52 लाख रुपये का खर्चा होगा। पैसा उपलब्ध होने पर यह काम कर दिया जाएगा। भवन सुरक्षित है। इन्होंने ओटू ब्रिज के मरम्मत की बात भी की। ब्रिज की मरम्मत का काम चालू है। ओटू के निकट सड़क का काम भी चालू है और पर्याप्त धन मिलने पर पूरा कर दिया जाएगा। सिरसा से हनुमानगढ़ तक सड़क का कार्य सड़क पर पड़े मलबे को उठाने से भुरु कर दिया गया है और अतिरिक्त राशि मिलने पर इसको पूरा कर दिया जाएगा। श्री जय नारायण खुण्डिया, एम0 एल0 ए0 ने जिला रोहतक की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए कहा है। इस काम को हम प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा वर्कचार्जड कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात कही गई है। जिन वर्कचार्जड कर्मचारियों की चार-पांच या साढ़े चार वर्ष की सेवा हो चुकी है उन्हें वित्तीय स्थिति सुधारने पर रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ये सी जितनी भी हमारे मेंबर साहेबान की मांगे हैं हमने सब नोट की हुई है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आवासन देता हूँ कि उनकी प्रत्येक मांग पर बड़ी हमदर्दी के साथ गौर किया जाएगा और उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इन भावों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों को प्रार्थना करूंगा और आशा करता हूँ कि इस भावदान बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब सदन कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

19:10 बजे

(तत्प चात् वीरवार, दिनांक 29-3-1988 को प्रातः 9:30 बजे तक के लिए *स्थागित हुआ।)